

कावाज की बाव

शैलेश मटियानी

कागज की नाव

(शंलेश मटियानी के ताजा लेखो का सग्रह)

	लेखकाधीन
प्रकाशक	
अनुभूति प्रकाशन	
५३, करनपुर, प्रयाग स्टेशन	
इलाहाबाद-२११ ००२	
<input type="checkbox"/>	
सस्करण	१६६१
<input type="checkbox"/>	
मूल्य	४५ ०० रुपये
<input type="checkbox"/>	
आवरण	
शिवगोविन्द पाण्डेय	
<input type="checkbox"/>	
मुद्रक	
पियरलेस प्रिंटस	
१, बाई का बाग	
इलाहाबाद-२११००३	

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक मटियानी जी के ताजा लेखों का ताजा संग्रह है।

मटियानी जी की भाषा उनका तेवर उनके तक दमदार ही नहीं हात उनमें ऐसी प्रहार क्षमता होती है कि लक्ष्य तिलमिला उठता है। वह नीक से हटकर चलते हैं घालते हैं, लिखते हैं।

इन लेखों में मटियानी जी की संवेदना आदमी के साथ ही भारतीय संस्कृति से जुड़कर चलती है। वे किसी को सवाल से ऊपर नहीं मानते। जब राम जोर रही हैं सवाल से ऊपर नहीं है तो संविधान और उसके निर्माता सचालक सभी पर वह अपने को और अपन व्याज से हर बुद्धिजीवी को उँगली उठान का अधिकारी मानते हैं।

साम्प्रदायिकता, स्त्री हत्या (मर्ता प्रथा) राष्ट्रियता, राष्ट्रगीत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक ये ऐसे मामले हैं जिन पर अक्सर ही अखबारों में तू-तू मैं-मैं होती है। पर सब टाय टाय फिक्स होकर रह जाता है। आवश्यकता है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचारने की। पर स्वायत्तता के बाद सब कुछ ठहर जाता है। जो किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक है।

मटियानी जी के इन विचारों को पाठकों तक संप्रसारित करके हम अपना प्रकाशकीय धर्म निभा रहे हैं और चाहते हैं उस पर बहस का आगे बढ़ाया जाए। जो सुविचारित सत्य निकले उसे स्वीकारा जाय और जो जाँचने परखने पर अप्रासंगिक हो उसे छोड़ दिया जाए।

अनुक्रम

संघकीय प्रामाण्य	१
कागज की भाव	१७
किसका विमग खतरा है ?	२३
हिंदू और मुसलमान	३०
मजहब बड़ा वि मुल्क ?	३५
सवाल का हवा	४१
झूठा की नैया	४८
लाकतल के दरवार	५३
हमारे माननीय विधायक	५६
कसा मवाद किससे सवाद	६४
स्त्री हत्या का उत्सव	६८
कौन है भारत भाग्य विधाता	७७
तमम दूर करन की समक	८७
राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री	१०५
क्या हम जानत है	११६
आदमी और कानून	१२७
कानून का राज्य	१३३
सविधान हमारे जीवन की किताब	१३८
कठफाड़वा कहीं रहता है ?	१५६

नदकिशोर मित्तल
को सादर

प्राक्कथन

एक तरह से देखें, तो विचार और अभिव्यक्ति की अद्भुत स्वतन्त्रता है। दूसरी तरह से देखें, तो सोच-विचार और संवेदन के सवाल ही इतने फालतू हो चुके दिखाई पड़ेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हान, या नहीं होने की बहस ही हाशिये पर की वस्तु लगे। लिखना, दर-असल, लोगों को आवाज देना है। जिन तक—या जिस रूप में—बाल कर बात पहुँचाना मुश्किल, लिखकर साक्षात् खोजना है। लिखना पढ़ने वालों से सम्बन्ध बनाना है। लेकिन हालात अगर यहाँ तक पहुँच जायें कि सम्बन्ध बना सकने की गुंजाइश ही वही दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे, तब कोई क्या करे ? -

जबकि आज की हकीकत यही है। लेखक कभी भी पूरी निष्ठा और सरोकार के साथ लिख ही नहीं सकता, अगर कि उसे इतना विश्वास नहीं कि लिखा व्यर्थ नहीं जाना है। लिखने का कोई अर्थ नहीं, अगर उसे पडा नहीं जाना और पढे जाने का कोई मतलब नहीं, जब तक कि जिस उद्देश्य से लिखा, उसी उद्देश्य से पडा नहीं जाय। लिखने और पढ़ने वाले के बीच का साया ही लिखे गये को सार्थक करना है

और आज यह साक्षात् ही अन्तर्धान मानूम पड़ता है। लिखने और पढ़ने वालों के बीच एक अभेद्य अदृश्य दीवार-सी खड़ी है और पारदर्शिता वही नहीं। न लिखने वाला यह देख पाने की म्यिति में है कि उसने लिखे को पढ़ने वाले के चेहरे, उसकी संवेदना या आँखा में कोई प्रतिबिम्ब वही झिलमिलाई, या नहीं—और न पढ़ने वाले को यह अनुभव कर पाने का कोई अवसर कि लेखन तब उसकी शक्ति पहुँच रही है।

सब कुछ सबको नहीं। साँसत सिर्फ उहँ है, जा आगने-सामने होना चाहते हैं। जिस उद्देश्य ने लिखा, उसी उद्देश्य से पढ़ने वाला भी तलाश ही किसी लखन की सबसे गहरी तलाश हुआ परती है। जिनकी किसी किताबें लाखों की संख्या में बिक रही हों, यों इस इतमीनात में बिलगुल रह सकते हैं कि उनका लिखा स्मरण नहीं जा रहा, लेकिन जिन्हें पता हो कि सिवा सरकारी और छिंटपुट वाचनालयों खरीद के किताब को अब वही कोई रास्ता नहीं कि पढ़ने वाला तर पहुँच सके, उनका सब कुछ सामान्य नहीं। आज यह सब कुछ हिन्दी के उन सप्ताह लेखकों पर छाया है, जो रचनात्मक या वैचारिक लेखन की दुनिया के याशिदे हैं। जिन्हें इतना भी विश्वास बंधना बठिन है कि करोड़ों-करोड़ बड़े जा रहे हिन्दी पाठक-वर्ग के बीच उनकी किसी किताब की साल-भर में कम-से-कम सौ-पचास प्रतियाँ तो निकल ही जाएगी। प्रकाशक अगर लम्बी बाँहों वाला नहीं, तो साल-भर में दस-बीस प्रतियाँ का भी ठिकाना मुश्किल है।

अस्सी करोड़ की आबादी वाले महादेश में अगर किसी लेखक का साल-भर में पचास-पचास किताबों के भी पाठकों तक पहुँचने का विश्वास बंधना बठिन हो, तो कोरे कागज के सामने उपस्थित हान में शब्द और भाषा—या कि रचनाकर्म—की कितनी प्रासंगिकता कोई लेखक अनुभव कर सकता है, इसका अनुमान, शायद, कठिन नहीं होगा।

आज की सचार्ई यही है।

इस देश की व्यवस्था ने, जहाँ तक इससे बन पड़ा है, लेखक और समाज के बीच के सेतु या तो ध्वस्त कर दिये हैं और या उनकी ऐसी

नाकाबंदी कर दी है कि आवाज ही कठिन है। लेखक अपने लिखित के द्वारा समाज तक पहुँचना, और उसे यह बताना, चाहता है कि लिखत मही है, या नहीं। लोगो की भावनाओ, उनके विचारो और जीवन-सघर्षों की जो तस्वीर उसने प्रस्तुत की, वह सही है, या कि गलत? व्यवस्था की अमानवीयता और शोषणवृत्ति की जो पहचान वह दे रहा है, उसमें कुछ सार है कि नहीं। और कि अगर वह समाज की जड़ता के सवाल उठा रहा है, तो इनमें कुछ दम है कि नहीं?

लिखना, दरअसल, बताने के सिवा कुछ नहीं। मनुष्य के सघर्ष और सौंदर्य के बारे में अधिकतम प्रभावी भाषा में अपना अनुभव बताने की ललक ही किसी व्यक्ति को लेखक बनाती है। समाज में अपनी साख या जगह ढूँढता फिरता है लेखक, तो इसीलिए कि अपने बताये की प्रासंगिकता को समझ सके। जब तक साहित्य के समाज तक पहुँचने का सिलसिला बरकरार हो, तब तक लेखक के पास यह मान लेने का आधार बिल्कुल है कि उसका लिखा व्यय नहीं जा रहा। किताब का पढ़ा जाना ही उसकी पहली सीढ़ी है। यही किताब की सामाजिक स्वीकृति है। यह प्रमाण है कि लेखक के समाज और समाज के लेखक के साथ के रिश्ते ठीक-ठाक चल रहे हैं। यानी दोनों ओर मुशाल है और दोनों छोर आपस में जुड़े हैं। लेकिन जब किताब को ही रास्ता बंद दिखाई दे, तो इतना समझ लेने में कोई देर नहीं होनी चाहिये कि मामला गड़बड़ है!

किताब को रास्ता नहीं मिलने का मतलब होता है, लेखक को समाज और समाज को लेखक तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलना। अगर यहाँ आकर हम इस नतीजे पर पहुँचते हो कि इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि न समाज का काम लेखक के बिना अटकना है और न ही लेखक का काम समाज के बिना, तब कोई समस्या नहीं होगी। इस नतीजे पर पहुँचने का मतलब ही होगा कि लेखक और समाज, दोनों की दिशाएँ भिन्न हैं। न लेखक को समाज की जरूरत है और न ही समाज को लेखक की। सामान्य बुद्धि से भी देखें, तो चिंता की स्थिति सिर्फ तब

बनती है, जबकि काम नहीं चल रहा हो ! जिस समाज का काम लेखक के बिना चल जाय, उसे लेखक जरूरी क्यों हो ? ऐसे ही, जब समाज के बिना ही अपने सारे काम-काज ठीक-ठाक चल रहे हो, तब लेखक को क्या गरज हो कि समाज के साथ के अपने रिश्ते को जांचता फिरे ?—किंतु यही आकर यह सवाल जन्म लेता है कि—क्या वास्तव में हकीकत यही है ?

जिन्हें जगतगति नहीं व्यापती, या कि जो जगतगति के सवाल में जाने में ही असमर्थ हो, उन्हें छोड़ दीजिये । हर समाज में ऐसे कुछ सिरफिरे होते जरूर आये हैं, जा भूख, खपती और अप्रासंगिक मान लिय जाने के जोखिमों के बावजूद सवाल उठाते हैं । जो जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कमी भी, बिना किसी सामाजिक आधार के ही सवाल उठा ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल स्वयं में ही एक सामाजिक उत्पत्ति है । जहाँ-जहाँ सवाल उठते हैं, जब-जब सवाल उठते हैं और जिन जिन कारणों से सवाल उठते हैं, इनके पीछे समाज के उद्बेसन ही मौजूद हुआ करते हैं । इसलिये किसी भी विचारवान व्यक्ति के लिये यह नतीजा सतोष की वस्तु नहीं ही होगा कि लेखक को समाज, या कि समाज को लेखक, की कोई जरूरत नहीं रही । बल्कि यह तुरत जायेगा इस सवाल में कि ऐसा आभासित होने क्यों लगा ? जो एक-दूसरे के सबसे अभिन्न अंग हैं, जिनकी स्वस्ति के सवाल एक-दूसरे पर टिके हैं और कि जिनके बीच आत्मा और वाणी के बीच का-सा अनन्य सम्बन्ध है, इनके बीच का यह अलगाव किसी सामान्य सङ्कट की निशानी नहीं होगा । बल्कि ऐसी कोई भी स्थिति इस बात का सबूत होगी कि जरूर इन दोनों के बीच कोई ऐसी 'तीसरी सत्ता' उपस्थित हो गई है, जिसने दोनों को इस मुकाम पर ला दिया है, जहाँ कि इनकी स्वस्ति या अस्वस्ति के सवाल अब खुद इनके (भी) देखते-सुनते, सोचते विचारते और जांचते चलने के सवाल नहीं रह गये हैं ।

यह 'तीसरी सत्ता' ही राज्य है ।

समाज के मुख्यतः दो अंग हैं। कर्म और चिन्तन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ एक भी अक्षय, वहाँ सकट अवश्यम्भावी है। एक लोहार और लेखक में, समाज के लिये कौन जरूरी और कौन फालतू हो सकता है? जाहिर है कि दोनों समाज के जरूरी अंग हैं और इनमें जो स्वयं के कर्म और सोच से जितना प्रतिधुत, ठीक उतनी ही हद तक उसकी प्रासंगिकता भी है। एक लोहार अगर सिर्फ स्वयं के गांव के हित को ही समर्पित हो, तो वह किसी भी मामले में समाज से प्रतिधुत लेखक से कम जिम्मेदार नहीं। कम की प्रकृति के भिन्न होने से दोनों के क्षेत्र भिन्न हो जाते हैं, लेकिन कर्म और चिन्तन में से किसी एक की जरूरत खत्म नहीं हो जाती। लोहार और लेखक में कर्म और चिन्तन का सिर्फ अनुपात बदल जाता है। इसलिये इतना अभिज्ञान जरूरी है कि मूल सत्ता समाज की है। अपने में अलग से किसी की कोई सत्ता नहीं, क्योंकि अस्तित्व स्वयं में ही एक सामाजिक तथ्य है। तब देखना जरूरी होगा कि यह जो समाज के धार्मिक और बौद्धिक, दो अंगों के बीच स एक तीसरी सत्ता 'राज्य' के रूप में सामने आती है, इसका स्वरूप इतना सर्वप्राप्ती न हो जाय कि बाकी किसी की कोई स्वाधीनता बचे ही नहीं।

'एक-दूसरे की तरफ नहीं, बल्कि सिर्फ राज्य (सरकार¹) की आर देखो' का आनाकरण निर्मित होने लगे, तो यह सघुन होगा इस बात का कि राज्यव्यवस्था का चरित्र अधिनायकवाद के मुकाम पर जा पहुँचा है। साम्राज्यवाद या तानाशाही, ये दोनों भी अधिनायकवाद के ही सिक्के हैं। समाज को इस मुकाम पर ले आना कि उसे लेखक की जगह ही अनुभव नहीं हो और लेखक को यहाँ कि 'तुम्हारा सारा बदोबस्त हम किये देते हैं'—ये दोनों ही लक्षण अधिनायकवाद के होंगे। अधिनायकवाद या वहाँ कि एवाधिपत्यवाद का यह चरित्र होता है कि बाकी सबकी सत्ता को लीनते जाओ। इस दृष्टि से देखने पर इतना विलगुल कहा जा सकता है कि—सिर्फ साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के दौर

मे ही यह सम्भव है कि समाज के संवेदनश्रोत्रों पर भी राज्य का अधिग्रहण बाधक होने लगे ।

लेखक और समाज के बीच का रिश्ता क्या है, इस पहचानने के लिए जानना जरूरी होगा कि उसका साधन क्या है । भाषा ही तो ? और भाषा का साध्य क्या है ? भाषा का सर्वोत्तम रूप वहाँ जाकर प्रकट होता है ? विज्ञान, इतिहास, भूगोल-पगोल, अर्थशास्त्र ही नहीं, बल्कि दर्शन अथवा विचारधाराओं तक में भाषा साध्य नहीं, साधन है । सिर्फ साहित्य में ही भाषा साधन नहीं, बल्कि साध्य भी हुआ करती है । यह कारण है कि भाषा कि सर्वोच्च छटा हम सिर्फ साहित्य में ही मिलती है । महाकाव्यों की भाषा और अर्तवस्तु को पृथक् करना असम्भव है । भाषा जहाँ मनुष्य से अभिन्न हो जाती है, वह क्षेत्र भौतिक नहीं, आत्मिक ज्ञान का है और आत्मिक ज्ञान के सारे स्रोत संवेदना से जुड़े हैं । भौतिक-ज्ञान के बुद्धि से । लेखक का क्षेत्र संवेदन है । उसके सारे ज्ञान, ध्यान एक संवेदना पर टिके हैं । समाज के संवेदनो को भाषा में उतारने का काम उसका है और यही उसका समाज से—और समाज का उससे—रिश्ता है ।

आज चतुर्दिक के हाहाकार के बीच समाज के संवेदनो की पारदर्शी झिलमिल जो कहीं दिखाई नहीं पड़ती—कहीं से कोई ऐसी आवाज आती सुनाई नहीं पड़ती, जिसमें कि पूरे समाज की आत्मा बोलती आभासित हो सके—इसका कारण क्या है ?

अवारण कुछ नहीं होता । पूरे समाज का गला रुंधा जान पड़ता है, तो इसलिये कि राज्य का पंजा उसके संवेदनश्रोत्रों तक भी जा पहुँचा है । अपने सबग्रासी संचार-माध्यमों के द्वारा राज्य ने संस्कृति तक को अपने कब्जे में कर लिया है, क्योंकि संस्कृति संवेदना जगाती है । हर वर्बर व्यवस्था सबसे पहले आदमी की संवेदना को मारना चाहती है । उसे इतना भय सदैव घेरे रहता है कि जब तक आदमी संवेदना में बच रहा, प्रतिरोध करेगा जरूर । सुलकर नहीं, तो छिपकर । बोलकर

नहीं, तो समय आने पर बोलने का संकल्प करते हुए ! आज नहीं, तो कल ! कल नहीं, तो परसो ! परसो भी नहीं, तो बरसो के बाद ही सही, लेकिन संवेदना बच रहेगी, तो आदमी कभी-न-कभी बोलेगा जरूर !

आपात्स्थिति क्या थी ? राष्ट्रीय पैमाने पर संवेदनाहनन का परिणाम ही तो ! और अवसर पाते ही लोगो ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, व्यवस्था भूली नहीं है । वह भली-भांति जानती है कि यह अन्तिम सघर्ष नहीं, इसलिये संवेदनाहनन का सिलसिला सतत जारी है । जो भी वस्तु आदमी में संवेदना जगा सकती हो, उसे या तो खरीद लेना है—और या तोड़ देना—यह पक्का इरादा आज भी व्यवस्था में ज्यो-का-र्यो मौजूद है । लेखक और समाज के बीच के रिश्ते को छ्वस्त कर देने की मुहिम इसी योजना का एक अंग है, लेकिन यह काम वह डके की चोट पर नहीं, बल्कि सात पर्दों के पीछे से करने में विश्वास रखती है ।

आज देश के अधिकांश मूर्ख लेखकों की शक्ति श्रुति अथवा कलात बौद्धिकों की निकल आई है, तो इसलिये कि लेखकों ने समाज के संवेदन-क्षेत्र पर भी कब्जा जमाते सर्वग्रासी पक्षों की तरफ इंगित करने का इरादा छोड़ दिया है । उन्होंने मान लिया है कि देश में कहीं क्या हो चुका, हो रहा या होने वाला है, यह देखने का काम उन राजनैतिक नेताओं का है, जिन्हें राज्य चलाना है । शिक्षा, भाषा, कानून और प्रशासन—ये सब राज्य के अंग मान लिये गये हैं और ज्यादातर लेखक इन पर कुछ नहीं बोलना चाहते । अनुमति के दायरे से आगे बढ़ते लेखकों को डर लगता है । जबकि लेखक का वास्ता उस हर वस्तु से होना जरूरी है, जो संवेदना से जुड़ी हो ।

आज की वास्तविकता यही है कि देश के मूर्ख लेखकों और व्यवस्था के बीच एक दीर्घकालिक अनुबध हो चुका-सा दिखाई पड़ता है । शिक्षा, भाषा और प्रशासन ही नहीं, बल्कि साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी राज्य के एकाधिपत्य को एक आम स्वीकृति मिल चुकी है । अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं, लेकिन जहाँ तक हिन्दी का सवाल

है, किसी भी मूर्ख लेखक को शिक्षा, याय, कानून, सविधान, भाषा या प्रशासन के ज्वलंत सवाल पर इस तरह बोलते नहीं सुना जा सकता कि हमें लगे, हमारी बेदना की बाणी देने से बचनबद्ध लोग मौजूद हैं ।

ज्ञान से बड़ी वस्तु है, ध्यान । जिसे ध्यान नहीं रहा, उसका नाम किसी काम का नहीं । ध्यान रखने का विवेक ही ज्ञान की पहचान है । जब लेखक को इतना भी ध्यान नहीं रहे कि कैसे उसे समाज की मुख्य धारा से काटकर, हाशिये पर फेंक दिया जा चुका है, तो यह सबूत होगा कि उसका ज्ञान दीमक की बाबी बन चुका है । लेखक की एकमात्र पहचान इसमें है कि उसमें देश, काल और समाज के सवाल मिलमिलाए दिखाई पड़ें, क्योंकि भाषा की पहली शर्त पारदर्शिता होने से, झूठ और सच के बीच की धुंध को दूर करने में ही उसकी कुतार्थता है ।

लेखक का काम झूठ और सच के बीच धुंध को कायम रखने में हाथ घटाना नहीं है । आज किसी भी सामाजिक सकट पर किसी मूर्ख लेखक का कोई ऐसा लेख कभी मुश्किल से ही देखने को मिलेगा, जिससे लगे कि ध्यान रखा गया है । ध्यान रखा गया है कि समाज का कोई भी ऐसा अंग नहीं, जिससे कि लेखक का कोई वास्ता नहीं बनता हो । जो-कुछ भाषा, वह सब-कुछ लिखने वाले की हद में है । कोई यह तक नहीं दे सकता कि यहाँ लेखक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसने किस वस्तु का क्या मतलब बताया है—और गलत बताया है कि सही—यह समाज को दस्तावेज़ा तौर पर लिखकर बताने का काम लेखक के निम्न है । लिखने का इरादा ही अपने आपमें लिखने का हक भी है । देखने की बात है सिर्फ यह कि अपने इस हक का किस कितना ध्यान रहता है ।

क्यों नहीं राष्ट्रभाषा का सवाल आज तक हल नहीं हो पाया ? क्या सविधान के अत्यंत ही घातक अंतर्विराधा पर कोई बहस आज तक शुरू ही नहीं हो पाई ? क्यों पंजाब की धू-धू निरंतर बढ़ती ही जाती है ? क्या देश की नयी पीढ़ियाँ की आँखा में अंग्रेज़ा की ओलाद बन सकने के सपने दिन-पर-दिन गहरे ही हाँसे जा रहे हैं ? क्यों याय और

मातृन खरीद-फरोख की सामग्री हो गये हैं ? क्या प्रशासन सामान्य जनों के प्रति क्रूरता की हद तक लापरवाह होता गया है ? साम्प्रदायिकता का जहर और गहरे, और गहरे क्यों घुनता जाता है ? इस तरह के तमाम सवालों का एक ही जवाब है—इसलिये कि जिन पर झूठ को झूठ और सच को सच बताने की जिम्मेदारी थी, वही अपनी कीमत लगवाकर, एक तरफ हो गये ।

अगर कहें कि देश का बौद्धिक वर्ग ही समाज के प्रति सबसे ज्यादा विश्वासघाती वर्ग है, तो क्या यह झूठ होमा ? विडम्बना तो है यह कि जो आर्थिक तौर पर जितना सुरक्षित, वही इन सवालों पर सबसे अधिक गुमसुम है । उसे साफ दिखाई दे रहा है कि हम आखिर-आखिर किस सवप्राप्ती अंधेरे के हवाले होने जा रहे हैं, लेकिन वह भी देश के पूँजी-निवेशियों और राजनैतिक नेताओं की तरह इस पूरे इतमीनान में जी रहा है कि—जगल की आग जगल तक ही रहेगी !

समाज जगल नहीं है । समाज को आग के हवाले रखना ठीक नहीं । सबसे गहरी आग आदमी के भीतर के अलाव में जलती आई है । बड़े-बड़े सम्राटों और तानाशाहों के हवामहल इसी आग में राख हुए हैं । लेखक को आदिम-अग्नि का ज्ञान सबसे जरूरी है । उसे यह ध्यान जरूरी है कि उसकी सामाजिक साख क्यों नष्ट हो गई । आखिर क्या बात है कि लोगो ने उसे अपने ध्यान से ही उतार दिया और मान लिया है कि हमारे सारे सरोकार सिर्फ राजनेताओं से जुड़े हैं । लेखक का, समाज की मुख्यधारा से दूर, साहित्य और सस्कृति के शोभा प्रतीकों की हैसियत का जीवन ही उसका सबसे दुखद मरण है । जिसके जीवित होने का अहसास समाज को नहीं, वह लेखक जिंदा मुर्दा से बेहतर कुछ नहीं । जो लेखक समाज को फालतू हो चुका, गाँव के कुत्ते से गया-बीठा है ।

बगदाद के एक फकीर का वृत्तांत वही पढ़ा था ।

बगदाद के किसी खलीफा ने ऐलान करवा दिया कि वह खुद ही

खुदा भी है, और जो कोई इस बात पर ईमान नहा लायेगा, उसकी गदन फाँसी के फंदे में हवाले होगी। धीरे-धीरे ऐसा सन्नाटा छाया कि फाँसी का फंदा खाली-का-खाली ही हवा में झूलता रह गया। बहुत खोजने पर पता चला कि वही दूर के बियावान में एक फकीर है, जो खलीफा हुजूर के खुदा होने पर ईमान लाने से इकार करता है। फकीर को, मुश्कें बाँध, खलीफा के दरबार में हाजिर किया गया, तो भी फकीर की गर्दन आदाब में झुकी नहीं। आखिर खलीफा खुद गद्दी से उतर कर नीचे तक आया। उसने अपने जजीर से बड़े खौफनाक और बदशक्ल कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए पूछा—‘अरे ओ, ऊपर वाले खुदा की रट लगाने वाले, फकीर! तेरी जिदगी सिर्फ एक सवाल पर टिकी है। तुझे सिर्फ उतना जवाब देना है कि यह मेरा कुत्ता और तुम—दोनों में बेहतर कौन है? कौन है बेहतर—तू कि मेरा यह वफादार कुत्ता?’

फकीर का जवाब था—‘जितना यह कुत्ता तुम्हारा, इससे कहीं ज्यादा वफादार अगर मैं उस पाक परवरदिगार से हूँ, जो कि जस मेरा, वस ही तुम्हारा भी निगहवान है, तो कहने का हक है मुझे कि इस कुत्ते से बेहतर मैं हूँ। और अगर ऐसा नहीं, तो जाहिर है कि यह कुत्ता मुझसे बेहतर है।’

कहना जरूरी नहीं होना चाहिए कि लेखक की समाज ही खुदा है। क्योंकि सिर्फ तभी तक उसका बज्जद है, जब तक कि वह समाज से जुड़ा और वही से खुराक पा रहा है। समाज से नाभिनाल-सम्बन्ध के खत्म होठ ही उसका बज्जद भी खत्म है। फिर तो वह जितने दिन जिंदा है, पहल की जमा पूँजी से है। लेखक के तौर पर बच रहता है सिर्फ वह, जिसका नाल समाज से गटी नहीं। जो समाज के गर्भगृह से हटा नहीं। इसी का दूसरा छोर है यह कि जिस समाज में लेखकों की बोलती बंद हो, वह बिना पसियों का जगल है।

इस सग्रह की टिप्पणियाँ समाज के विभिन्न सवालों पर मुँह खोलन की योशिश भर हैं। इनकी व्यर्थता स्वतः उजागर है। लेकिन, फिर भी,

इतना कहने की इजाजत चाहिये जरूर कि सवाल से ऊपर कुछ नहीं। जो खुद को सवाल से ऊपर लगाये, वह तानाशाह है। और जो सवाल से बाहर हो गया, वह बेवज्जद! आदमी को तो न तख्त सवाल से ऊपर है और न तब सवाल से बाहर। तबे से लेकर तख्त तक निगाह रखने वाला ही दावा कर सकता है कि जागता है।

इन टिप्पणियों में से अधिकांश, 'कागज की नाव' शीघ्रक स्तम्भ के अनर्गत, अक्टूबर ८७ से लेकर अप्रैल ८८ के बीच की अवधि में, 'अमृत प्रमात' और 'अमर उजाला' दैनिकों में छपी। इनमें कुछ ऐसे प्रसंगों पर बोलने की कोशिश है, जिन पर प्रायः नहीं लिखा गया। सविधान और कानून पर खासतौर से। लिखने वाला का काम ध्यान दिलाना है और लिखे की कोई सार्यकता ही तब है, जबकि ध्यान जाय।

काल भी बोलता है। आदमी के रहते सब बोलते हैं। सवाल सिर्फ सुनने का है। आज हम जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं, यह वक्त है कि साहित्य, कला, शिक्षा, राजनीति और ग्याय—समाज के सारे मुख्य अंगों के प्रवक्ताओं के बीच सवाद जरूरी है। सवाद के लिए जरूरी होगी गहरी चिंता। चिंता गहरी हो, तो ध्यान भी स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। कहना-सुनना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने वाले से कम महत्व सुनने वाले का नहीं। सब को सुनने में समथ लोग ही सब के कह जान का वातावरण निर्मित करते हैं।

ये टिप्पणियाँ उग्र हो सकती हैं। झुटिया भी जरूर होगी, लेकिन इनमें जो-कुछ कहा गया है, अवज्ञा या अवमान नहीं, बल्कि वेदना और चिंता है। इनमें एक बहस उठाने की कोशिश है, साहित्य, शिक्षा और कला या चिंतन ही नहीं, बल्कि राजनीति भी समाज का उतना ही मुख्य अंग है। कह कि जहाँ तक तात्कालिक प्रभावों का सवाल है, राजनीति का पलड़ा सबसे भारी है। कानून का अधापन राजनीति के अधों की देन हुआ करता है, इसलिए जो सही दृष्टि और दिशा की राजनीति करने का

दावा रखते हों, उन्हें न्याय और कानून पर किसी भी गहरी बहस से कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहस से ही घुघ दूर होती है।

आज बहस की सबसे खास जगह को भी बंदूको ने घेरना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हमारा इगित ससद की ओर ही है। और इतना कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि हर वस्तु अपनी जगह पर ही शोभा देती है। बंदूकों बहस से बड़ी होने लगे, तो उन्हें छोटा करना जरूरी है। बहस आज पूरे ससार की सबसे बड़ी जबरत है और बहस की भी पहली शर्त है, ध्यान।

ये टिप्पणिया ध्यान दिलाने की अदना कोशिश-भाव हैं।



कागजों की नाव

मुहावरा तो यही है कि 'कागज की नाव कितनी दूर तक जायेगी' लेकिन जरा ध्यान से दूसरा पहलू देखिये, तो पता चलता है कि इससे ज्यादा दूर तक कोई नहीं जाता। क्योंकि चलन में आने ही कागज पर की लिखत पढ़त जीवन्त हो उठती है और कागज 'चालान' बन जाता है। काल की धारा में कागज की नाव से ज्यादा कोई नहीं टिकता। आदमी तक हमेशा बड़े बड़े मालवाही जहाजों से ज्यादा सामग्री पहुँचाती आई है, कागज की नाव। मानसिक, बौद्धिक और वैचारिक राशन-पानी-हर्बा हथियार पहुँचाने का सबसे बड़ा माध्यम है—कागज। समस्त मानवीय ज्ञान-विज्ञानों का परिवहनवाय यह नाव ही समाले है। दूरदशन और आकाशवाणी में भी वह यात बहती। कागज पर की लिखत पढ़त के बिना, इन दाना ठिकानों पर भी सिवा सनाटे के और कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ना।

हम अक्सर पढ़ते हैं, जरा इसे ही ध्यान से देख लें। सिर्फ बीबीस पण्डों के सफर में यह देश-विदेश, ज्ञान विज्ञान, इतिहास-भूगोल, विचार-कला, साहित्य सस्कृति और राजनीति की कितनी सामग्री हमारे दरवाजे तक छोड़ जाता है? आप कह सकते हैं कि यह

कागज की मान भी वहाँ ज्यादा देर तक चलती है। इसमें छद्म की पटाई खत्म हुई कि अखबार रहीवासे खाने में जमा हो गया। हम कहेंगे, अंतर कहा जायेगा? कितने लोग अखबार तो पढ़ते हैं, लेकिन इस बात की उन्हें हवा भी नहीं लगती कि इस पर छपी सामग्री उनको क्या बनाती और वहाँ पहुँचाती चली जा रही है। आज के सारे राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि सामाजिक सार्वजनिक आर्थिक सोच-विचार को भी सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बरामात यही है—
येह कागज की मान!

अपनी दिन भर की बातचीत और सहस्र मुवाहिमा का सलाहोगा हम तैयार करें नभी, तब ही पता चल सकता है कि हमारी सारी मानसिक और वैचारिक बनावट में इसकी हिस्सेदारी कितनी है। हजार रूप हैं इसके। वही यह बलाकृति की शकल में है तो कहीं पोखी पत्रों के। मसि कागद नहीं छूने और कलम हाथ में नहीं लेने का दावा करने वाले यकीन को भी यादिर मजबूर होकर कहना पडा — 'दाई आखर प्रेम का, पढे सो पढित होय।' यानी सिफ़ बरने में ही कुछ उ होगा, चाहे जिदगी भर कैसा भी महान् प्रेम करते फिगे। पढित, यानी प्रेम का सचमुच का जानी, होन के लिए चाहे दाई आखर ही मही, पढना जरूरी होगा प्रेम को। और पढ़ेंगे कहा आप, कागद पर ही तो?

कागा रे, मोरा सदेसवा पिपा से कहियो जाय ।' माना कि कागा ने पहुँचा भी दिया सदेश, तो यह सब पता चलेगा कैसे ? और कब ? सिवा इसके कि बागज के किसी काने में सहेजा हुआ हम तक भी पहुँच जाय ? कहने का मतलब कि 'कागज को नया वहाँ तक जायेगी' मुहावरे में भी नमोहत है यही कि इस नया का बहुत ध्यान से देखना की जरूरत है । तभी हम जान भी सकेंगे कि यह सचमुच कितनी जरूरी चीज है, और कि इसमें की सामग्री की तकीकत क्या है । और १. हमारे हक में है कितनी खतरनाक ! क्या क्या है इसमें, जो

हमारे ज्ञान की शाखाओं को समृद्ध करेगा। और कितना ऐसा, जो हमारे सोच विचार और सत्कारी की जड़ें खोखली कर डालेगा।

आप अखबार पढ़ते हैं? ध्यान से देखते हैं कि रोज सवेरे दरवाजे से आ लगने वाली इस कागज की नाव में क्या क्या सामग्री पहुंचाई जा रही है आप तक? दूध, डबलरोटी, सब्जी और फल, अपना दिन-दिन उपयोग की सामान्य वस्तुओं को जितना उसट पुलट, नाप जोख और जाच परख कर लेते हैं आप, क्या इतना ही ध्यान इस कागज की नाव पर के सामान पर भी देते हैं, जो कि आपकी पूरी मानसिक वपारिक दुनिया को प्रभावित करता है?

एक बात आइने की तरह साफ रहनी चाहिये। बिना उद्देश्य के कोई कुछ नहीं करता। निरुद्देश्य न कोई कुछ सिखता है, न छापता है, न पढ़ता है। क्या हम कभी ध्यान से देखते हैं कि किस उद्देश्य से पढ़ते हैं हम कुछ भी? फिर चाहे वह अखबार हो कि किताब? सनसनीखेज काण्ड हो कि साहित्य? थोड़ा इतिहास के कागद पलट कर देखें हम लोग, तो इतना साफ पहचान सकेंगे कि पिछली कितनी शताब्दियों से हम इस चेतना से शून्य ही चल रहे हैं कि अपने रहन सहन, खान पान, ज्ञान ध्यान के उद्देश्य के प्रति उदासीन जातियां ही आखिर आखिर गुलाम बनती हैं। जिन्हें अपना उद्देश्य जाचना न आये, वो यह भी नहीं समझ सकते कि दूसरों का इरादा क्या है।

वस्तुओं को पूरी चेतना से उलटने पलटने, छानने फटकने और जांचने परखने की प्रक्रिया हममें लगभग नदारद है। न शिक्षा, न भाषा, न राजनीति कला-संस्कृति, न अखबार या किताब। कुछ भी हमारी जांच परख का विषय नहीं कि बसर वहाँ तक जायेगा। हम लालसाओं के घनी रह गये हैं, जिज्ञासा के नहीं। जिज्ञासा रखने में कुछ कष्ट होता है। इससे बुद्धि, विचार और दृष्टि के सवाल जुड़े हैं। गुलामी की बोझ ढीठ में उतना कष्ट नहीं होता, जितना

जिज्ञासा रखने में, क्योंकि जिज्ञासा सिर्फ स्वाधीन जातियों की वस्तु है। जिज्ञासा आदमी को सधप में ले जाती है। गुलाम सधप नहीं चाहते। आखिर सधर्ष से बचने की ही तो आदमी गुलामी बन्न कर रहा है।

इसमें क्या शक कि निरुद्देश्य कोई गुलामी भी नहीं करता। सौ वर्ष अंग्रेजों की गुलामी हम इसी उद्देश्य में तो करते रहे कि सधर्ष मोल न लेना पड़े। और जब सधर्ष की चेतना हममें आती, तो सूर्यास्त नहीं देखने के दावदार ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का बोरा बिस्तर बेंचने में तीस चालीस साल भी नहीं लगे। लेकिन आसमान से चले आकर खजूर पर अटक रह गये हैं हम, ता इसलिए कि विदेशी की तुलना में स्वदेशी लुटेरों को महान राष्ट्रीय तत्व मान लेना का सिद्धांत गले मढ़ गया। इस बात पर कतई कोई ध्यान नहीं दिया कि आजादी के बाद की हुकूमत को जांच-परख और उसट फेर से ऊपर मान लेने के लतरे क्या होंगे। अब परिणाम सामने है। हमारी शक्ल फिर वही सदियों के गुलामी की निकल आयी है। वही सदियों पुराना कोटर-जीवी चरित्र फिर हम पर हावी हो गया है। अपने पुनरुत्थान की प्रक्रिया में हम फिर उसी सनातन उदासीनता में पहुँच गये हैं, जहाँ अगर पंचनद के क्षेत्र में विदेशी हमलावारों के छोटे दौड़ रहे हैं तो यह पूर्वी उत्तरी या दक्षिणी हिंदुस्तानियों के सरोकार की बात नहीं। हमें अपनी अपनी जात प्यारी है। अपना अपना क्षेत्र और अपने अपने राजा साहब प्यारे हैं। राष्ट्रीय चेतना नाम की भी कोई चीज हुआ करती और आदमी को इस मामले में दिशाओं पर निरंतर आलस रखनी होती है—इस सबसे हम अपनी अपनी मंथिया के मस्तानों का क्या लेना। जो आज पंजाब, कल हमारी छाती पर भी अपनी फौजी घमक कायम करेंगे जरूर, इतना चेत रहा होता हमें, तो मुट्ठी भर गोरों साहबों की कम्पनी सात समुद्र पार आकर हमारी पीठ पर कोढ़े वही बजा पाती ?

विषय को फिलहाल यहाँ सिर्फ अखबारों की दुनिया तक सीमित

करते हुए हम अब फिर सवाल उठाना चाहेंगे कि हमारे राशन पानी, हाट बाजार, रास पियेटर, इल्म-फिल्म, कला संस्कृति इतिहास भूगोल या राजनीति, नवि धूमिल के शब्दों में कह तो, 'समय से सड़क तक' के सवालों से यास्ता है इनका। लेकिन अब बार पढ़ते वक्त क्या हमें सचमुच ध्यान रहता है इस बात का? इन कागज की नावों में हमारे छोर तक पहुँच गयी सामग्री को अपने हित के हिसाब से जाचते परखते हैं कभी? कभी उठाया है हमने यह सवाल कि थप्पड़ जरूर एक ही हाथ से मार सकता है कोई, लेकिन ताली हमेशा दो हाथों से बगती है ?

आखिर अब बार निकालने वाला न एकतरफा तौर पर यह फमला कैसे कर लिया कि हम, जितना ज्यादा सम्भव हो सके चरित्र में बीना, लेकिन मानसिकता में सनसनीबाज बना दिया जाय? क्रिसते कर दिया हमारे सारे राजनीतिक नुमाइशों को इस इतमीनान में कि हमारे लिए 'ब्लू स्टार ऑपरेशन' से लेकर 'ब्लू फिल्मों' तक का सारा सिर्फ समाशास्त्रों की हैसियत से हिस्सा लेना का रहेगा— सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक मुद्दों पर हमारी किसी पहल का कोई मतलब नहीं होगा। वोट देने के बाद हमें झूल जाना होगा कि डिम्बों में भरे कागज के टुकड़ों का आखिर हुआ क्या? लोकतंत्र का मतलब हमारे लिए सिर्फ हाथ कटाकर देना होगा— कट हुए पत्रों वाले हमारा क्या हाल करेंगे, यह उनके तय करने की बात होगी !

क्या रुझ है अब बार नबीसों का हमारे प्रति ? जैसा ये समझना चाहें उतना ही हमारी समझ को काफी है ? जितना और जैसा ये महसूस कराना चाहे, इससे इधर उधर हमें नहीं हाना है ? ये हम खुद भी चीजों को खान फटक और जाँच परख लेने की चेतना में लैस करना और इस बात से खबरदार रखना चाहते हैं कि जो अपने सारा सच नहीं उठा सकते, वो कभी स्वाधीन नहीं रह सकते ? या

कि देखकर, इस मानसिक वैचारिक जड़ता में डाले रखना चाहते हैं कि जो कुछ इन्होंने हमें बताया, उतना ही हमको ज़रूरत से ज्यादा है ?

सामाजिक आर्थिक चेतना की जगह, फिन्मी जाकी और सांप्रदायिक ज़हरवाद के बीटाणमों के अड़्डे क्यों बढ़ते जा रहे हैं हमारे सोच विचार की दुनिया में ? कौन हैं ये लोग, जो सुबह सुबह गद, फुहड़ और विद्रुस विनायनों के पोस्टर फँला जाते हैं, हमारे घरों में ? कैसे जान लिया इन्होंने कि हमें अपने देश काल और समाज के सुलगते सवालों से ज्यादा भया सनसनीखेज हत्याकाण्डों, अश्लील कृतित्त विनायनों तथा किस्मों सितारों के नगनाच में आता है ? किसने कर दिया इन्हें इस इत्मोनान में कि हमें सुकारात्मक राजनीति नहीं, बल्कि सनसनीखेज राजनीतिक कांडों में ज्यादा दिलचस्पी है ? रामस्वरूप कुमारनारायण बाबू हों, या कैप्टनफैस बोफोस बाबू — 'स्तूस्टार आपरेशन' हो या दिल्ली जमशेदपुर बानपुर के कलामा आतंकवाद हो या सांप्रदायिक दंगे ये सब 'पढ़ने का भया' लेने वाली चीजें हैं ।

हर वस्तु के दो छोर हैं । एक छोर अधेरा, दूसरा उजाला है । एक छोर जड़ता दूसरा चेतना का है । एक पर राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक चेतना को जगाने का सवाल है — दूसरे छोर पर सारे शोषण उत्पीड़न से उदासीन पड़ रहने का । हमारे अलबार्नबीस हमें किस छोर पर रखना चाहते हैं ?

जो कागज पर की लिखत के प्रति उदासीन हों उन्हें गारत होते ज्यादा बक्त लगता नहीं । कुछ नहीं इस ससार में, जिसे कागज के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाया जा सकता हो । कागजी कार्यवाहियों के बिना किसी कार्यवाही का कोई अस्तित्व नहीं । वह हर चीज कागज है, जिसमें कुछ दर्ज है । ध्यान से देखें, सभी जान सकेंगे । 'कागज की नाव' का दर्जा क्या है ।

किसको किससे खतरा है ?

खतरे का सवाल बहुत व्यापक है। हम यहाँ, फिलहाल, एक सीमित प्रसंग में बात करना चाहते हैं। हिंदुओं से मुसलमानों और मुसलमानों से हिंदुओं को खतरे पर। दृष्टांत के लिए भी 'राम ज मभूमि बनाम बावरी मस्जिद' के नाजुक सवाल को ही इसलिए सामने रखना चाहते हैं कि इस हमाम में हमारी सांप्रदायिक नगई अब बिलकुल साफ साफ झलकने लगी। हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिकता की आग जितनी इस प्रकारण पर फूटी है वह दोनों सम्प्रदायों के धार्मिक पाखण्ड, सांप्रदायिक जहर और नैतिक उजाड़ की ऐसी भयावह शक्त सामने लाती है, जो आने वाले वर्तनों में कभी पूरे देश में आग का दरिया फैला सकती है।

हिंदुआ और मुसलमानों का धर्म के नाम पर सड़क के साँड़ों की तरह फुफकारना धमनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था की सरेआम धाज्जियाँ उड़ा रहा है, लेकिन केन्द्र में बैठे भारतभाष्यविद्याताओं को आज भी राजनीतिक जुगालियों से फुसत नहीं। जबकि देश के नागरिकों के बीच सांप्रदायिक धार्मिक टकरावों को लेकर सबसे पहले (और सबसे ज्यादा) चिंता उस सरकार को होनी चाहिये, जो धमनिरपेक्ष

राज्य का दावा रखती हो। जबकि आज्ञा के तुरन्त बाद से ही भारत सरकारों का काम तासा ठाकने और तासा खुलवाने तक सीमित रहा है। जगल की भाग की तरह सुलगते सवाल पर इस शुद्ध देशी चादरतान उदासीनता का रहस्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब धार्मिक साम्प्रदायिक द्वंद्वों तथा टकरावों की छूट भी मान लें, तो भी कानून व्यवस्था का सवाल बाकी रह जाता है। सरकार यह प्रभाव उत्पन्न करने से हमेशा बतराती रही है कि धार्मिक मतलों को कानून से ऊपर नहीं आने दिया जायेगा। स्वर्णमंदिर म'ब्लैकबडर आपरेशन' के बाद धर्म को राष्ट्र के कानूनों से ऊपर नहीं आने देने और राजनीति में धर्म के घासमेंल से बचन की उद्योपणाएँ जकर तेजी पर हैं इधर, लेकिन इस युनियामी सवाल से अब भी कोई वास्ता दिखता नहीं कि जब धर्म और जाति के समीकरण का चुनाव की प्रथा चलन में हो, तब राजनीति से धर्म का बहिष्कार होगा कैसे ?

सिफ इतना ही काफी हाता कि नाना प्रकार के धार्मिक विश्वासों रीति रिवाजों और परम्पराओं वाले समुदायों को यह बात साफ पता रहती कि दश में कानून का राज्य है और कस भी धार्मिक विश्वासों को सिफ कानून के भीतर ही हल किया जा सकता है—साम्प्रदायिक शक्ति प्रदर्शन के द्वारा नहीं। संविधान में जनहित और राष्ट्रहित में रोक लगाने की स्पष्ट व्यवस्था है, लेकिन सरकार समय समय पर साम्प्रदायिक शक्ति प्रदर्शनों की खुली छूट देती चली आ रही है। 'राम ज मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद' मामले का सबसे खतरनाक पक्ष यही है कि हिंदू धीरे मुस्लिम साम्प्रदायिक शक्ति प्रदर्शन का मुद्दा बना दिया गया है। मुसलमानों के कठमुल्ले प्रतिनिधियों का तर्क है कि बाबरी मस्जिद के मामले में दब जाने का मतलब हमेशा हमेशा के लिए हिंदुओं के दबाव में आ जाना होगा। हिंदू धर्मधुरीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया है कि राम ज-मभूमि पर मुसलमानों का कब्जा रहना हिंदू जाति की कायरता, दब्लू मानसिकता और सरकार के मुस्लिम

परस्त हाने का सबूत बना रहेगा ।

इस मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रहनुमा भारत सरकार पर हिंदूपरस्ती का दृष्टान्त लगाते नहीं थकते और राम जन्मभूमि मूर्ति संगठन व वर्तनीधर्ती मुस्लिमपरस्ती का । और आश्चर्य कि सरकार को इस यथास्थिति के कायम रहने में ही घमनिरपेक्ष राज्य की कामयाबी दिखाई पड़ रही है । जबकि कोई भी सरकार एक ही समय में मुस्लिमपरस्त और हिंदू-वादी, दोनों साथ साथ नहीं हो सकती । और अगर ऐसा भ्रम बनता हो, तो इसका सीधा मतलब होगा कि सरकार दोनों सम्प्रदायों के साँपों को दूध पिलाती चल रही है ।

आये तब इस तरह के समाचार आते रहते हैं कि मुसलमानों की ईद और मुहर्रम पर फला फला जगह के हिंदुओं ने कैसे साफ़ेकारी निभाई तथा रामलीला भरत-मिलाप या होली दीवाली पर मुसलमानों ने हिंदुओं के कंधे से कैसे कंधा मिलाया रखा । देश के अधिकांश खेति-हर इलाकों में आज भी हिंदू-मुस्लिमों का सम्बन्ध एक ही धरती के बंटो के मेल मिलाप का सबन्ध है । समाज के प्रबुद्ध तथा सवेदनशील तबकों की पक्षधरता भी सामुदायिक सौमनस्य के प्रति है, सम्प्रदायिक दरिद्रता नहीं । तब भी यह ले के रहेंगे बाबरी मस्जिद !' और मुक्त करेंगे जन्मभूमि की, तभी करेंगे हम विधाम—हिंदू को धिक्कार ह तब तक, जब तक बघन में है राम !' की मगनभेदी विघाट कायम क्यों है ?

अब थोड़ा इस प्रसंग पर भी विचार कर लें कि क्या राम जन्म-भूमि बनाम बाबरीमस्जिद का मामला वास्तव में ऐसा मसला है कि जो हमेशा हमेशा के लिए एन-एन समुदाय को नीचा दिखाया बिना हल हो हो नहीं सकता ? क्या इतिहास की गवाहिया यह सिद्ध करने में सक्षम अक्षम हैं कि पहले जन्मभूमि का अस्तित्व था, या

मस्जिद का ? मान लें कि इतिहास का सच हमारे सबधों को भाई चारे की आँख नहीं देता, बल्कि आँखें आता है, तो भी सवाल सामन होगा कि 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा, हम बुनबुने हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा' के वृद्धमान का मतलब क्या माना जाय ? एक देश के बाशिंदों की तरह जीने के आवासीय लोगों में इतना भी सहज विवेक और सोमनस्य नहीं कि इतिहास के काले घन्टों को आपस की साझेदारी से साफ कर सकें ? अगर नहीं, तो ऐसे जड़ तथा दुबुद्धि लोगों को साम्प्रदायिकता का जहर घोलने से कौन रोक सकता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब धार्मिक साम्प्रदायिक हंगामों की खुली छूट के सिवा और कुछ नहीं हो ?

क्या होना चाहिये पूरे देश के लिए एक खतरनाक नासूर इस वितण्डावाद का, इस बहस में फिलहाल यहाँ सिर्फ यह सवाल उठाना चाहेंगे कि क्या हम इस धार्मिक साम्प्रदायिक जहरवाद का हल हकीकत में चाहते भी हैं ?

समस्याएँ दो तरह की होती हैं । एक, जिनका हल कोशिशों के बावजूद नहीं निकल पा रहा हो । दूसरी, सारा जोर जिन्हें बनाने रखने पर होता है । 'राम जमभूमि बनाम बाबरी मस्जिद' समस्या दूसरी तरह की समस्या है । इस समस्या को खड़ी करने के पीछे मने ही शुद्ध धार्मिक साम्प्रदायिक भावनाएँ काम करती हो, लेकिन इसे लगातार खड़ी रखने, और भीके के हिमाय से दबाने या उभाड़ने के पीछे सत्ता की सियासतबाजी काम करती चली आ रही है ।

दोनों घड़ों के धार्मिक साम्प्रदायिक नेताओं के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचने के लिए लड़ाई जारी रखने के सारे मक़द सग्राम का रहस्य यही है कि समस्या के हल होने का मतलब होगा, उनकी धार्मिक साम्प्रदायिक मियासत की तिजारत का रास्ता बद होना । राम जमभूमि बनाम बाबरी मस्जिद का सारा झगड़ा हिन्दू मुसलमानों की

धार्मिक, साम्प्रदायिक भावनाओं को भटकाकर, खुद की राजनीतिक तिजारत कायम रखने वालों का करिश्मा है। इस समस्या के हल होने का मतलब एक सदाबहार राजनीतिक घड़े का हाथों से निकल जाना है। अथवा इतना कौन नहीं जानता कि साड़ो के लगातार नयुने फूलाते घूमने का सीधा मतलब है कि नकेल कहीं और है।

आखिर एक न एक दिन इस फैसलाकुन मुकाम पर पहुँचना जरूरी होगा कि राम ज मभूमि या बि बावरी मस्जिद। ऐसे में यह सवाल आज ही पूछ लेने में क्या हज़ है कि कौन और कैसे लेकर रहेगे बावरी मस्जिद? कौन और कैसे स्थापित करेंगे अखण्ड राम ज मभूमि? और कब? कब निकलेगा आखिर वह मूहूत, जबकि बावरी मस्जिद और राम ज मभूमि के दावेदारों के बीच आखिरी फैसले की लड़ाई लड़ी जायेगी? और घमघुड़ का ऊट इस या उस करवट बँठकर, अटकलों की सासत से मुक्त करेगा?

जहाँ तक हम समझते हैं, बाजुओं के जोर पर फैसला करने की नौबत सिर्फ तभी आ सकती है, जबकि सरकार और कानून व्यवस्था नाम की चीज़ खत्म हो जाय, बराबर्ता और गृहयुद्ध का दौर चल पड़े — और या सरकार भी तय कर ले कि अब मसले का खत्म हो जाना ही उसके हक में है। जब तक सरकार किसी एक के पीछे नहीं, दोनों के साथ मौजूद है, तब तक ही दोनों घड़ों के बठमूल्तो की मारी 'फो फो' कायम है। जिस दिन सरकार किसी एक घड़े की पीठ पपधपा देगी, दूसरा मिट्टी संघता दिखाई देगा। धार्मिक साम्प्रदायिक विचार, में सरकार को पंच बनाये रखने की मौजूदा भेड़चाल हिंदू मुसलमान, दोनों को आत्मविनाश के मुकाम पर ले जायेगी। और दोनों में से किसी एक को पंजाब की नियति से सामना पड़ेगा जरूर! राम ज मभूमि बनाम बावरी मस्जिद के धार्मिक साम्प्रदायिक उमाद को सरकारी छूट के हिसाब से बुलंद रखने के नसीजे जब भी निकलेंगे, हिंदू मुसलमान, दोनों की बर्बादी में निकलेंगे। क्योंकि जो भी बात देश के

हक म नहीं हो, बाशिंदों के हक म कभी नहीं होगी।

झगडा खडा करना, लेकिन नतीजों से बचना, य दो काम साथ साथ नहीं हो सकते। जब तक राम ज मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद का कोई दोनो ममुत्तायो को स्वीकार नतीजा नहीं निकलेगा, तब तक भी इस सांप्रदायिक धार्मिक जहरबाद के नतीजे निकलते ही रहेंगे। अयोध्या की भूमि पर कायम यह सांप्रदायिक जहर भिवण्डी जहमदा बाद-मुरादाबाद मेरठ औरगाबाद चगरा क्षेत्रो के अपना असर दिखाता रहेगा। इसे कायम रखना यमन और भाईचारापसंद लोगों क हक मे नहीं। इस जामूर के कायम रहते हिंदू मुसलमान एकता की सारी खामलयालिया बेकार हैं। हिंदू सिखों के बीच जो सिर फुटव्वल स्वण मंदिर की राजनीति ने कायम की, उसके नतीजे सामने हैं। समय रहते नहीं सँभले हम, तो 'राम जमभूमि बनाम बाबरी मस्जिद' का अजाम इसमे भी बन्तर तीर पर सामने आयेगा। अपना अपना मौका साधने और दाव लगान की ताक मे बठे लोगों के बीच कोई भाईचारा कभी किसी हाल मे कायम नहीं हो सकता। राम जमभूमि बनाम बाबरी मस्जिद के झगडे ने हिंदू और मुसलमानों की पूरी मानसिकता मे जहर घोल दिया है। एक दूसरे को दुश्मन की शकल मे देखने का ही यह नतीजा है कि अगर मुसलमान के कान मे 'इस्लाम खतरे मे है' की अजान पड़ती है तो वह जल्दी से कान नहीं हटा पाता। और 'हिंदू धर्म संकट मे है' की चिल्लाहने से ही हिंदू को होता है कि मुसलमानों के मौजूद रहते यही हाना है।

आज के हालात क्या हैं? हिंदू को मुसलमानों से खतरा है मुसलमान को हिंदुओं से। ताजुब कि जिस धार्मिक सांप्रदायिक सिया सतवाजी ॥ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भात के हर एक नागरिक को खतरा है उसी से खतरा कोई महसूस नहीं करता। यहीं हम यह सवाल सीधे सीधे सठाना चाहते हैं कि अगर रुचमच हबैत यही है कि हिंदुओं से मुसलमानों और मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है,

फिर यह धर्मनिरपेक्ष भारत सरकार किस मज की दवा है ? इसके मस्ये पर मौजूद रहते सबके सब एक दूसरे से इतनी नफरत और दहशत में क्यों हैं ? हर एक समुदाय के लोगों को यह भरोसा क्यों नहीं है कि अगर कभी वहीं कोई भगड़ा उठा भी, तो सरकार सिर पर मौजूद है ? सर्वप्रभुत्वसम्पन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के कायम रहते हिंदुओं को मुसलमानों और मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा क्यों है ?

राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद एक मुसलमान सवाल है और इस सवाल से भगना ठीक नहीं । इतना कह लेने की हमें इजाजत रहे कि अगर भारत सरकार सधमुच हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखना चाहती हो, तो यह सवाल खुद उसके हक में भी उतना ही है, जितना हमारे ।

हिन्दू और मुसलमान

कितना कम फासला है, रामजन्मभूमि और याबरी मस्जिद में, लेकिन कितना रास्ता ! एक तरफ राम जानकी रथ के चक्के इस दूरी को नापते नापते थक चुके, दूसरी ओर 'लेके' रहेगे याबरी मस्जिद ।' का जिहानी सफर तय करने वालों को तलुओं में पड़े खानों ने बेहान कर रखा है ! हिन्दू और मुसलमान के बीच का फासला भी एक तरह से कितना कम है, और दूसरी तरह से कितना ज्यादा ! .. इस फिक्क में ही हमने कहा कि — हम तुम्हारे किसी तरह न हुए तुम हमारे किसी तरह न हुए । यर्ना दुनिया की तो बात ही छोड़ दें, इसी 'हिन्दूस्तान' तब से मिमालें कुछ कम नहीं कि जब जब हिन्दू मुसलमान और मुसलमान हिन्दू का हुआ है तब-तब इतिहास में कुछ बेमिसाल दृष्टांत उपस्थित हुए हैं । घुर इस्लामी गहशाहो के ही राज में हिन्दू मुसलमान के बीच दगों जैसी किसी हैवानियत को कोई पनाह नहीं मिली है । इस्लामी खून और हिन्दूस्तानी दूध के मेल ने अमीर खुमरो जैवो बेमिसाल भारतीय हस्तों को नुमाया कर दिखाया है । हिन्दू और मुसलमान के बारे में इतिहास तक यही कहला बताया जाता है कि आर्यों का एक जरया मध्य एशिया से ईसापूर्व की शताब्दियों में चला

था, दूसरा ईसवी सारीख के हजार सालों के बाद ! गंगा जमुनी सस्कृति जैसी अपूर्व तथा असम्भव चीज का वजूद कौन सी कहानी कहता आ रहा है, हिन्दू के मुसलमान और मुसलमान के हिन्दू का होने के नसोजो की साजबाज कहानी के सिवा ?

सस्कृति के मामले में भारत एक भजब मुस्क रहा है। आक्राता और मूल निवासियों के मेल मिलाप से सांस्कृतिक उत्थान की एक लम्बी परम्परा रही है इस देश में। जहाँ भारतीय सस्कृति आर्यों और द्रविड़ों के संगम की देन है, वही हिन्दुओं और मुसलमानों के साम्ने का चमत्कार है— भारतीय सस्कृति का उत्तरपक्ष, गंगा जमुनी सस्कृति ! लेकिन इस हिन्दू मुसलमान मामले का एक दूसरा पहलू भी है। गंगा-जमुनी सस्कृति की गवाही के बरबक्स हिन्दू मुसलमान के झगड़ों की कहानी भी उतनी ही बड़ी है। जितनी लबी और गहरी साम्ने-दारी, उतनी ही भीषण मारामारी भी दज है, हिन्दू और मुसलमान के इतिहास के पन्नों में। जितना उजला है इसका हिन्दू मुसलमान की साम्नेदारी वाला पहलू, उतना ही स्याह है, दूध में घुला अंग्रेजों की कूटनीति के जहर वाला हिस्सा ! बदनसीबी दोनों, और साथ साथ मूक, की कि अंग्रेजों का बोया जहर उस काप्रेस की छवछाया में लबालब सहारा नजर आ रहा है, जिसकी नींव में महात्मा गांधी की अस्थियों के फासफोरस की चमक भी गुम होती जान पड़ती है।

हम पहेलियाँ नहीं बुझा रहे। हिन्दू मुसलमान का सवाल इस मुस्क का हजार साल लम्बा सवाल है। पाकिस्तान से यह सवाल हल नहीं, और जटिल हो गया। विडम्बना यह है कि पाकिस्तान, 'पूरे में से एक हिस्सा हमारा अलग' साबित करता, एक किनारे हो गया और बाकी के हिन्दुस्तान में बरकरार रह गया है, पाकिस्तान जाने से इन्कार करने वाले मुसलमानों का साम्ना ! यानी भारत ही नहीं, बल्कि भारतीय सस्कृति की गंगा जमुनी साम्नेदारी में से भी अपना

हिंसा अलग लेके चैन की वशी बजा रहा है पाकिस्तान और इस साम्राज्य सस्कृति को पूरी की पूरी जिम्मेदारी लद गयी है दोनों पक्षों के अग भग से लहलुहान भारतवर्ष नाम के उस मुल्क पर, जिसकी फिजा में जब भी 'सारे जहाँ में अच्छा हि दोस्ता हमारा' का गान गजता है, तो बरबस याद आ जाता है कि इसके मुरीद मोलाना ओश मलीहाबादी की कब्र पर का चिराग टिमटिमाता है, पाकिस्तान में ।

कटटरपयी हिंदू भारतीय मुसलमान की इसी कमजोर मज्ज को सबसे पहले और सबसे ज्यादा छेड़ना चाहता है । यह इस सच्चाई की बरफिनार कर देना चाहता है कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया, उन्हीं की सदोस्त बचा रह गया भारत, पाकिस्तान की नकल का हिंदूस्मान बनने से । कटटर इस्लामी मुल्क की हैसियत बना चुके पाकिस्तान और बंगलादेश के अलग बगल भारत आज भी हिंदू राष्ट्र की तानाशाही शक्ल में नहीं खड़ा है, तो इसका कुछ अर्थ उन मुसलमानों को भी है, जिन्होंने पाकिस्तान जाने से इन्कार किया । लेकिन अगर आज हिंदुओं का खौफ फिर यही है कि एक पाकिस्तान और तयार करने में सगे हैं ये भारत में बच रहे मुसलमान, तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपद होती है, कांग्रेसी हुकूमत पर, जिसने कि न हिंदू का मुसलमान का बनाये रखने की कोई चिन्ता रखी, न मुसलमान को हिंदू का !

भारत के मुसलमान अग्रेज नहीं । इन्हें समुद्र पार खदेड़ने का कोई मौका हिंदुओं के पास नहीं । ये भारत के साम्नीदार हैं, और रहेंगे । यह साम्नीदारी फिर स मुल्क के बटवारे के मुकाम तक नहीं पहुँचे, यह जिम्मेदारी हिंदू और मुसलमान, दोनों पर बराबर है । भारत का पूरा भविष्य एक इसी बात पर टिका है कि क्या करना है हिंदुओं को मुसलमानों, और क्या मुसलमानों को हिंदुओं का । जैसा कि पहले ही कहा, दोनों के बीच का फासला जितना कम, उतना ही ज्यादा भी है । वहाँ तक कि दूध और दूध में भी । भारत का मस-

समान 'एनोइडिडन' नहीं, लेकिन जितना ज़ेरीश-उमे उकसाया जायेगा, उतना ही वह मजहब की छतरी तानेगा, जहाँ से हिंदू और ब्रिटीश हुकूमत, तीनों यही काम

करते चले आ रहे हैं। इन तीनों को ही भारत से कुछ लेना देना नहीं। इन्हें कुछ भी इल्म नहीं कि हिंदू मुसलमान की एकता ही भारत को गारत होने से बचा सकती है। धर्मांध मिट्टी की भावें ही स्वयंसे ज़बरदास्त कमजोर हैं। बेतुना पर चढ़ी चर्वी की परता ने इनकी आँखों की ज्योति को डक लिया है। इनकी महाकाल से बड़ा हो गया है सत्काल ! अपने स वास्त के स्वार्थों के लिए य भारत के भविष्य को अंधे हुए म डकेलने से परहेज करने से रहे। हिंदू और मुसलमानों के बीच अलगाव और नफरत को बढ़ाते ही जाना आखिर आखिर फिर देश को बटवारे तथा खून खराबे के मुकाम पर पहुँचा कर ही रहेगा, इस मचाई से ये सभी अपना चेहरा छिपाये ही रहना चाहते हैं। इनकी मारी पित्र सुद तक महदूद है। देश की मरहदा या इमान की बेदनाओं के मजाल, इनके नज़दीक निरे फागून सवाल हैं जबकि हम फिर जोर देकर यही कहना चाहेंगे कि भारत का सबसे बड़ा मजाल यही है—बचा करना है हिंदुओं को मुसलमानों का और बचा करना है मुसलमानों को हिंदुओं का ? और यह सवाल ज़ब्र तक मुहम्मदगुन्ना पूरे देश में नहीं पूछा जायेगा, तब तक हम कभी समझ नहीं पायेंगे कि हिंदू मुसलमान का सवाल दरअसल कितना बड़ा सवाल है।

हमारी समझ में क्या करना चाहिये हिंदुओं को मुसलमानों और मुसलमानों को हिंदुओं का, इस तफसील को छोड़ते हुए, यहाँ किन्तु हान हम इतना इशारा भर करना चाहेंगे कि दोनों के बीच जहरीला घुसा फैलान का जरिया बन गई है, धर्म और मजहब के उपलों की भाँव म घुन की दाल बाटी पकाने की मियासत। जब तक इस मिया

मत का मुह नहीं तोड़ा जायेगा, तब तक हिंदू के मुसलमान और मुसलमान के हिंदू से टकराने, यानी आखिर आखिर भारत के टूटने का खतरा भी हर्गिज कम नहीं होगा ।

राम जमभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने हिंदू और मुसलमान के दोफाह होने का खतरा ही उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि प्यवत रहते इस जाबुक सवाल को बहुत नजदीक, उत्तने ही ध्यान से भी देख और समझ लेने का सुनहरा मौका भी सामने जरूर कर दिया है कि क्या करना है हिंदुओं को मुसलमानों और क्या करना है, मुसलमानों को हिंदुओं का । अगर भारत सरकार यह दावा करना चाहे कि इस अहम सवाल में उसकी भी दिलचस्पी कम नहीं, तो हमें उसे भी इस सुलगते सवाल में शामिल होते देखकर गहरी खुशी हो होगी क्योंकि जब तक सरकार हिंदू और मुसलमान के बीच क मगड़ों को सियासत के बुबकुट सग्राम की शक्ल में बदलते रहने पर खोर दगी, तब तक हिंदू मुसलमान के एक दूसरे के होने का सवाल भी हवा में भूलता रहेगा । यह उसी की तमाशबीनी का करिश्मा है कि राम जमभूमि के प्रात गान और बाबरी मस्जिद की अजानें उगा जमुनी सस्टुति का अनहद नाद उत्पन्न करने की जगह, हिंदू मुसल मान दगों का निमित्त बने हुए हैं । वनी पडित भीमसेन जोशी और चस्ताद अमीर खां साहब के आलापों में पक कितना !

मजहब बड़ा कि मुल्क ?

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में, अपनी बात फिलहाल आखिरी तौर पर कहते हुए इतना हम पहले ही कहना चाहेंगे कि भारत के मुसलमानों को एक ही तर्क को सबसे पहले तक करना होगा—मुल्क से पहले या मुल्क से ऊपर मजहब को मानने के तक को । क्योंकि इसी तक से भारत के एक हिस्से का नाम पाकिस्तान हुआ । और इसी मुत्तक की उपज है खालिस्तान का भूत ।

यो भी देखिये कि आदमी की सबसे बड़ी नियामत क्या है—मिट्टी, हवा पानी और कुदरत, या कि मजहब ? इतना कह लेने की इजाजत रहे कि जो भी बीज आदमी आदमी के बीच की सड़क की चौड़ा करती जाय, वह हर हाल में खाटी है । हवा-पानी और मिट्टी को इंसान इंसान में कुछ भी भेद नहीं । गंगा को हिन्दू के निमित्त भी वैसे ही बहना है, जैसे मुसलमान क । हवा हिन्दू-मुसलमान को अलग अलग चलने से रही । मिट्टी ने दोनों में फक मरते दम तक नहीं करना । जिसे हम भारतीय संस्कृति में गंगा जमुनी कलम का नाम देना चाहेंगे, वह इसके सिवा और है क्या कि धरती को जैसे हिन्दू मुसलमान, वैसे ही सनातन धर्म और इस्लाम में कुछ फर्क

नहीं ! लेकिन इसान की तो फितरत है कि वह फक करता चले । सवाल, बस इतना है कि यह फक करने की फितरत उसे ले कहा जाती है—अच्छे और बुरे का फक करने की तमीज में, या इसान की इसान से नफरत के मुहाने पर ।

सनातन धर्म और इस्लाम की एक दूसरे से सामेदारी में कोई मकाबट नहीं मानने का नतीजा है—मगा-अमुनी संस्कृति । और रकाबट खड़ी करने की मुहिम का नतीजा है—रामज मभूमि और आबरी मस्जिद का बबानेजान । बस, दूध में काजी का पड़ना हो गया । वही तो हिंदू और मुसलमान की सामेदारी बनते ही रामज मभूमि के पक्ष में मुसलमान लड़े पाये जाते और आबरी मस्जिद के पक्ष में हिंदू । दोनों के सिफ इस सोच में पहुँचने की दर थी कि झगडा खड़ा नहीं रखना, किसी हाल में जहर घुलने नहीं देना है । बंदर और बंदर के झगडे में आखिर आखिर बंदरी को ही लहू लुहान होना है । मदारी को नहीं ।—बस, इतनी सी समझदारी ने हिंदू मुसलमान की सामेदारी को फिर दोआवे की हरिमाती में बदल दिया । दोनों को धिक्कार कि भकट सग्राम की मारामारी में मर्तन हैं ।

अब जरा फिर इस प्रसंग पर आये कि मजहब और मुत्ब की आत्मी की जिन्गी में भूमिका क्या है । हम आप को हजार ऐसे लोगों को गिना देंगे जो न सनातन धर्म के मुरीद, और न ही इस्लाम या इसाईयत के पुजारी, लेकिन फिर भी न सिफ इतना कि बाकायद धार्मिक निहायत इमानदार, शरीफ नेकवरत इमान के रूप में बतमान होंगे । हम आप को धर्म या मजहब के बिना जितने लोगों को हजारों लाखों की संख्या में दिखा देंगे और आप हृदय सिफ एक आदमी दिखा दीजिये, जो कि हुवा पानी और मिट्टी के बिना जितना हो !

जो हाँ, हम बिल्कुल यही धज करना चाहेंगे कि आदमी का

बुनियादी आधार मिट्टी हवा पानी और कुदरत है—मजहब इन सबसे घाब की चीज है और अगर यह आदमी के मिट्टी हवा पानी की तासीर को और बेहतर समझने, या आदमी को आदमी का बनाने के काम आने वाला नहीं, तो न सिर्फ यह कि ऐसा मजहब किसी काम की चीज नहीं, बल्कि बेहूदा और खतरनाक चीज है।

सगे हाथो, इसी सिलसिले में, अब हम एक उस बात का जिक्र करना चाहेंगे जिसे हम हिंदू और मुसलमान के बीच का एक महम मसला मानते हैं। क्या मतलब होता है मिट्टी हवा पानी और कुदरत की आभा और क्या घम और मजहब के अघाकुष्य का, यह समीज नहीं होन से ही हमें हिंदू और मुसलमान मामले के इस सबसे प्रासंगिक पहलू की भी कोई समीज नहीं कि मजहबी कठमुत्लापन शहरों में ही ज्यादा क्यों है? हिंदू-मुस्लिम दंगों की जहनुमी आग शहरों में सीनी में ही क्यों ज्यादा घघकती रहती है, गावों में क्यों नहीं? और यह सवाल मई 1987 के मेरठ दंगों के बाद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि इन दंगों में शहरों का जहनुम गावों की सरहदों तक भी पैर पसारता साफ नजर आया है।

इसलिए, हिंदू मुसलमान के मामले में, हमें यह सवाल भी आखिर आखिर उठाना ही होगा कि क्या बजह है, जो कि कट्टर-पथी हिंदू और कठमुल्ले मुसलमानों का डेरा ज्यादातर शहरों में ही पाया जाता है, गावों में नहीं? 1947 के विभाजन की त्रासदी इतनी जल्दी भुला देने की चीज नहीं। चार लाख से ज्यादा लोगों का बल और करोड़ों के बेघर बेआसरा ही जान का हादसा इतनी छोटी चीज नहीं। हमारा तय्यकथित राष्ट्रीय नेतृत्व अब सिर्फ 1947 के भण्डे फहराने की घटना की याद दिलाना चाहता है हमें। उस महाविनाश का वह कोई हवासा नहीं देना चाहता, जिसमें लाखों करोड़ों निर्दोष हिंदू मुसलमानों को कत्लेआम के बाले तूफानों का आखेट बना दिया गया। हमारी सरकार हमें यह याद दिलाना

नहीं पसंद करती कि वह शहर और गांव, दोनों मुकामों पर घमां घटा और मजहबी जनून के आग के दरिया के फैल जाने का नतीजा था। न ही तथाकथित विपसी पार्टियों को फिर है कि लोगों को आगाह नहीं करना ही घोषे की राजनीति खेलना है। लेकिन हिंदू और मुसलमानों को अपनी खैर चाहिये हो, तो उनको इतना सबसे पहले और सबसे ज्यादा याद रखना होगा कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम दंगों की आग का दरिया फिर शहरों की हड्डें तोड़कर गांवों तक जा पहुँचा, दुबारा वही सन् 47 हिंदू के सामने भी होगा — और मुसलमान के सामने भी।

‘देश का विभाजन हमारी लाशों पर होगा!’ का अभयदान बूझने वाले राजनीतिक नेताओं की जात अभी बरकरार है। और हम सभी जानते हैं कि उनकी बात पूरी तरह सच निकली। देश का बटवारा लाशों के बीच हो हुआ—लाशों लाशों के ढेरों के बीच—मगर इन लाशों में अंग्रेजों के विरासतदार अभयदानियों में से किसी की लाश नहीं थी। यहाँ तक कि मदात्मा गाँधी की भी नहीं। इतिहास के इस सच को भुलाने पर हम फिर कभी न कभी उसी मुकाम पर फिर घुमते खड़े होंगे। वही सन् 1947 हमारे सिर पर फिर काल की तरह मढ़ा रहा होगा और इसकीसवीं सदी में पहुँच चुके होने का मुगलता तब हमारे किसी काम आयेगा नहीं।

हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत को पचाते जाने का अजाम वहाँ तक जा सकता है, इस सवाल से बेखबर रहना या रहना, दोनों खतरनाक हैं। भारत के भारत होने से बच रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है—हिंदू के मुसलमान और मुसलमान के हिंदू का होकर रहने का रास्ता। — कहना जरूरी नहीं कि सिखों और ईसाइयों की भी सामीप्य का सवाल इसी एक बड़े सवाल में जजब है। क्योंकि अहम सवाल भारत को नाना घमों और रीति रिवाजों की रंगारंग टा में देखने की आवाजा का है। इस समझदारी का है कि नाना

धर्मों और रीति रिवाजों की सांझीदारी ही सांप्रदायिक मारामारी के सिलसिले को रोक सकेगी। जो हिंदू मुसलमान, वह उतना ही सिख और ईसाइयो पारसियों का भी होगा। यही कंफियत मुसलमान की होगी। एक देश में नाना जातियो-धर्मों की सांझीदारी से ही भारत भारतीय सस्कृति का दावेदार बना है, यह तमीज ही हमें मजहब और मुल्क को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा नहीं करने की समझदार में भी ले जायेगी। और तब हम इस सवाल में और ज्यादा गहराई से जा सकेंगे कि सारे धार्मिक मजहबी जहरबाद के बड़े शहरों में ही क्यों और किस तरह कायम हैं। और कि शहरों के इन देश द्रोही बड़ों को अगर बाकायदे पनाह मिल रही है, तो आखिर कहीं से, और क्यों मिल रही है ?

भारतीयता का तक देश की मिट्टी का तक पहलू है, मजहब और जाति का, बहुत बाद में। जिसमें भारत की मिट्टी बोलती हो, वही असली हिंदू, यानी हिंदुस्तानी है। जिसमें सिर्फ मजहब या धर्म के उल्लू बोलते हो, वह हरहाल में देशद्रोही है—फिर वह चाहे हिंदू हो कि मुसलमान, सिख हो कि ईसाई पारसी। हिंदू और मुसलमान में जब-जब सांझीदारी हुई, इसी तमीज के सहित हुई है।

मिट्टी—दूसरे शब्दों में कहे, तो देश—पर सबसे पहला हक उसका है, जिसका उसकी मिट्टी से नादात्म्य हो। जिसे उसमें मा का सा रूप भिन्नमिलाता दिखायी पड़ता हो। जो उसे खुद की पैदाइश और परवरिश की भूमि के तौर पर देखता हो। जो इस बात पर ईमान लाता हो कि एक ही घरती की कोख से निकले हुआ में चू कि मिट्टी हवा पानी और आकाश तथा अग्नि की विकदार का अलग-अलग होना मुमकिन नहीं, इसलिए दूध और खून में भी जो फल होगा, वह एव की आन का दुश्मन दूसरे को बनाने वाला जहर तो हगिज नहीं होगा।

जो मिट्टी का नहीं हुआ, वह किसी का नहीं हो सकता।

मिट्टी हिन्दू मुसलमान ही नहीं, इमान मात्र के लिए अपना मुँह एक तमान खोलती है। पृथ्वी माता है और हम उसकी ससति, इतना जिसकी समझ में आ गया उसे इतना समझने क्यों देर लगनी है कि हिन्दू मुसलमान का कैसे हो सकता है और मुसलमान हिन्दू का।

मिट्टी की तालीर को समझने वाला ही मजहब और धर्म की जड़ों तक की पहुँच सकता है। जिसकी ऊँट मिट्टी में नहीं, मजहब में होना तामुमकिन है।



सवाल का हक

कभी कभी भारत सरकार अचानक कोई नैतिक भटका देती है। धर्माचार्यों तक तो ठीक, लेकिन कई बार साहित्याचार्यों को भी दूरदर्शन के रूपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने, इतना पुनः तो वह कमा ही लेती है कि हम राष्ट्र की वेदना को स्वयं उसके वाणीपुत्रों के श्रीमुख से सुन सकें। — अभी कुछ समय पहले हिंदी के अज्ञातशत्रु साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी को आतंकवाद के विरुद्ध बोलते देखा, तो ध्यान लगाकर सुनना जरूरी हुआ। साहित्यकारों के बीच विष्णु जी की छवि लगभग कबीर की चदरिया मानी जाती है। उनसे गलतफहमी की बात सोचना बुरा है। वो सरकार के पक्ष में झूठ बोलेंगे, इसकी कल्पना भी कष्टप्रद ही हो सकती है क्योंकि विष्णु जी जितना सादगी, उतने ही सचाई के लिये भी जाने जाते हैं। — लेकिन 'काजल की कोठरी में कैसे हूँ समानो जावे' मुहावरा कहाँ जायेगा ?

स्पष्ट है कि 'दूरदर्शन—समाचार' में विष्णु जी के वयान का उतना ही अर्थ प्रसारित किया गया, जितने से वास्तविकता का एक ही छोर प्रकट हो— यानी अद्वैत ! उनके प्रसारित वक्तव्य का कुल सार इतना कि— देश में अचानक जो आतंकवाद का सिलसिला चल

पडा है, यह कितना अमानवीय और अराष्ट्रीय है। — और कि इस उद्देश्यहीन मार काट से राष्ट्र और समाज की कितनी बड़ी क्षति हो रही है। — संवेदनशील लोगों के हृदय कैसे विदीर्ण हो रहे हैं। हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा नहीं। प्रतिहिंसा की जगह प्रेम उपजे, सभी आतंकवाद की समस्या हल होनी है।

ऊपरी तौर पर देखिये, तो वास्तव्य अपने में पूरा, लेकिन गहराई में जाइये, तो आधा सच है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ध्वनि है कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवादियों के छोर पर है, सरकार के छोर पर नहीं। इस तथ्य से विष्णु जी भी अवगत हैं कि कदाचिद् 'दूरदर्शन' का माध्यम खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथों में होता, तो वो भी खुद के कारनामों को तो घमण्ड और सिख अस्मिता की सरक्षा का दर्जा देते — भारत सरकार के बारे में बताते कि वह पुलिस तथा फौजी आतंकवाद मचाये हुए है। — यानी वो भी वास्तविकता का सिर्फ एक ही छोर सामने रखते, क्योंकि झूठ उसकी नियति है, जिसका चरित्र दोमुंहा हो। लेकिन सवाल यहाँ भारत जैसे विशाल देश की केन्द्रीय सरकार के चरित्र का है।

जब तक यह न बताया जाए कि आतंकवाद के बुनियादी कारण क्या हैं उसकी वास्तविक जड़ें कहाँ हैं और कि इन्हें निमूल कैसे किया जा सकता है, तब तक सिर्फ इतना बताने से क्या होगा कि आतंकवाद से पूरे देश को खतरा है? इतना तो हम नितांत सामान्य बुद्धि के लोग भी बिनाकुल देख और समझ रहे हैं कि आतंकवाद कैसे हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में जहर धोस रहा है। आतंकवाद अमानवीय है और इसकी खबरता न जाने कितने घरों में सनाटा कायम कर चुकी, यह सब भी छुप की तरह उजागर है। — लेकिन यह बात अभी भी पूरी तरह साफ नहीं कि आतंकवाद की बुनियाद कहाँ है। और कि इसमें कितनी भूमिका अमेरिका ब्रिटेन-पाकिस्तान

मे पालथी मारे भारत को तोड़ने की साजिश मे लगे तत्वों की है — और कितनी खुद धम, जाति और राजनीति की तीन पत्ती का खेल खेलने वाली भारत सरकार की ? यह सब स्पष्ट हुए बिना कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है ?

विष्णु जी नहीं जानते, ऐसी बात नहीं । सोच विचार के भरोसे खुले रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वास्तविकता क्या है और इसके निदान की शक्तें क्या हैं । देश और समाज के सवालो मे रुचि, और ऐसी चिंता, रखने वाले किसी सामान्य व्यक्ति से बातें करके देखिये, जिसके कि कुछ खुद के प्रबन्ध न हो । वह उस सारी हकीकत को बयान कर देगा, जिसे छिपाते छिपाते सरकार की हथेलियों मे गड़बड़े पड़ गये हैं । सवाल सिर्फ तथ्यों को राष्ट्रीय — सामाजिक सदमों से जोड़कर, सकट के दोनों छोरों को गौचर बना देने का है, जिसमें विष्णु जी पूरी तरह सक्षम है । ज़रूरत उनसे राष्ट्रहित मे पूरा बयान मांगने और उसे ज्यों-का त्यों हमारे सामने रखने की थी । सरकार ने ऐसा नहीं किया । उसने सिर्फ खुद के मतलब भर का सामने रखा । अगर विष्णु जी ने कहा होता कि दोषी सिर्फ आतंकवादी हैं, सरकार तो आतंकवाद के निदान मे पूरी ईमानदारी से जुटी है, उसके आखरण मे वही कोई गड़बड़ नहीं, तो दूरदर्शन, दूसरी खबरों में कुछ बटौती करके भी, इस बात को ज़रूर प्रसारित करता । स्पष्ट है कि विष्णु जी ने नहीं कहा कि समस्या का सिर्फ एक छोर है और सरकार इस मामले मे कतई दोषी नहीं । लेकिन मतलब भर का प्रसारित करके सरकार ने दिखाया यही कि विष्णु जी जसे मूर्ख-य साहित्यकार भी मानते हैं कि ज्यादाती सरकारी छोर पर वही नहीं है । और कि सरकारी आतंकवाद का मतलब आतंकवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अक्षमता होता है ।

हमे शिकायत इसलिए हुई कि राष्ट्र के मूर्ख य बाणीपुत्रों का बयान आधा अधूरा और प्रसंग से कटा प्रसारित हो, इससे कहीं

अच्छा हो कि ये चुप रहें। क्योंकि हमारे लेखे लेखक के मुख के किसी छोटे से कोने का खुलकर घट हो जाना ठीक नहीं। हम तो यही मानते चले हैं कि आदमी और समाज की बिल्कुल भीतरी भिलमिल को भी अगर कोई बार से पार तक मूल्य कर सकता है, तो वही, क्योंकि सचाइयो को समाज की छाती से कान सटाकर सुनने को जितनी गहरी जरूरत उसे हुआ करती है, किसी और को नहीं। उसका सारा ताम भ्राम ही ध्रुति पर टिका है। हमसे सुनकर ही तो लिखता आया है वह, हमारे जीवन के तमाम स्पर्दनों को। और इतनी प्रामाणिकता के साथ कि जाने किननी बार हम चकित कर डाला है, इस बात से कि हमारा दुःख सुख, राग विराग और लड़ाई झगडा हमसे बेहतर उसने कैसे सुन लिया? ऐसे में, उसके मह को चिड़िया की चाब से भी कम खुलते देखकर, हम गद्दी, तो क्या उन लोगों को भटका लेंगे, जो फिल्मी किन्नरों के भोठे जिंदा डांस दिखाने के लिए तो रोज मनचाहा समय निकाल सकते हैं लेकिन विष्णु जी सरीसे मनीषी जनो को दस पांच मिनट भी नहीं दे सकते कि वो राष्ट्रीय सफ्ट के प्रसंग पर पूरी बात बता सकें?

एक अश समाचार में, पूरा वस्तव्य असंग से प्रसारित होता, सब शर्का की गुंजाइश नहीं होती। ऐसा न होने का सवाल स्वाभाविक है कि क्या विष्णु जी ने सचमुच इतना ही बताना चाहा था, जितना कि आज कोई अघा-बहुरा भी बता सकता है? सवाल आदमी का बुनियादी हक है। अगर यह हक उस नहीं, तो बाकी मारे एक मिट्टी हैं। लोकतन्त्र की हजार खामियों के बाद की नियामत यही है—सवाल करने का हक। इस हक के खत्म होते ही लोकतन्त्र भी खत्म हो जाता है। फिलहाल विष्णु जी से हम सिर्फ इतना ही सवाल करना चाहेंगे कि उन्होंने सरकार को यह मोका क्यों दिया कि वह उन्हें दस पांच सेकण्ड खुद के पण्डे की शक्ल में प्रस्तुत करके, तुरंत बस्ता समेट ले?

अब फिर कहना चाहेंगे कि हर वस्तु के दो छोर हैं और आदमी

का धम है कि मुह खोले, तो दोनों छोर सामने दिखाने के इरादे में ही। इस इरादे के बिना उसकी कंती भी विद्वत्ता, सदाशयता, चाकि-सिद्धि का कोई मतलब नहीं। एक छोर अधेर में है, तो दूसरे के उजाले में होने की कोई प्रासंगिकता नहीं। तुरताफुरती में एक ही छोर दखें, तो रावण भी महापानी है और राम कवणा से दूर। अगर कोई कहे कि उसे तो अभी सिफ एक ही छोर पता है, तो पूछना जरूरी होगा कि इतना ही बताने की ऐसी जरूरत क्या आ पड़ी ?

सरकार और खालिस्तानवादियों के मामले में वास्तविकता यह है कि दोनों मुछोटा लगाये हैं। दोनों का माधन झूठ है। सरकार अपना रूप आतंकवाद मिटाने की कृतसकल्प कवणानिधान का निका नना चाहती है और गांधी बुद्ध-ईसा की अहिंसा की दुहाइ देते नहीं सकती। जबकि सरकार से ज्यादा किसे पत है कि आतंकवाद खुद उसकी बोयी-गोडी निराई फसल के सिवा कुछ नहीं। साम्प्रदायिकता और धर्मों माद के हुक्के इसी चौधरी के घोपाल में ज्यादा गुडगुडान रहे हैं। आज भी स्थिति क्या है ? कस भी जघम हत्याकांड, डाक लूट, बलात्कार और जोर जुल्म आतंकवाद नहीं, अगर इनसे सत्ता की दीवारों पर खरोंच नहीं पड़ती हो। आतंकवादी तो सिफ वो ह, जो तल्ल के पायो में छेद करना चाहते हो। कौन नहीं जानता कि पंजाब का जंगल में की जाग की तरह घू घू करता आतंकवाद सत्ता के आतंकवाद की ही समांतर सृष्टि है और इसे पहले सत्ता के चरित्र में से दूर होना है, तब बाहर। सरकार आतंकवाद के पूरे देश में पसरे सामाजिक आर्थिक कारणों पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि इससे छुद की पोल उघड़ती है। वह इस रहस्य को जग जाहिर नहीं होने देना चाहती कि आतंकवाद का डोया सामान्य लोगों के जीवन सघर्षों की दबाने का एक हथियार बन चुका है।

जो देश को टुकड़ों में बांटना चाहते और इसी इरादे में आतंक

बाद मचाये हैं, उनके विरुद्ध ज़ोर बाधवाही जरूरी है। इन्हें बशरना राष्ट्र को सकट में डालना है। लेकिन अपने पापकर्मों का मोक्ष सिद्ध करने में सैन्य या पुलिस बलों का उपयोग सत्ता के आतंक की जमीन तैयार करता है और सत्ता के चरित्र में गिरावट आते ही उसके तमाम अंगों के नैतिक तंतु जबर पड़ने शुरू हो जाते हैं। साम्प्रदायिक दंगों की आद में राजनीतिक-सामाजिक सबूतों को किनार रखने की कूटनीति आखिर दंगवातियों की ही माँ बाप की नानी याद दिलायेगी—देश के दुश्मनों को नहीं।

आतंकवादियों की जमात एक नहीं। एक तरफ सरकारी सरक्षण प्राप्त आतंकवाद है, दूसरी तरफ सरकारविरोधी। इतना जरूर कि सरकारी सरक्षण प्राप्त आतंकवादियों की गतिविधियाँ समाज की लूट-खसोट तक सीमित हैं, लेकिन सरकारविरोधी आतंकवादियों की टोलियाँ खालिस्तान-गोरखालैंड की सरहदें टटोल रही हैं। इनमें भी फक है। एक तरफ 'ब्लूस्टार आपरेशन' और दिल्ली-जमशेदपुर कानपुर के कलेआमा से सतुलन खो बैठे लोग हैं, दूसरी तरफ खालिस्तान के मसूबेदार। इन दोनों से समान बर्ताव ठीक नहीं। पहलों की वेदना सुनने, उन्हें भरोसा बंधाने और उनके सुसंगत धार्यों पर सवेदना का शीतल मलहम लगाना जरूरी है और जिन्हें खालिस्तान चाहिये, आलिस्तान के सिवा कुछ नहीं चाहिये, उनसे पूरी सख्ती में निबटना। जिन पेशेवर आतंकवादियों का मुसोटा 'ब्लूस्टार आपरेशन' और दिल्ली जमशेदपुर, कानपुर के कलेआमों का बदला लेने वाले शहीदी जत्थों का है, लेकिन इरान खालिस्तान का, उन्हें कुचलना जरूरी है। जिन्हें कोई फिक्र नहीं कि इनके काले कारनामों ने खुद विश्व समाज की कितनी क्षति हो रही है। देखें तो विश्व समाज की साक्ष को सबसे ज्यादा इन पेशेवर आतंकवादियों ने ही नष्ट किया है। इन्हें यह भी चेत नहीं कि खालिस्तान की बात करना ही सरकारी दमनचक्र की नैतिक आठार देना है।

पंजाब के आतंकवाद से निबटने का एक ही रास्ता है—हिंदू-सिखों की अटूट एकता और इसी पर चारों तरफ से चोट पड़ रही है। इस पुल के टूटने पर ही देश टूटेगा। खालिस्तानवादी-उग्रपंथियों की वंसी भी उत्तेजक कायवाहियों के जवाब में साम्प्रदायिक एकता के बोझ में कोई दरार नहीं आने देना, रास्ता इसके सिवा कोई नहीं। सवाल सिर्फ व्यवहार का है और इसके लिए जरूरत है, सच्चाई की। विष्णु प्रभाकर जी जैसे मूढ़ या साहित्यकारों को पूरी बात कहने से रोकना, सच्चाई का रास्ता बन्द करना है।

थोड़े में कहें, तो सच्चाई पर पाबंदी लगाना ही लोकतंत्र के रास्ते बन्द करना है। लोकतंत्र सवालियों का तंत्र है और झूठे जवाबों की एक हद्द होती है और इस हद्द से आगे अनहद्द नहीं, सानाशाही के कपाट खुलते हैं। क्या हम सम्मति करें कि भारत सरकार दूरदर्शन पर विष्णु जी जैसे साहित्यकारों के पूरे वक्तव्य सामने आने देंगी—खुद अपने ही हक में ?



झूठो को नैया

मनचाहा राष्ट्रपति मिल गया होने के आनन्द में प्रधानमन्त्री ने एक बात काफ़ी हृदय तक मचकह दी। अपने एक दूरदर्शनी प्रवचन में प्रधानमन्त्री ने पूरे उत्साह और सकल्प में कहा कि वो देखेंगे कि कितने देश को गांधीजी के रास्ते पर (और भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के गरीबा को उनके मौजूदा हासत से आगे) ले जाया जा सकता है। शायद, पहली बार दोटूक कहा उ होने कि देश का आर्थिक आजादी नहीं मिली है। आवश्यक कि हम प्रसंग में उठाने पण्डित नेहरू या श्रीमती गांधी नहीं, बल्कि महात्मा गांधी का नाम लिया।

जोहिर है कि प्रधानमन्त्री ने हमें उताना और भरसा बंधाना चाहा कि देश को राजनैतिक आजादी मिलाएँ तो भूमिका मोहनदास करमचन्द गांधी का भी आर्थिक आजादी दिलाने में राजीव गांधी की होगी।—यानी कि जिस सम्पूर्ण स्वाधीनता का हम सपना ही देखते रह गये, उसके पूरा होने की घड़ी (इक्कीसवीं सदी) नजदीक आती जा रही है।—हालांकि प्रधानमन्त्री के 'हम देखेंगे' में एक चेतावनी यह जरूर छिपी मौजूम पड़ती है कि आर्थिक आजादी के सपने को पूरा होने के बिना बरबरी होगा कि राजीव भी हमें इक्कीसवीं सदी में

भी वही दिखाई पड़े, जहाँ आज हैं। यो विनोद मे हम कह सकते हैं कि इसका मतलब तो हुआ कि देश और हम तो आगे निकल चुकें होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पिछड़े रह जायेंगे। —लेकिन असली सवाल यह नहीं। असली सवाल है यह कि जब आर्थिक आजागी नहीं मिली होने की हकीकत से इन्कार नहीं, तो यह दावा क्यों है कि राजनैतिक आजादी मिली।

पद की झंझाई के कारण प्रधानमंत्री हमसे बहुत ज्योंही देखते हैं और हर बात को देखते हैं, माँ बाप की नानी तक को, मगर इतना तो हम भी जरूर देखेंगे कि कि क्या यह अजूबा सचमुच सम्भव है? क्या आजादी के सचमुच अलग अलग हिस्से होते हैं केंचुए के टुकड़ों की तरह? आर्थिक आजादी नहीं भी हो, तो राजनैतिक आजादी मौजूद हो सकती है, राजनैतिक नहीं हो, तो आर्थिक आजादी? ऐस ही सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, वैचारिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक आजादियाँ में से कोई एक। जबकि केंचुए के टुकड़ों को केंचुआ नहीं, उसके टुकड़े ही माना जाता है? तो क्या प्रधानमंत्री अपनी अपार खुशियों की घड़ी में सचमुच इस सच्चाई को स्वीकार करने की पहल करना चाहते हैं कि हमें आजादी नहीं, बल्कि उसका केंचुए के टुकड़ों की तरह का एक टुकड़ा भर मिला है? और इसीलिए बनी हुई है आज भी हमारी मानसिकता टुकड़खोरो की? भाषा, शिक्षा संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सामाजिक-आर्थिक नीति नियोजन और प्रशासनिक ढाँचा—किसमें टुकड़ाखोर नहीं हैं हम?

सदियों की गुलामी के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्वाधीन देशों के समकक्ष आन में वक्त लगना स्वाभाविक था, क्योंकि साम्राज्यवाद में उपनिवेशों को ज्ञान विज्ञान का भी 'उपकद्र' ही रखा जाता है, लेकिन क्या उन क्षेत्रों में हमने एक स्वाधीन देश के अनुरूप स्वतंत्र

नोनियाँ बनाई, जहाँ कि ऐसा बिल्कुल सम्भव था ? मंगलन भापा, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक नीति नियोजन और प्रशासनिक ढाँचे में वही झलक दिखाई पड़ती है कि हमें स्वाधीन हुए चार दशक बीत गये ? — जबकि इन्हीं चार दशकों में परमाणु बमों की मार से स्वतः छोटा-सा मुल्क जापान कहा का-कहा पहुँच गया। इजराइल तुर्की-जन विज्ञान भर के मुल्कों ने अपनी स्वतन्त्र भाषा, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी कर ली—लेकिन महादेश भारत आज भी हर क्षेत्र में अंग्रेज आकाओं की नकल में मस्त है । - और हमारे वर्तमान प्रधान-मन्त्री जी हमें समझा रहे हैं कि राजनैतिक आजादी मोहनदास कमचंद गांधी दे गया था, आर्थिक आजादी ये पकड़ाने जा रहे हैं । भारत-जैसे महादेश के प्रधानमन्त्री को अगर इतना भी पता नहीं हो कि आजादी किस धिड़िया का नाम है तो इसे पूरे राष्ट्र के लिए एक जमाना हादसे के सिवा और क्या कहा जा सकता है ।

माम अरुन लिया चाहोने, लेकिन जरा यह भी देख लेते कि मोहनदास कमचंद गांधी राष्ट्र की भाषा के बिना आजादी को अधूरा मानते थे, तो इसकी वजह थी । तक बिल्कुल दिया जा सकता है कि जब भागते भूत की लँगोटी से भी सतोष करने का मुँहावरा मौजूद है तो भागते मोरो से अधूरी आजादी पा जाने में क्या बुरा रहा ? लेकिन पहली बात यह कि भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भूत की लुगी नहीं था कि दो टुकड़ों में चीरकर एक हमें थमा दिया गया, तो 'जय है जय है ।' गाने के सिवा और कुछ सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं रही । हमारे अधूरी आजादी लेने और पूरी स्वाधीनता को ठोकर मार कर, अधूरी आजादी को बचूस करने में फक है । इससे भी आगे, हमन न सिर्फ यह कि अधूरी आजादी को स्वीकार किया बल्कि पिछले पचास साल इसे अधूरा ही रखने में खपा दिये । अब यह आधी अधूरी भी घपले में है ।

प्रधानमन्त्री का एक था कि जो देख रहे हैं कि विकसित देश परी

मुल्कों को आर्थिक गुलामी में जकड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उन्हें मित्रों का एक ही पहलू क्यों दिखाई दे रहा है? जब आर्थिक आजादी न होने की सच्चाई उन्हें स्वीकार है, तब राजनैतिक आजादी के भी नहीं होने से इन्कार क्यों? सब इस सच से परहेज क्यों कि हम आर्थिक ही नहीं, बल्कि राजनैतिक स्तर पर भी विकसित देशों की गुलामी ही डो रहे हैं? इसलिये नहीं कि कोई और रास्ता नहीं, बल्कि इस पूरे इरादे में कि देश की राजनैतिक आजादी उसकी आर्थिक आजादी से अलग चीज नहीं। प्रधानमन्त्री जिस राजनैतिक प्रतिष्ठान का नुमाइश हैं, उसके ठेकेदारों को इतना बिल्कुल पता है कि देश का राजनैतिक स्तर पर आजाद होते ही उनका आर्थिक साम्राज्य और प्रभुत्ता का किला भी मिट्टी में मिल जायेगा। क्या प्रधानमन्त्री महोदय की सच मुच पता नहीं कि जब भी कोई देश स्वाधीन होता है राजनैतिक स्तर पर आजाद होकर, आर्थिक तौर पर दवा में गही लटक जाता। कोई भी या तो स्वाधीन होता है, या गुलाम। अलबत्ता कुछ बाधाएँ या कुछ सहूलियतें होने की बात जरूर की जा सकती है, लेकिन कुछ बाधाएँ होने से न तो स्वाधीन गुलाम बन जाता है और न कुछ सहूलियतें होने से गुलाम स्वतंत्र।

गरीब मुल्क होने का मतलब गुलाम मुल्क होना नहीं होता। अमीरी स्वाधीनता की गारंटी नहीं। न गरीबी गुलामी का पर्याय है। जो चरित्र, वही चरितार्थ में गुलाम होते हैं। प्रधानमन्त्री इस दुखती रंग पर हाथ नहीं रखना चाहते कि हमारा चरित्र क्या है, क्योंकि इसी से जुड़ा है उनके खुद के चरित्र का सवाल भी। वो क्या हमें बतायेंगे कि आर्थिक आजादी न होने की वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देश की गरीबी या व्यवस्था का साम्राज्यवादी चरित्र? भारत जैसे अकूत ससाधनों वाले देश में अमीरी के ठाठ उत्पन्न कर रहे 'मल्टीनेशनल्स' की अपरिहायता गरीब मुल्क में क्यों? अपने समाधनों और जरूरतों के हिसाब से आर्थिक नियोजन से कौन

रोक रहा है हमें ? एक तरफ भारत ही नहीं, दुनिया भर के गरीबों के उद्धार की हातिमताई सतरानियाँ—दूसरी तरफ अंग्रेजी के ऐसे मठों के प्रसार पर ब्रिटिश हुनमरानों से भी ज्यादा जोर, जो देश की कम से कम पिछाने-वे प्रतिशत जनता को अघरे में रख सके—इस दोमुँहे खरित्र के लिए कौन बाध्य कर रहा है, हमारे गरीबपरवर प्रधानमंत्री को ? देश की गरीब जनता, या कि देश को देख खाने पर तुले पूँजी पतियों का आर्थिक, राजनैतिक मायाजाल ? पाकिस्तान लका के माँ बाप अमरिका को उसकी नानी याद करवा देने की ताकत जिसके फौलाने हाथों में हो, वही महाशक्तिमान सुपरमैन' क्यों रोता फिरे कि अमरिका हमारी आर्थिक आजादी काटे में फसाये बठा है ? और क्या सिर्फ आर्थिक ही ? राजनैतिक आजादी को नहीं ? प्रधानमंत्री देंगे कोई उगाहरण किसी ऐसे व्यक्ति, समाज या देश का, जो राजनैतिक स्तर पर तो आजाद हो, लेकिन आर्थिक तौर पर गुलाम ?

साफ है कि प्रधानमंत्री हिंद महासागर में झूठ की नया चला रहे हैं । देखने वाले जरूर देखेंगे कि यह दोमुँही नाव कहाँ तक टिकती है, लेकिन इतना तो हम अभी भी देख रहे हैं कि जब तक देश की राजनीति में यह नया चल रही है भारत क्या, हिंद महासागर की भी खर नहीं ।

राजनैतिक आजादी और आर्थिक आजादी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । इनमें से एक ही पहलू का चलाना खाटा सिक्का यानी झूठ चलाना है । जहाँ इनके की चोट पर सफेद झूठ चलाया जा सकता है, उस मुल्क की आजादी को सिवा इसके क्या कहें कि—नया चली जाय रे, सफेद झूठी की नया, चली जाय रे ।

लोकतंत्र के दरबार

१९४७ को सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद नहीं, बल्कि सदियों लम्बी मानसिक वंचारिक दासता से भी मुक्ति का वचन कहा गया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के कथनानुसार भारतीय जनता की सम्प्रभुता का वचन ! सिर्फ राजतंत्र नहीं, लोक की सम्प्रभुता का वचन !

कांग्रेस का सबसे पहला, और सबसे मुख्य दावा था—देश को 'नोकुत' न दे रहे होने का। यानी राजशाही की जगह, लोकशाही। राज्य की निरंकुशता की जगह, सामान्य जनता की सम्प्रभुता। गोरानाही और लाटसानाही के दमनचक्र तथा दासता की फटकारों से मुक्ति, यानी साम्राज्यवाद का अंत, समाजवाद का अभ्युदय !

स्वाधीनता के अहोरात्र के उस दौर में जनता को ही सर्वोच्च सत्ता माना गया। अफसरशाही ही नहीं, बल्कि सैन्य-पुलिसबलों पर भी जनप्रतिनिधित्व का बचस्व घोषित हुआ। जिसे जनता ने संविधान का युग बरार दिया गया, यानी माना गया कि मारे विधि विधान जनता की सम्प्रभुता को के दम रूखकर तब होंगे, और राज्य की भूमिका जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की आकांक्षाओं का प्रशासन देन की होगी, देश की जनता पर

वर्गीय सवारी गाठने की नहीं। जनहित के प्रत्येक सवाल के प्रति कल्याणकारी राज्य की विधायिका, न्यायपालिका और 'न्यायपालिका की नियेणी सतत जागरूक और नायनीस रहेगी। छोटे शर्मा में, जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनेगी। तब माना गया कि प्रभुसत्ताधन के तैयारशुदा (रेडीमेड) हाकिम दृक्कामों का इस देश में अब कोई बज्रूद नहीं रहा। आसीजाहो, हुजुरो और मीसाहों का जमाता सद गया। अब भारत के सामान्य जन मासिकों की मर्जी के मोहताज नहीं रहे। उनकी स्थिति अब भारत माग्य विधायक' गणा की हो गयी। भारत की जनता के लिए सुबह सुबह 'यशस्वी रहें, हे प्रभो हे मुरारे, बिरजीव राजा व रानी हमारे।' प्राथमा गा गावर अपन गात समुंदर पार के आकाओ का दीन हीन गुलाम होन का स्मृत देने का शमनाश दीर सत्तम हुआ और 'अय ह, जय हे, जय हे।' व तुमुल नाद-निनाद के साथ स्वयं की स्वाधीनता, स्वायत्तता और सम्प्रभुता का तिरगा पहरा का स्वर्णयुग प्रारम्भ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ—विश्व के सबसे बड़े और महान गणतन्त्र का अभ्युदय।

स्पष्ट है कि यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं था। भारत का यह अपूर्व स्वाधीनता आंदोलन ब्रिटिश साम्राट साम्राज्य के विरुद्ध दशों राजा महाराजाओं या शहशाहो नवाबों का सत्ता सग्राम नहीं, बल्कि देश की सम्पूर्ण जनता के ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जज़ीरें तोड़ फेंकने के अथवा सघष का प्रतीक था। स्वाधीनता के इस राष्ट्र-यापी सघष का ही परिणाम था कि कांग्रेसी नेता और आठ म लड़े पूजीपति दोनों मानसिक वैचारिक तौर पर राष्ट्रिय दबावों में थे। वो जानते थे कि इस समय सम्प्रभुतासम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से कम की बात करना 'खोदा पहाड़, निकसी चुहिया' साबित करना होगा और जो जनाक्रोश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उमड़ा, इसके स्वदेशी प्रभुओं की तरफ रख करने के नतीजे हूँ में नहीं होय।

इसलिये 'धीमे धीमे, र मना, धीमे सब कुछ होय' की तज में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के औपनिवेशिक चरित्र का देशी संस्करण प्रकट करने में चार दशक लगा दिये गये। धीरे-धीरे लोकतन्त्रात्मक गणराज्य और जनता की सम्प्रभुता व ढपोरसखी उद्घोष तथा आलेख चरित्र की जगह, सवादे की शक्ल लेते गये और आज परिणाम सामने है।

विदेशी की जगह, स्वदेशी प्रभुओं की ठोकरो के हवाने हो रहन की यह आसदी दश के करोड़ों करोड़ सामान्यजनो की स्वाधीनता स्वाभिमान और सामाजिक अस्मिता को कंस मिट्टी में मिलाती गई है, इसके उदाहरण के लिए फिलहाल हम यहाँ सिर्फ एक ही दुःख उपस्थित करना पर्याप्त समझेंगे।

अभी कुछ समय पहले जिलाधिकारी महोदय के दरबार में हाजिरी लगाने की जरूरत हुई तो लगा कि शब्द का अर्थ के विपरीत चलाना सिवा घोलाघड़ी के कुछ नहीं। लोकतांत्रिक चेतना का चरित्र की जगह खाल पर जोर देने तक सीमित हो जाय, तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है 'जिलाधीश' की जगह 'जिलाधिकारी' शब्द का प्रयोग इसका एक फल त सबूत है। लगभग दो घण्टे की हाजिरी में देखा कि आस पास, दूर दराज के गावों, कस्बों के लोग झुण्ड के झण्ड दरबार में उपस्थित हो रहे हैं और जैसे ही अपने गहुंगा विधायक या अन्य किसी तत्सम नेता के साथ जिलाधीश महोदय के सामने पहुँचते हैं, इस महान् देश के महान् लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का यह 'अवगि देखिए, देखन जोगू' वाला परिदृश्य शुरू हो जाता है। सम्प्रभुतासम्पन्न जन गण 'माई बाप, गरीबपरवर, हुजूर मालिक' जैसे गणतन्त्रात्मक सम्बोधनों के साथ अपना दुखड़ा सुनाते और बीच बीच में 'मिहूरबानी किया जाय, हुजूर' रत्न करें, मालिक' की टेक लगाते धरणी में माथा नवाते जाते हैं और मालिक, गरीबपरवर तथा हुजूर जिलाधीश महोदय सामन्तो, मीलाहों

और राजा नवाबों की सी मुद्रा में भारत व दीन हीन जनघनों की लिजलिजी फरियादें सुन रहे होते हैं।

यह दृश्य कहीं एक जगह नहीं, पूरे राष्ट्र में व्याप्त है। स्पष्ट है कि जिलाधिकारी मात्र अधिकारी नहीं। उसकी स्थिति अपने ऊपर के सत्ताधीशों के लिये चाहे जो हो, लेकिन सामान्य जनता के लिए जिलाधीश की ही है। यह जिलाधीश का सिलसिला ही भारताधीश अधिनायकों तक जाता है।

इधर भंडों के भण्डों की शक्ति में अपने अपने जनप्रतिनिधियों, अर्थात् गडरियों के साथ दरबार में उपस्थित हुए जन गण अपने पहनावे, हाल-चल और शक्ल-सूरत में भी ठीक वही हैं, जो भाषा में। उनकी दीनता और दयनीयता भ्रूषा और भाषा, दोनों से टप-टप टपक रही है। उधर लोकसेवक जिलाधिकारी महोदय का दस्तबा-डासे बिल्कुल अलग है। देश की फटेहाल सम्प्रभुता 'टूजू', माई बाप गिडगिडा रही है और फटी-फर जनता के सेवक जिलाधीश महोदय 'सबसमयप्रभु' की तरह देखेंगे हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। आखिर हम ही तो देखना है।' के आश्वासन धमाते हुए भंडों को सुरक्षापुरतो में काठी से बाहर करवाते गडेरियों से बातों में व्यस्त हो जा रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और भाषा, दोनों में प्रभुता का आभा है। उह इतना कहने की जरूरत बिल्कुल अनुभव नहीं हो रही कि—यहां कोई राजा या नवाब साहब का दरबार नहीं लगा है। आप लोग मेरे कोई गुलाम, आसामी या भिलमगे नहीं एक सम्प्रभुतासम्पन्न लोकतन्त्र के स्वाधीन नागरिक हैं। आप लोगों का इस तरह की दयनीय और दबी सहमी भाषा में बोलना पूरे राष्ट्र के लिए शर्मनाक है। मेरी हैसियत सिवा एक ऐसे प्रणामनिक अधिकारी के और कुछ नहीं जिसको यही जिम्मेदारी है कि आप लोगों की समस्याओं को हल करें। मेरे प्रति आप लोगों के 'माई-बाप, चूत्र या गरीबपरवर जैसे दीनता और दासता में लिये सम्बोधन

निहायत ही शमनाक और दुःखद है ।'

स्पष्ट है कि किसी जिलाधीश को यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है । पूरा देश कालाशाही ने ज़िम्मे है । देश की जनता लोकतांत्रिकता का सबादा ओढ़े राजनैतिक भेडियो के हवाले है जिनकी निरकुश सत्ता देश की अधिसूच्य जनता की सवेदना स्वस्ति, सामाजिक जागरूकता राजनैतिक चेतना को चाटने पर ही टिकी है । जिन्होंने अपनी राजशाही का अफसरशाही से ऐसा राष्ट्रघाती तौंड जोड़ कर लिया है कि सामान्य जनता ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौर से भी ज्यादा दीन हीन हो चुकी है । उसमें एक स्वाधीन राष्ट्र का नागरिक होने की आभा पूरी तरह नदारद है । उसकी अस्मिता और आत्मा उसके फटे पुच्छे कपड़ों से भी ज्यादा खींचा हा चुकी है । उसे स्वाधीनता आज भी पुराणों की वस्तु है । उसमें अपनी दुदशा के सवाल उठाने की चेतना मूढ़ हो चुकी है । उसे अपने बोट के बदले में मिलने वाली बोटों और कम्बसों की कीमत ही बहुत है । उसमें इतना दम ही नहीं कि पूछ सके कि जनता की सम्प्रभुता के दावे वाले संविधान को महाप्रभुओं की भापा में तैयार क्यों किया गया है ? राष्ट्र का मुसोटा लगाये देश में एक भी राष्ट्रीय नीति बाखिर क्यों नहीं बनायी गयी ? महाप्रभुओं के लिए दून शेरबुड सेंट स्टोक्नो का इतजाम करके, हमें टाट पट्टियों का मोहताज क्यों रखा और ऐसी आतंककारी अफसरशाही के हवाले क्यों कर दिया गया है, जिसे 'हुजूर, माई बाप' पुकारते हुए हमारे घुटने काप रह हाते हैं ? क्योंकि इतना हम बखूबी जानते हैं कि हमारा सारा सुख चैन इनकी कृपा पर टिका है । इन लोकतंत्र का दरबार सजाये बैठे महामहिमों की कृपा पर ।

बहरहाल यहाँ हम विश्व का विशालतम लोकतंत्र होने के दावेदार भारत की सर्वधानिक प्रतिज्ञा उद्धृत कर रहे हैं । यह प्रतिज्ञा इस

प्रकार है—

‘हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोक-तन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बाधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारीख २७ नवम्बर, १९४६ ई० को एतद्वारा, इस सविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मोचित करते हैं।’

यह वष १९८७, यानी स्वाधीनता के चार दशकों के बाद का वष है। इस वष की भारतीय जनता का हुलिया जरा उपरोक्त प्रतिज्ञा से मिलाकर देख लिया जाय और तब हमें बताया जाय कि जिनके आस पास ही नहीं, बल्कि चरित्र में भी दोनता और दयनीयता की मक्खियां भिनभिना रही हैं—जो लोकतन्त्र के दरबार में आज भी ‘हुजूर माइ बाप’ ही गिड़गिड़ाने को बाध्य हैं—और कि जिनके भाग्य आज भी विघाता प्रभुओं की ठोहरों के ही मोहताज हैं—उन करोड़ों कराड़ मुसामों की स्वाधीनता का वष कब आयेगा ?

हमारे माननीय विधायक

पिछले कुछ अरसे में बंधुआ मुक्ति आ दोसन की चर्चा बहुत रही है। 'गरीबी हटाओ' नोटकी का एक शानदार करिश्मा रहा है— बंधुआ मजदूरो की मुक्ति का नामक। आज भी स्थिति यही है— 'शातता नाटक चालू आहे।' लेकिन इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का एक लोकतान्त्रिक बहादुरी से भरा जो बयान 'इण्डिया टुड' में देखने को मिला उसने बंधुआ समस्या को एक क्रांतिकारी मोड़ दिया है। बयान इस प्रकार है—

देखिये आजकल विधायकी बहुत आराम की चीज है (हँसते हैं) प्रति महीने चार हजार रुपये सारी सुविधाएँ और हवाई यात्रा। अगर मैं पार्टीविरोधी गतिविधियों के लिए उठे निकालने पर मजबूर जाऊँ, तो कोई भी ये सुविधाएँ गवाना नहीं चाहेगा। वे जानते हैं कि बी पी सिंह से उन्हें कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलेगा।'

क्या माननीय विधायको को बताना जरूरी होगा कि इस बयान का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री की विधायको का डक की चोट पर अपना बंधुआ धोपित करती वीरमुद्रा हमारे लोकतंत्र की किस शमनाक स्थिति की ओर इशारा कर रही है ?

स्पष्ट है कि कंसा भी खुना मखौल उड़ाने के बावजूद अधिकांश विधायक प्रतिवाद में मुद नहीं खालते हम पूरे एरमोनान म हो मुख्यमत्री महोदय ने ऐसा वक्तव्य दिया है जो तिक विधायकी, स्वयं मुख्यमत्री तथा प्रदश की समूची जनता के लिए शमनाक हो नहीं, बल्कि लात-तख के लिए खतरनाक है। जनता द्वारा निर्वाचित विधायकी की जनता की जगह सत्ता स्वाधीनता में घिरा हुआ तथा चार हथार उपे महीने बेसन और हवाई उड़ान प्रदान करने म समय व्यक्ति का बंधुआ गुनाम घोषित करना माफ बात रहा है कि सप्रभुता सम्पन्न गणतन्त्र किस भयावह दुदशा की प्राप्त हो चुका है।

मुख्यमत्री महोदय के ज्ञान से साबित होता है कि प्रदेश के राज्यकोष पर उनका निजी स्वामित्व है। विधायकी को बेतन देना उनकी शक्त पर निर्भर है। सत्ता के व्यक्ति में के हीकरण की इस असोकतांत्रिक प्रक्रिया ने ही लोकसभा और विधानसभाओं को चरित्र क बोन और व्यक्तिवही लोपा की महासभाओं म बदल दिया है। मुख्यमंत्रियों की खुद की हसियत एक सूबेदार से ज्यादा कुछ नहीं। वो विधायकी के बहुमत की जगह, आलाकमान की मर्जी के मोहताज हैं और इसीलिए उ हे विधायकी का खुना मजाक उड़ाने म कोई बाधा नहीं। हमारे विधायकी म अगर जरा भी स्वयं की स्वाधीनता और गरिमा की चेतना होती और अपने की चुनने वाली जनता के सम्मान की चिंता, तो इसी बात पर मुख्यमत्री के विरुद्ध बवाल मच गया होता और हवाई उड़ानों के प्रलोभन से विधायकी को सत्ता के खूटे म बाधे रखने के दाव्यार मुख्यमत्री हवा में भूल रहे होते।

जब हम अपने निहायत ही शमनाक मखौल को भी चुपचाप पी जाने के आदी हो जायें, तो यह सतूत है कि बे-यैरत हो चुक। भाषा की फटकार कोड़ा की फटकार से भी तीखी होती है, लेकिन उन पर भाषा का कोई असर नहीं होता, त्रिनकी त्वचा मर चुकी है। आदमी की त्वचा का खाल में बदलना उसका पशु से भी बदतर हो

जाना है। तब कसे भी सुलगत सवाल उसमें कोई चेतना नहीं जगा पाते। तब वह मानापमान के सारे सवाल स ऊपर हो जाता है। तब उसे आप सरआम राजनतिक दलाल कहिये, तो भी वह सिफ इतना जानना चाहगा कि कीमत कितनी मिसनी है।

मुख्यमन्त्री इसी बात को यो भी कह सकते थे कि क्या विधायकों को इतना अवसरवादी समझा जा रहा है कि वे जिस तरफ राजनैतिक लाभ देखेंगे, उधर ही टूट पड़ेंगे? मुख्यमन्त्री दावा कर सकते थे कि बूकि हमारे विधायक कि ही निजी स्वार्थों से नहीं, बल्कि लोकतन्त्र के मूल्यों, राष्ट्र की वि ता और प्रदेश की जनता के हित के सवाल से बंधे हुए हैं—चार हजार रुपये की रकम, बगलों की सुविधाया या हवाई उड़ानों की अयशाशों से नहीं, इसलिए प्रदेश में कांग्रेस की सरता के लिए कोई सकट नहीं है।

मुख्यमन्त्री ने नहीं कहा, तब यह हमारे विधायकों की गहरी नतिक जिम्मेगारी जाती थी। और बनती है कि वो यह सवाल उठते कि उनकी इस खुली अवमानना का जवाब मुख्यमन्त्री को हर हाल में देना होगा कि सत्तापक्ष ही नहीं, विपक्ष के भी सारे विधायक खरीद की वस्तु हैं। इनकी जनता, लोकतन्त्र या सस्था के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं। कि ये सब सिफ अपने अपने राजनैतिक लाभों और पैसे तथा हवाई उड़ानों से बंधे हैं। इस सवाल को नहीं उठाने का मतलब होता है, मुख्यमन्त्री ने जो कुछ कहा है सच ही कहा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा है।

आम्मी उसके सवाल से जाना जाता है। जो स्वय की गरिमा, स्वाधीनता और चेतना के सवाल नहीं उठा पाता, वह देश, समाज और काल, तीनों के लिए बोझ बन जाता है। हित और स्वाधीनता के सवाल से उदासीन और जड व्यक्ति ही लोकतन्त्र की सबसे बड़ी बाधा है। जैसे बकरी सेंडी छोडनी है, ऐसे मतपेटी में वोट डाल

आने वाले नागरिक ही लोकतंत्र को ले डूबते हैं, क्योंकि ज़से बकरी को खुट की लेंढी से कोई सरोकार नहीं रहता कि उसका क्या उपयोग है—ठीक ऐसे ही जड नागरिक को वोट से । इसी से पूरे देश में ऐसी राजनतिक गदगी व्याप्त हुई है कि वोट का बदले में बोटल या कम्बल यमाना वोट देने वाले पर कृपा करने के समान हो गया है । हम माननीय विधायक गण ममा करें, जो भी सवाल से यहां उठा रहे हैं , राष्ट्र और समाज के हित में उठा रहे हैं । सवाल से बिदकना ठीक नहीं । कैसे भी तीव्रे सवालो में कोई हज नहीं, क्योंकि इनमें आज किनारा करें, कल फिर मूह-सामने खडे होते हैं ।

सवाल डडे से नहीं, बल्कि बहस से हल किये जायेंगे, यही लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है । सवालो का युक्तिसंगत जवाब, इसी पर लोकतंत्र के सारे विधि विधान टिके होते हैं । लोकसभा और विधानसभाओ की प्रासंगिकता ही इसमें है कि वहा कसे और कितन ज्वलन्त सवाल उठाये जा रहे हैं । लेकिन जो जनता के सुख दुख शोषण उत्पीडन, हित ग्रहित, उसकी जडता और चेतना, अपमान और गौरव तथा बाढ और सूखे के सवाल उठाने को विधानसभा में पधारे थे, वो अपनी ही फत्रीहत और छीझालेदर के विध्वंस मूह खोलने में असमर्थ हो, तो जनता के सवालो का क्या होगा ? हम यह बताया जाना कि देखो, जिसे तुम धून धक्कड और धूप बरसात भेलकर भी इसलिये वोट देने दीडे थे कि यह तुम्हारे सवाल उठावगा, उमे सिवा पैसे, राजनेतिक लाभ और हवाई उडानो की अम्प्राशिया बटोरने के और कोई काम नहीं—हमारा ही नहीं, देश और लोकतंत्र का भी मज्जाक उठाने के सिवा कुछ नहीं । यह प्रकारा नर से, इस बात का भी सबूत है कि हमारा वोट देना सिवा उडना और मूसता के कुछ नहीं ।

व्यक्ति हो कि राष्ट्र, स्वाधीनता, और गरिमा और प्रतिबद्धता के मवान मखोल की सामग्री नहीं हुआ करते ? लेकिन दुर्भाग्यवश

आज की हकीकत यही है। इस जगत में हर कोई बँधा है, क्योंकि बिना बंधन के आदमी नहीं चल सकता। किसी न किसी मूल्य, सकल्प, सम्बन्ध या स्वायत्त से बँधकर ही आदमी अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। जो किसी से नहीं बँधा, वह आदमी नहीं। देखने की बत सिर्फ इतनी इतनी है कि कौन किससे बँधा है। तप से बँधे और तस्करी से बँधे में अंतर है। समाज के कर्तव्यों से बँधे और सत्ता की कुर्सी से बँधे में अंतर है। प्रेम से बँधे और पाप से बँधे में अंतर है। हम अपने माननीय विधायकों से बिल्कुल सवाल करना चाहेंगे कि आप कहाँ, किससे बँधे हुए हैं ?



कैसा सवाद, किससे सवाद

इधर कई एक समाचार पत्रों में पढ़ने का मिला कि प्रधानमंत्री जल त राष्ट्रीय मुद्दों पर देश के बुद्धिजीवियों से (भी) सवाद चाहते हैं। यह 'भी' ही ज्यादा ध्यान अटकाने वाला है क्योंकि इससे इतना तो साफ ध्वनित हो जाता है कि बाकी सबसे तो बाकायदे है ही।

राज्यव्यवस्थाओं का इतिहास बताता है कि प्रायः प्रत्येक शासक को किसी न किसी प्रसंग में, इस 'बुद्धिजीवी' नाम के वर्ग की (भी) जरूरत पड़ती जरूर आई है। लोकतंत्र में राजदरबार की गुंजाइश नहीं। हालांकि कहने वाले तो यहां तक बह जाते हैं कि लोकसभा से बड़ा दरबार कहा। यहां के सवाद विवाद तो रावण विभीषण को भी चकरापित्री खिला दें। बहरहाल हम, फिर दोहराकर, इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रत्येक शासक को कभी न कभी बुद्धिजीवियों से (भी) सवाद की जरूरत पड़ती जरूर है। श्रीमती गांधी भी कई बार बुद्धिजीवियों को स्मरण कर लिया करती थीं। बुद्धिजीवियों से तात्पर्य विचारकों की सी छवि वाले साहित्यकारों से भी हुआ करता है। हम यहां इसी वर्ग का कुछ जिक्र करेंगे अगर, अपनी माता जी की ही तब में, राजीव गांधी भी बुद्धिजीवियों में साहित्यकार किष्कि के व्यक्तियों को

भी शामिल करते हो।

श्रीकांत वर्मा के नहीं रहने से हिंदी के बुद्धिजीवियों का प्रति-निधित्व, लोकसभा में लगभग शून्य के स्तर पर पहुँच गया है। क्योंकि वहाँ जो ५० नरेशचंद्र चतुर्वेत्ती जी हैं, सो राजनीति में पठित नेहरू और माहिल्य में सनेही-युग के विशेषज्ञ हैं। और उधर बालकवि बेरागी का बौद्धिक स्तर अभी रेखा से काफी नीचे है। वैसे भी जब राजीव गांधी आह्वान कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि यह सत्ताकेन्द्र से बाहर के बुद्धिजीवियों को बुलावा है। क्योंकि सत्ता के द्रव्य बुद्धिजीवियों से तो उन्हें सञ्वाद की जरूरत नहीं। इशारा काफी है।

'मान-न मान, हम तेरे महमान' के तक से हम खुश को भी बुद्धि-जीवियों की कतार में शामिल कर लें, तो इसमें एतराज न किया जाए; क्योंकि पहली बात तो यह कि राजा जब संगीत की जरूरत आहिर करे, तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि उसे नींद आ रही है। दूसरे वह, ताज की ही तरह, खुश के कामकाज में भी नग जड़वान का शौकीन होता है। ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों पर दश के बुद्धिजीवियों से प्रधानमंत्री की वार्ता—यह भी एक शुद्ध जडाऊ नग है। दश के बुद्धिजीवियों की कुछ भी ज्यादा ओकात न पण्डित नेहरू के दरबार में थी। श्रीमती गांधी के यहाँ रही और न राजीव गांधी के दरबार में होनी है। पूजोवादी लोकनृत्य के ढाँचे में विवाद की चाह जितनी हो, सवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सवाद सिर्फ बराबर के सांझीदारों के बीच ही सम्भव है। इसलिए पहला ही सवाल उपस्थित होगा यह कि प्रधानमंत्री देश के बुद्धिजीवियों की हैसियत क्या आंकते हैं? और इसके बाद प्रारम्भ होगा, राष्ट्रीय मुद्दा पर सवालियों का एक ऐसा लम्बा सिलसिला, जिसे बिल्कुल सम्भव है कि प्रधानमंत्री यह घोषणा करते हुए एक ही भटके में तोड़ फेंकें कि—'हम देश के सारे बुद्धिजीवियों को उनके बापों की (भी) नानियाँ याद करा देंगे।'।

यद्यपि अवसर पाया जाता है कि उनका गांधीवाद (भी) नादीनाद से कम फुफकार भरा नहीं होता ।

जा व्यवस्था गैर बराबरी के सिद्धांत पर टिकी और जिसने स्वयं देश के बुद्धिजीवियों को ही असवाद में पहुँचा दिया हो, उसके प्रधानमन्त्री को अगर सवाद की जरूरत हो, तो एक रास्ता उसकी इस खजुआहट को मिटाने का हो सकता है । दूसरा उसे इतना साफ साफ बता देने का भी कि सवाद की पहली सीढ़ी सचाई है । और सचाई है यह कि प्रधानमन्त्री देश के बुद्धिजीवियों से सवाद नहीं, सवाद के नाटक की बात चलाना चाहते हैं । अ यथा इतना वो भी जानते हैं कि उह ऐसी कोई सनाह कर्नई नहीं चाहिए, जो राष्ट्र के मुद्दों को प्रधानमन्त्री की कुर्सी से बड़ा करती हो । जो बहस को इस मूकाम तक (भी) ले जा सके कि इसके लिए उनका कुर्सी से हटना भी जरूरी हो सकता है । जा राजनीति का यह मम उजागर कर सके कि शासन करने वालों की कुर्सी पर बैठना ही नहीं वक्त पड़े पर उठना भी जाना चाहिए ।

राजा को सही सलाह सिर्फ वह व्यक्ति दे सकता है, जो लोभ और भय से ऊपर हो । जो राज्य से स्वयं के स्वार्थ साधने के मोर्के की तलाश में स्वयं की बौद्धिक वचारिक धूँधन आगे निकाल रहते हों, या जिनके घुटने राजा के शक्तिमण्डल की चकाचौंध की मार भेलने में अममथ ह। ऐस बुद्धिजीवियों में प्रधानमन्त्री का सवाद कैसे हागा ? सवाद तो, जैसा कि पहले ही कहा, बराबर के सांझीदारों के बीच की वस्तु है । सवाद बौद्धिक वैचारिक सांझीदारी की भाग करता है । कम और स्थिति में भिन्न होने के बावजूँ उद्देश्य तथा चिन्ता में समान लोगों के बीच सवाद स्वयं बन जाता है । राष्ट्र और समाज के ज्वलन्त सवाल के प्रतिबद्ध लोग जब राजनीति में आते हैं, तब उनका दश के बुद्धिजीवियों से अपने आप सवाद का सिससिला बन जाता है । जार-शाही के विरुद्ध रूस और गिराशाही के विरुद्ध भारत के स्वाधीनता

संघ का दौर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

बिना उद्देश्य और बिना में एक हुए स्थिति में एकरूपता असम्भव है और सवाद का कोई मतलब नहीं हुआ करता, अगर कि वह एक ही उद्देश्य के पथियों का आपस में बातचीत करते चलना नहीं हो।

सचाई है यह कि जिस दिन इस देश में समाज की राजनीति का ज्वर, उसी दिन राजनीति और विचार के क्षेत्रों के लोगों में सवा की जमीन भी तैयार होगी, इससे पहले नहीं। तब तक देश के बुद्धिजीवियों से सवाद की बात राजनतिक शिरोधारजी के सिवा कुछ नहीं क्योंकि इकीकत की प्रधानमन्त्री ही नहीं, देश के बुद्धिजीवों भी समझते जरूर है। यह भी कि देश की मौजूदा राजनीति में एक ही राजनेता ऐसा नहीं, जिसका बौद्धिक वैचारिक कद हृद से ज्यादा बौना नहीं हो। सत्ता और विपक्ष, दोनों जगह राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अकाल यन्त्रा रहा है। जो मंच पर मौजूद हैं, उनसे वार्ता के लिए देश के बुद्धिजीवियों को छ इंच छोटा करना जरूरी होगा। बल्कि, शायद, इससे भी ज्यादा क्योंकि इनसे वाता के लिए महत्त्व ही नहीं, हृदय भी घर पर ही छोड़ना जरूरी होगा। कारण कि जो सत्ता पर विराजमान हैं, पक्ष या विपक्ष कही भी, उनकी चेतना पर चर्च की परतें जम चुकी हैं। जो नहीं हैं, उनकी चेतना झिल्ली हो चुकी है। आज का सच यही है कि अ भिव्यक्ति और विचार की स्वाधीनता को खूटी पर टांगकर ही कोई बुद्धिजीवी इस मुक्त के राजनेताओं से वार्तालाप कर सकता है।

देश आज गम्भीर सबटो से गुजर रहा है। ऐसे ही समय में एकात्मकता की गहरी जरूरत हुआ करती है। राजनीति जब विचार और दृष्टि से चलना चाहे, तब एक बहस जरूरी है। लेकिन हर हाल में सवाद बराबर का साक्षा है। प्रधानमन्त्री से सवाद के लिए देश के बुद्धिजीवियों को यह देखना जरूरी होगा कि किसकी हेतियत क्या है। तब प्रधानमन्त्री का वास्ता इस सवाल से भी पड़ सकता है कि हेतियत

सिफ कुर्मी की ही नहीं होती । इससे पहले तो कोई सवाद होना नहीं, क्योंकि कुर्मी और आदमी में सवाद असम्भव है । कुर्मी जब भी बोलती है, आदमी की बोलती बंद कर देती है ।

देश जिन परिस्थितियों में घिरा है, लोगों की मानसिकता में जो दरारें आ चुकी हैं, सवाद जरूरी है । सवाद जरूरी है, विभिन्न क्षेत्रों के प्रवक्ताओं के बीच, राजनीति, शिक्षा, व्याप, प्रशासन, नीति नियमों जन से लेकर कला और विचार—समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच सवाद और बहम का वातावरण होना जरूरी है । किसी भी ऐसे देश के लिए जो आर्थिक-राजनैतिक ही नहीं, बल्कि मानसिक व धार्मिक तौर पर भी विखसाम दिखाई पड़ने लगा हो । जहाँ बहम और सवाद के छोट-छोटे उजाड़ पर हो, लेकिन बम बंदूकी स्टनगना के साथ निरंतर गहरे होते जा रहे हो । लेकिन सवाद की पहली शर्त है सचाई और सचाई यह है कि हमारे सुदृशन प्रधानमंत्री हमसे सवाद नहीं, सिफ सवाद का नाटक करना चाहते थे—और वह भी अभी तो शुरू हुआ नहीं ।



स्त्री-हत्या का उत्सव

रूपकुवर का दहन सनसनीखेज नहीं, शमनाक घटना है। सिफ दिवराला नहीं, पूरे देश के लिए। भारतीय समाज, सविधान तथ सरकार तीनों के मुह पर कालिख है, रूपकुवर का सती होना। जहा सफ़्फ़ो लोग समाशाई हो, उसे स्वेच्छा से सती होने का दर्जा कतई नहीं दिया जा सकता। क्याकि अगर कोई सचमुच सती होना चाहती हो, तो उस मा इतिहास में जाना होगा — और था एकात में अपनी चिता खुद रचती होगी। क्याकि सिफ जाहिल और बबर ही किसी को आग में जलते देखकर चुपचाप खड़े रह सकते हैं। हालांकि यह एक सचाई है कि जाहिलो और बबरो का न अब अकाल था, न अब है। लेकिन इतना तथ है कि रूपकुवर की हत्या में वह प्रत्येक ब्यक्ति शामिल है, जो भीके पर मौजूद था। लेकिन सबसे जघन्य हत्यारे हैं, उसकी समुरान धाले। अगर समाज जागता होता, तो रूपकुवर के समुरा-लियों के मुह पर कालिख पोतकर, न सिफ यह कि पूरे दिवराला में बुमाया जाता, बल्कि स्त्री हत्या का उत्सव मनाने की जगह, जेल के सीलचों के भीतर अपन पाप कर्मों का रोना रो रहे होने।

दिवराला सबूत है कि हमारा बुद्धि का दिवाला पिट चुका है।

प्रधानमन्त्री भी सती प्रथा रोकने को अध्यादेश लाने की घोषणा करके मगन है, जबकि नागरिका व अस्तित्व की रक्षा के लिए संविधान प्रथम ही बचनबद्ध है। हत्यारो को फाँसी या फिर उम्रकद की कानूनी व्यवस्था पहले ही मौजूद है। हर बात के लिए अलग से अध्यादेश जरूरी होने की बात करना संविधान की खुली तोहीन है। हमारे नवजात प्रधानमंत्री को हर काम के लिए अध्यादेश चाहिए। साफ है कि उनकी भी कोशिश मामले पर सीपापोती की ही है, अर्थात् वो पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री और उन तमाम पुलिसवालों को निकाल बाहर करते जिन्होंने हत्या रोकने से इंकार किया और लोगों को स्त्री हत्या का नगा उत्सव मनाने की छूट दी।

अध्यादेश अधिनियमों की हकीकत किसी से छिपी नहीं। किसी बाण्ड पर हो हस्ता ठठते ही सरकार अध्यादेश जारी करने की बाहवाही लूटने में जुट जाती है। दहेज हत्यारो पर कितना अकृश लगा पाई है सरकार हम सभी जानते हैं। आखिर रूपकुंवर के हत्यारे भी देखराब छूट निकलेंगे। बाहवाही सूसने की गिरफ्तार किए गए हत्यारो को हो हस्ता बैठते ही, कानून के चोर दरवाजों से बाहर कर दिया जायेगा।

प्रभाप जोशी जैसे राष्ट्रीय पत्रकार जिसे पुनर्जागरण के दिव्य दर्शन, परम्परागत गरिमा और वशगत शीघ्र की सज्ञा देने का धूणित फाय कर रहे हैं, यह राजपूतों के शीघ्र नहीं, जमानतों की बर्बरता का सङ्गत है। एक स्त्री को आग में भूनना शीघ्र नहीं क्रूर नगई का परिचय देना है। हम यहाँ इस प्रसंग में सबसे पहले स्त्री की अवधारणा का सवाल उठाना चाहेंगे, क्योंकि आन्मी धारणा के अनुसार ही व्यवहार करता है। स्त्री की हमारी अवधारणा क्या है, यही बात बनावेगी कि हमारा चरित्र क्या है, क्योंकि स्त्री अत्यंत कठिन परीक्षा है। जो स्वयं के अस्तित्व में स्त्री में स्पष्ट अनुभव करते हैं, उन्हें ही न केवल सवाल भी व्यापक है। बचरा को स्त्री जिसे के सिवा कुछ

नहीं।

जायन समाजों की पहली पहचान स्त्री की प्रतिष्ठा है, क्योंकि सस्कृति के सार रचयक सवेदना की धुरी से चलते हैं और सवेदना का मुख्य आधार है, स्त्री। वेदों का वरण उसे मनुष्य की प्रथम प्रतिश्रुति करता है क्योंकि वही गुनती है मनुष्य व पृथिवी पर अवतरण की पहली पहली आवाज। अभी जबकि हमारी वाचा, अनुभूति और श्रुति के सारे स्रोत देवाधीन हैं एक वही है, जो कि गम में प्रत्यक्ष क्षण अनुभव करती है हम। मनुष्य की प्रथम धारिणी वही है। छात्री से अधिष्ठात्री तक की उसकी सकल्यता यो ही नहीं की गई। भाया से भी प्रथम आर्या का स्थान माना गया उसका। हम उपादा दूर नहीं जाएँगे। अपन ही देश काल और समाज में खोजेंगे स्त्री की अवधारणाएँ।

अध्यागिनी से लेकर आद्यापति तक का उसका विपुल विस्तार खोजने को हम अ यत्र यती जान की कोई जरूरत नहीं। स्त्री को महीयसी कहने वही दूर जान की नोबत हमें कभी नहीं आई। क या से महाकाली तक कैसे जाती है स्त्री की शृ खसा, इसे हमसे बेतर पूरे विश्व में कोई नहीं जानता और इसमें क्या शक कि स्त्री की जो जो पत्नीहृत और दुर्गति हमारे हाथों है इसका भी स्पर्श मिलना, शायद, कठिन ही हो पूरे विश्व में।

स्त्री का मजाल मानव समाज का सबसे उपादा मूलगत सवाल है। जसी स्त्री, वैसा ही समाज अग्रशम्भावी है। इसीलिए श्मन रूप कुंवर के प्रसंग में सबसे प्रथम स्त्री की अवधारणा का प्रश्न उठाया और इसना हम बिल्कुल दावे के साथ वदना चाहते हैं कि जो अवधारणा नहीं करते, जिसमें में भले ही पड़े रहे, चेतना व सार पर मर जाते हैं। उनकी मवेत्ता काठ चेतना उजाड और त्वचा खाल हो जाती है। हृदय भी वही करता है, जो अवधारणा नहीं कर सकता। जो इस सवाल में कभी नहीं जा सकता कि मनुष्य जब उत्पन्न होता है, तो

माता के पूरे अस्तित्व में कसी अपूर्व हलचल मचाता हुआ आता है। और अगर कि उसे अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, तो धीरे धीरे कैसे, अपनी जननी की आशा आकांक्षाओं की तरह ही ध्वस्त हो जाता है।

स्त्री का मतलब समझना सम्पूर्ण मृष्टि का मतलब समझना है। अगर हम मृष्टि का मतलब नहीं समझते, तो रूपकुंवर का मतलब भी नहीं समझ सकते, क्योंकि किसी भी वस्तु का सही सही मतलब सिर्फ वही समझ सकता है, जो कि उस आर से पार तक देख सकता हो। वस्तु हा कि आदमी, उसका एक छोर अधूरा है।

स्त्री के भी कई ओर छोर हैं। क्या स मुसलमी तक जाता है, उसका जीवन का व्यास। ब्रिटिशों से दादी अम्मा तक जाते हैं उसके रिश्ते। अगर कि यह अविवाहित विधवा या सतानहीन हो, तो भी वह स्त्री है और स्वयं में मानव समाज की एक धारा। सवाल यह है कि क्या हम उद्गम से मुहाने तक बहने का अवसर देते हैं उसे? जिस समाज में स्त्री की नदी की भाँति बहने और अपनी कल कल को बहने का अवसर नहीं, वही अंधा रेगिस्तान है। रूपकुंवरों इसी अंधे रेगिस्तान में गुम होती हैं। यह स्त्री के प्रति बबरता का रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान नहीं, उन सारे हिंदू स्थानों में है, जहाँ जहाँ इसे मारा जाता है।

एक पौदा तक प्रकृति में अपना अर्थ तभी पाता है, जब उसे उसका पूरा समय मिले। आदमी और काल का सम्बन्ध सामान्य नहीं। जब हम प्रकृति में हमारा पूरा समय नहीं मिलता, तो हम इस अकासमृत्यु कहते हैं। जब समाज से नहीं मिले, तब क्या करेंगे इसे? सिवा अकाल हत्या के और क्या माना जाय रूपकुंवर के अग्नि-दाह की? नाम का राजस्थान रह गया है और नाम के राजपूत। चरित्र राक्षसों से ज्यादा घृणित है। राक्षसों के यहाँ बहू बेटीयों की आग में जीवित भूनने का उत्सव कभी नहीं मनाया गया। लेकिन

स्त्री को शक्ति यो ही नहीं माना गया । रूपकुँवर ने भी शक्ति होने का ही सबूत दिया है । पूरे देश की नगई को उछाड़ने का निमित्त होने की शक्ति का ।

रूपकुँवर के मामले का सबसे बड़ा पेंच है बिना सतति के ही विधवा हो जाना । और हमारे सामाजिक चरित्र का इतना खोखल और खतरा होना कि अकाल विधवा हमको सासत क सिवा कुछ नहीं । हमारे चरित्र के खोट इतने शमनाक हैं कि इ हे दापने के लिए न सिर्फ स्त्री की हत्या, बल्कि इसका आकायदे एक ऐसा छद्म सामाजिक सांस्कृतिक दशन गढ़ा जाना जरूरी है, जो हमारी संवेदनशून्य यत्ना, चारित्रिक नगई, धार्मिक जघन्यता और अमानवीयता पर वशानुगत शीघ्र परम्परागत गरिमा का कुत्सित आभरण कर सके । हमारे, पुरुष नहीं, कापुरुष होने की हकीकत पर सांस्कृतिक पहचान का पर्दा सान सके । हमारे हत्यारे होने को आत्मा की अमरता तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत के धोखे की टट्टी की आह म छिपा सके ।

जसा कि पहले ही कहा, हर वस्तु के दो छोर हैं । जहाँ पत्नी के न रहने पर पति के उसकी चिता में प्रज्ज्वलित होना का शास्त्रीय विधान नहीं हो, वहाँ पति के साथ स्त्री के सती होने का तक गढ़ना घूतता और जघन्यता के सिवा कुछ नहीं । स्त्री पति वियोग में विदग्ध होकर आत्महत्या कर ले, यह उसकी स्वेच्छा का सवाल ही सकता है । सती होना एक सांस्कृतिक कृत्य है और इसमें शामिल प्रत्येक की शक्ल एक जघन्य हत्यारे के सिवा कुछ नहीं ।

पति पत्नी, ये एक ही तथ्य के दो छोर हैं । तब इनमें से एक का नहीं रहना अलग अलग अर्थ नहीं रख सकता । जो स्थिति पति के बिना पत्नी की बनती हो, वही पत्नी के बिना पति की अगर नहीं है, तो साफ है कि वही कोई जबदस्त घपला है । रूपकुँवर का मामला हमारे इसी सामाजिक कोड की देन है, जो स्त्री को देवी महादेवी की

प्रतिमा के रूप में पूजने को तो घूँप अगरवत्ती, घटो सहताल लिये सदा प्रस्तुत है लेकिन समानता का दर्जा देने का बतई तयार नहीं । जबकि समानता का दर्जा पहले पड़ता है और ऊँचाई का बाद में । हमें कुछ चेत नहीं कि जो स्त्री को समानता देने के हामी नहीं, उनकी देवीपूजा सिवा पासण्ड के और कुछ नहीं । रूपकुंवर की सांख्यिक हत्या हसार नसी चारित्रिक पासण्ड की देन है । हम उ पीड़ित स्त्री को सात्वना नन में जितने असमय साँसत खड़ी करने में उतनी ही महा-विकराल हैं ।

रूपकुंवर, या कहे कि बिना सतति की अकालविधवा, प्रत्यक्ष निम्न मध्यवर्गीय तथाकथित हिंदू जातिसमूहों की सवेदनजड़ता, चारित्रिक उजाड़ और कुठिन बबरता की गवाही है । स्त्री सिर्फ चरित्रहीन और कायरों कुठितों की ही साँसत होती है । जिस समाज में स्त्री को वर्णित करने की क्षमता नहीं वह कापुरुषों का डेरा है । हमें हमारा चारित्रिक उजाड़ खा रहा है । बेटा कैसे भी अयोग्य तथा भ्रष्ट होते भी प्राणों का प्यारा, लेकिन बहू बेटे के नहीं रहत ही-सहित है और इसमें पूरे समाज की बबरता और स्त्री के प्रति कुत्सित, नकारात्मक तथा बबर मानसिकता का दबाव भी उतने ही काम करते हैं । यहाँ हम एक सुझाव रखना चाहेंगे । जिनमें बहू या भाभी का मर्ती देखन का सांस्कृतिक शौच हो उन्हें थोड़ा अपनी बटी या बहन को आखा का सामान जीवित जलते देखन की कल्पना भी करनी चाहिये और जवाब देना चाहिये इस सवाल का कि क्या तब भी मधमृच कोई वेदना नहीं व्यापेगी ।

रूपकुंवर न पापा—मम्मी नइया की बरुण चौखी मारी, या नहीं हम कुछ नहीं जानते लेकिन इतना बिल्कुल मानते हैं कि उन दोनों की धिक्कार है जो बटी और बहन को जीवित जलाते सांस्कृतिक ८ । या यथानुगत शौच अनुभव करें और इस चेतना में शूय हों ।

बहु भाभी भी बिसी की बेटा और बहन हैं हम फिर बहेंगे, जिस समाज में स्त्री ह या परम्परागत शोय या धार्मिक पवित्रता का प्रतीक हो, उसका विनाश निश्चित है ।

हम वास्तव में राजपूत होते, तो स्त्री—हत्या का उत्सव मनाने वाले जघन्या को जाति—बाहर कर छोड़ते और इनके ऊपर धूकने का भी धूक की सीढ़ी मानते । हम राजपूत नहीं हैं । ऐसी प्रत्येक परम्परा संस्कृति और शोय सभी को बारम्बार धिक्कार है, जो स्त्री-दहन की वकालत करती है ।

सर्वोच्च यस्तु प्राण है । कोढ़ी भी स्वेच्छा से प्राण नहीं त्यागता । श्रेष्ठ वही है, जो प्राणों की कीमत समझता है । बबर समुदायो में ही प्राणों की कोई कीमत नहीं । मनुष्य वह है, जो पशु को जीवित जलते देखकर भी व्याकुल हो उठे । जि ह एक अस्पृश्यस्त्री का जीवित दाह सती—उत्सव मने, उनकी खाल कोड़ो से खींची जाए, तो भी कम है, क्योंकि जिनकी त्यचा खाल हो जाती है, वो बिना सींग पूछ के भीमत्स पशु के सिवा और कुछ नहीं । आदमी की खाल उतारना जरूरी है, क्योंकि खाल रहते उसे किसी की वेदना नहीं व्यापती ।

धम, धिचार, राजनीति, साहित्य, कला और संस्कृति—सबकी कसौटी है आदमी । और आदमी की कसौटी है, संवेदना । मनुष्य की धवना से धेमरोकार धम, शास्त्र, संस्कृति, परम्परा राजनीति, ये सब सिवा जघन पातक के कुछ नहीं । स्त्री की सावजनिक हत्या पर दशन, संस्कृति और परम्परा का पर्दा तानन वाले लोग ससार के सबसे जघन हत्यार हैं । रणकुवर की हत्या का उत्सव हमारे राष्ट्रीय पातक का प्रमाण है । रूपकुवर का अग्निदाह इस देश के स्त्री—हत्यारों की पहचान कराता गया है । इस रोशनी में हमारे सारे पाप उजागर हैं और ये पाप सिफ सती—काण्डो तक ही सीमित नहीं हैं । दहेज का दानव उस प्रत्येक घर में नगा नाच रहा है, जहाँ स्त्री अभी सिर्फ कया

है । लाखों स्त्रियाँ जिंदा गोشت की कीमत पर बाजारी में सरेआम बिक रही हैं । लेकिन आश्चर्य कि 'चलो, बुलावा आया है, हम माता ने बुलाया है ।' के अक्षण्डकीतनिये हम पाखण्डियों का स्त्री-हत्या के उत्सव सतत और सबल चालू हैं ।



कौन है भारत-भाग्य-विधाता

लोकतंत्र का सारतत्त्व बहस है। बहस का चलते रहना ही लोक-तंत्र का मौजूद होना है। लोकतान्त्रिक राज्य-व्यवस्था में कुछ भी बहस के बाद ही स्वीकार, या अस्वीकार, किया जा सकता है। इतना ध्यान में रखते हुए कि चूंकि आदमी स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक सतत परिवर्तनशील तत्त्व (फेनॉमिना) है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को निरंतर जांचता ही चलेगा वह। कुछ भी उसके लिए अंतिम सत्य नहीं होगा। हमारे लिए पहले 'यशस्वी रहे हे प्रभो, हे मुरारे, घिर जीव राजा व रानी हमारे।' लगभग एक शताब्दी तक सत्य रह चुका और अब 'जन मन गण अधिनायक जय हे।' को भी चार दशक बीतने को है, तो याद रखना कुछ गलत न होगा कि हर वस्तु को जांचते चलना ही चेतनागत विकास की प्रक्रिया में होना है।

आदमी का इतिहास जानते चलने का रहा है। इतिहास की किताब स्वयं में ही एक जांच पुस्तिका है। घास पात, पोथी पत्रा से लेकर आकाश पाताल और आलू प्याज से लेकर आत्मा-परमात्मा तक को जांचते चलने का एक लम्बा इतिहास रहा है हमारा। देर से ही सही ब्रिटिश साम्राज्य को भी हमने जांचा जरूर और परिणाम

भी प्रकट हुआ। लेकिन इस हकीकत से मुह फिराना हक में न होगा कि १५ अगस्त १८४७ के आजादी के पक्ष के बाद, हम फिर उसी गिर-उदासीनता में चने गये, जब ईस्ट इंडिया कम्पनी के कुछ दलालों ने हमें बताया था कि वो भारत में सिर्फ एक व्यापारी की हैसियत (और मात्र इसी उद्देश्य) से आये हैं। और कि इससे दोनों मुल्कों को समान व्यावसायिक लाभ होगा। हम 'शुभ लाभ' के भुरीशों ने इतना जांच लेने की तब कोई जरूरत ही नहीं समझी कि इनका उद्देश्य क्या वास्तव में इतना ही है? इस व्यापारकम्पनी का इरादा कहीं पूर्व में अपने 'चिरजीव राजा व रानी' का 'यूनिशन जैक' पहराना तो नहीं, इस सवाल में हम स्वयं की भूमि से उदासीन गये ही नहीं।

भूमि और चेतना परस्पर जुड़े हैं। जिसकी चेतना जितनी विकसित होगी, भूमि से उतना ही गहरा उमका वास्ता भी होगा। जिसकी चेतना मोघर, वह जमीन से भी उतना ही बेसरोकार होगा। उसे कहीं पता होगा कि राष्ट्र अमीन का हा नाम है।

राष्ट्र क्या है, रहने की जगह है। हमारे रहने की जगह की तरफ कोई लाव लश्कर या गद्गठर पसर बांधे आ जा रहा है, तो आखिर क्यों और किसलिए, इस चेतना का उजाह ही हमें बता दिये तक गुलाम बनाये रहा और इस सदियों तम्बी चौड़ी दासता के गहरे चकत्ते हमारे माथे पर ही नहीं चरित्र में भी आज तक बाकायदे मौजूद हैं। और चूँकि १६४७ की मिली आधी भधूरी आजादी के बाद भी हम फिर जांचित परखते चलने की जगह, घमा दिये गये की ही नियामत मानने की मुद्रा में पसर गये हैं, इसलिए राष्ट्र की आत्मिक भित्तियों का गारा पलस्तर चिटखता ही चला जा रहा है और हम सदा के घासबाज भीतरी टूट फूट को ऊपरी रंग रोगन से लीपने पोतने में जुटे हुए हैं। हमारे चरित्र में अचानक जो इधर एक राष्ट्रीय अखण्डता का ज्वार बड़े जोरो से फूटा है, यह

हमारे भीतरी खोखल को और बड़ा करता जा रहा है, क्योंकि इसमें स्थितियों को जांचने की मांग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखण्डता की आड़ में सत्ताके द्र की अखण्डता पर ईमान लाने का आह्वान मात्र है। जबकि आज राष्ट्र की अस्मिता पर जो घातक सफाई मच रही है, एक एक वस्तु को भलीभांति जांचने परखने की जरूरत है। खास तौर पर सरकार और नागरिक, दोनों के चरित्र को। अब इस बहस की गहरी जरूरत है कि राष्ट्र की आखिर हमारी समझ क्या है।

हमारी समझ में राष्ट्र समाज का घर है। घर के आस पास की खासी जगह भी घर का हिस्सा होती है। रहने वालों और रहने की जगह के बीच एकात्मता ही किसी देश को राष्ट्र बनाती है। फौजों के बृते कायम बज्जा तो सिर्फ (सामू) राज्य बनाता है। इसलिए हमें इतना बिलकुल जांचना होता कि हम पूजा और राजनीति के गठबन्धन से स्थापित शोषक उत्पीड़क राज्य के बाणियों की नियति में धकेल दिये गए हैं, या कि एक स्वाधीन राष्ट्र के रहवासी हैं।

राष्ट्र और राज्य ये दोनों बिलकुल अलग-अलग तथ्य हैं, इन्हें एक ही समझना बिलकुल गलत समझना है। राज्य के अंग-उपांग अलग हैं राष्ट्र के अलग। राज्य राष्ट्र की एक अतवस्तु मात्र है, स्वयं में ही राष्ट्र नहीं। ऐसे में प्रथम हम राष्ट्र के चिह्नों की पहचान की मांग करेंगे और उस पर एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत होगी। एक एक चिह्न को जांच परख कर हो तय कर पायेंगे हम की हमारे द्वारा मान्यता प्राप्त चिह्न पूरी तरह खरे हैं, या कि कहीं कुछ कमी बुनियाद में हो रह गयी है। इस दृष्टि से हम देखें तो राष्ट्र के तमाम मुख्य प्रतीक चिह्नों को भी हमें फिर से गहरे जाकर उलटना पलटना होगा। इस सद्विश्वास में ही कि उलटते पलटते ही चिटखने लगें, ऐसी वस्तुओं से सामान्य घर तक बनाना ठीक नहीं, राष्ट्र तो पूरे समाज के रहने का ठिकाना है।

संविधान, भाषा, ध्वज और गीत—ये किसी भी राष्ट्र की

पठवान ये चार मुख्य प्रतीकात्मक सम्भो हुआ करते हैं। इसी बीच-सम्भो पर एक राष्ट्र समाज का पूरा नैतिकवित्तान टिका रहता है। इनमें से एक का भी गलत होना, पूर दश की राष्ट्रीयता को सकट में डाल सकता है। आज इतना ठीक ठीक तय कर लेना जरूरी है कि राष्ट्र सकट में है या नहीं। अगर हम मानें कि है, तो यह भी मान लेना जरूरी होगा कि इन्हीं चार सम्भो में बही दरारें छूट गई हैं। और जैसा कि पहले भी कहा, दरारों की भीतर तक भरन की जरूरत होती है, इन्हें ऊपर ऊपर रंग रोगन से लीपना पातना ठीक नहीं। यहाँ हम 'राष्ट्रगीत' पर बहस के प्रारम्भ की माँग करना चाहेंगे। भाषा, सविधान और ध्वजा के सवाल भी इसमें पूरी तरह जुड़े हैं। फिर कहेंगे, बहस में कुछ हज नहीं। इसमें जाले साफ होते हैं और जाँची गई वस्तु का रूप अधिक निखर आता है। यहाँ राष्ट्रगीत में के 'भारत-भाग्य विधाता अधिनायक' को लेकर बहम उठाने की जो कोशिश है, वह किसी प्रकार के ओढत्य नहीं गम्भीर चिन्ता और जिज्ञासा में है। बहस में वस्तु घूमिन नहीं होती निखरती है।

२५ अगस्त १९४८ के दिन, 'राष्ट्रगीत' के चुनाव के मुद्दे पर, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 'जन गण-मन अधिनायक, जय ह, भारत भाग्य विधाता।' के १९११ में जाज पंचम की स्तुति हेतु रचे गये होन के तक को निरस्त करते हुए सविधान-सभा में घोषित किया— गान की धुन उसके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है।'

हालांकि लोकतंत्र तो तब भी बाकायदे मौजूद था, लेकिन नीति निर्धारण के मामले में प्रधानमंत्री का वक्तव्य लगभग एक 'राष्ट्रीय हुक्मनामा' ही हुआ करता था और इस पर कोई भी बहस स्वतः सिद्ध रूप से निरर्थक मान ली जाती थी। 'पंचों की राय सिर माध, लेकिन पनाला तो वही गिरगा।' की टेक तब भी ससद से ऊपर थी। परिणाम यह कि अनेकानेक स्वनामधेय राष्ट्रकवियों राष्ट्रीय विचारकों

को व ची ची भी राबेच्छा का लकवा मार गया और यह निहायत बुनियादी रूप जल्दी सबाल हमारी उस राष्ट्रीय मूढ़ यो की सविधान सभा में बहो, किसी भी कोने से उठा हा नही कि जब शब्दों का कोई महत्व ही नही, उससे कुछ फव पडा हा नही, तब 'यशस्वी रह हे प्रभो, हे मुरारे, विजय जीव राजा व रानी हमारे । को ही 'राष्ट्रीय धुन' में यथा लेो में यथा हज है ? क्योंकि अगर धुन ही मुख्य वस्तु हा, तब 'उत्त मन-यण' की धुन में गाये जाने पर 'लारी लप्पा, लारी लप्पा नाई रखणा तेरी मेरी यारी रब्बा, लाई रखणा ।' किस तर्क से राष्ट्रीय गीत नही माना जायेगा ?

देश वा दुर्भाग्य कि हमारे किसी भी राष्ट्राय मूढ़ य की बाणी में यह सत्य प्रकट हुआ नही कि राष्ट्रगीत किसी भी राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक होता है, मात्र अंधवाजे की धुन नही । उसके एक एक शब्द में राष्ट्र की आत्मा की अनुगूँज होना जरूरी है । यो भी शब्दों के महत्व को नकारना मखोल उडाना है ।

हालाकि लोकतन्त्र का इनका मतलब तो उस जमान में भी बिल्कुल स्पष्ट था कि जो भा बहस करेगा उसकी जगह सत्ता दरबार से बाहर ही होगी और हमारे राष्ट्रकवियों का बुढापा ऐसी आराम की भूल में अकुल था । राष्ट्रीय चेतना की सूखी रोटी चबाने का ताब अंग्रेजों के छोडे माल भत्ते को देखते ही खत्म हो चुकी थी । अथवा ऐसा नही कि मैथिलीशरण जी, पत जी, दिनकर बच्चन आदि हमारे मूढ़ य राष्ट्रकवियों को इतना ज्ञान न हो कि राष्ट्र की आत्मा को प्रतिबिम्बित करने वाले शब्दों में रचा गया गीत ही राष्ट्रीय गीत हो सकता है—विदेशी आर्क्स्ट्रा में तैयार कर दी गई कोई धुन मात्र नहीं ।

जिना राष्ट्रीय शब्दों व कोई धुन कभी राष्ट्रीय नही हो सकती, इस सवाल को बहस का मुद्दा न बनाने का मतलब सारे राष्ट्रीय

मुझ या के पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रभामण्डल के तामने प्रतिभे की तरह फटफडाते होने के सिवा और कुछ नहीं था। लोभ इस मतलब को बाकायदे समझते भी थे, लेकिन खुद के नितम्बों के नीचे की मलमली आसन्धियों के सवाल चूक सारे राष्ट्रीय सवालों को दमानी बना चुके थे इसलिए बहम नहीं हुई।

जबकि शब्दों को बेमतलब मानने का रिवाज संविधान सभा में ही निंदित था यथा पा गया, इसलिए शब्दों का पुरसाहाल संविधान में भी कोई नहीं रहा। वहाँ भी 'तिरमा' राष्ट्रध्वज हो गया, 'जन-मैन गण' राष्ट्रीय गीत बन गया, लेकिन हिन्दी राष्ट्रभाषा तो दूर, राजभाषा भी महारानी विक्टोरिया की पालकी अनन्तकाल तक ढाँते रहने की शर्तों पर ही घोषित हो पाई। शब्दों की झूल की सामग्री मानने का यह सिलसिला ही आखिर 'वन्देमातरम्' के भूमि से हमारे 'मातापृथ्वी' के रिश्ते को तो ठोकर पर की वस्तु, लेकिन 'प्रोसीडेन्ट' को (राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष की जगह) 'राष्ट्रपति' मानवाने के मुकाम तक पहुँचा। राष्ट्र क्या कोई निजी जागीर या सम्पत्ति है, इस सवाल को उठाने का नैतिक साहस हम शताब्दियों के मुलामों में न तब था, न अब है। क्योंकि हमारे लिए प्रभुओं की चुनौती हुई चुन शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

बहुत से विचार करते जान के कारण ही आज हमारे भाग्य-विधाता अधिनायकों को खुद ब दूकों के पहर में सिमटना पड़ा है। अर्थात् वह भारतवर्ष कोई और मुक्त नहीं था जिसमें हमारा प्रथम प्रधानमंत्री अपना डेक्कटा डण्डा लिए हजारों लाखों की भीड़ में निविध्न निभय घुम जाता था और लोग गालियाँ देने, ढेले पत्थर फेंकने की जगह, 'पण्डित जवाहरलाल नेहरू की जय' चिल्ला उठते थे। हिन्दू, मुसलमान, सिख और पारसी आदि सभी जातिपाँत्य भी इस श्रेष्ठ में मौजूद थीं और विभाजन की धूँधू घघकती आग में भी हमारा टुट्टा बुझा करमदास मोहनदास गाँधी नोब्रासाली में

मुसलमानों के मुहल्मों में बसोफ भुसता ही नहीं था, उनका प्यार और सम्मान भी बटोर लेता था। तब राष्ट्रीयता के तत्त्व हममें मौजूद थे। तब देश में शताब्दियों के बाद विश्व का यह सबसे बड़ा चमत्कार घटित हुआ था कि हमारे एक निहत्थे मुमिया की बहस के आगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बूढ़ी बोल गई थी। भारतवर्ष की राष्ट्रीयता एकजुट हुई थी, तो दुनिया की मानना पड़ा था कि यहस की साक्ष्य बूढ़ों की साक्ष्य से बनी है। यहस का आधारभूत मूल्य है—अहिंसा ! अही यहस से इंसार हो, वहाँ अहिंसा सम्भव नहीं।

हम यहस की, मांग उठा रहे हैं तो इसलिए कि अहिंसा की लाठी हाथों में गिराव जान से ही हम आतंकवादियों की बूढ़ों की दहशत में घिर गये हैं। यह आतंकवाद किसी एक छोर पर नहीं। सरकार स्वयं आतंकवाद के हथकण्डे हथियाने की आदी होती जा रही है। इसलिए जब हम 'राष्ट्रगीत' पर बहस की बात कर रहे हैं, तो यह सिर्फ चंद गानों की बहस का नहीं, पूरी राष्ट्रीय चेतना और मरुतना का सवाल है। और इतना जांच लेने में, हम फिर कहेंगे, फाई हज नहीं कि हमारा राष्ट्रगीत दरअसल किसकी बचना का गीत है—राष्ट्र या कि किसी व्यक्ति (अधिनायक) की ?

अगर हमें यह समझा दिया गया कि महत्वपूर्ण धुन है, गीत के गान नहीं, तो क्या सपमुच सच ही समझाया गया ? कहीं ऐसा तो नहीं कि गानों की जांच में जाते ही गीत का अर्थ भी सही सही निकल आएगा, इस भीतरी डर में ही 'गानों में क्या रखा है ?' का तब हमारे मत्थे मढ़ दिया गया—और हम ईमान ले आए ? हालांकि ईमान भी जांच की शत से बरी नहीं।

हम इतना मान लेते हैं कि चलिये, 'जन मन-गण' जाज पञ्चम की स्तुति में नहीं रचा गया। कदाचित् रचा भी गया होता, तो मात्र एक इम किसी समय के तात्कालिक दबावों में लिखे गये गाने से बर्खास्त रखा के राष्ट्रीय सम्पदा के स्तर के साहित्यिक अवदान का

महत्त्व कम नहीं हो जाता। फिलहाल हम इतना ही देखें कि जितने शब्द राष्ट्र-गीत के निमित्त एक लम्बी कविता में से हमारे द्वारा चुने गये हैं इनका मतलब क्या निश्चलता है।

शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें गहराई से, तो स्पष्ट हो जाता है कि गीत में किसी एक ऐसे अधिनायक की संकल्पना और अभ्यसना की गई है, जो कि भारत का एकछत्र भाग्यविधाता है। जिसके शुभ नाम की लेत हुए सारे राष्ट्रवासियों को ही नहीं जागना है, बल्कि विध्य हिमालय, गंगा यमुना और सागर की उच्छल तरंगों तक को इसी भारत भाग्य विधाता जन मन-गण अधिनायक से शुभाशीष मागने हैं, ताकि इनकी भी स्वस्ति बनी रहे। अब सवाल रह जाता है कि यह 'अधिनायक' कौन है?

जाज पक्षम के ही भारत भाग्य विधाता होने की सो, शायद, कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ तक का डेरा तभी यहाँ में कब का उठ चुका। पण्डित जवाहरलाल नेहरू से चिह्न मिलायें तो सैद्धांतिक तौर पर, लोकतन्त्र में अधिनायक के लिए जगह कहा होगी? कुछ राष्ट्रीय विद्वानों ने मामला यों बुझाने की चेष्टाएँ की हैं कि यह उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की वदना है, जो हम सारे राष्ट्रवासियों की सरक्षा और शुभ का उत्स है। जिसके पुण्यालोक में हम भारतवासी-आसेतु-हिमाचल एक आत्मिक और राष्ट्रीय एगोति अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ भी अंतर्बाधा उपस्थित हानी है यह कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का भाग्यविधाता परमपिता परमेश्वर को घोषित करना धर्मनिरपेक्षता की चिद्विया उठान के सिवा और क्या होगा? आखिर 'वदमातरम्' की तब धर्मनिरपेक्षता व तब में ही तो अमाय किया गया था? हालांकि आज प्रातः गान बना दिया है, 'दूरदर्शन' में।

स्पष्ट है कि अगर हमारी संविधानसभा ने सर्वशक्तिमान परमपिता की 'भारत भाग्य विधाता' के रूप में अवधारणा की होती, तो

जो धमनिरपेक्ष लोकनय का पाखण्ड कभी नहीं रखते। तब उन्होंने भारत की एक ऐसी हिंदू राष्ट्र कल्पना में सकल्पना की होती, जिसका भाग्य विधाता वह परमपिता परमेश्वर हो जिसका शुभ नाम लेकर ही हम भारत के नागरिक ही नहीं, बल्कि गया यमुना विद्याचल हिमालय समुद्र तक जागते हैं। ऐसे में यह तक स्वतः ही अप्रासंगिक हो जाता है कि 'भारत भाग्य विधाता' से हमारा तात्पर्य उस सर्वशक्तिमान चिन्तनरूप परमेश्वर से होना है जिससे कि हम स्वयं की स्वस्ति की कामना रखते हैं। तब यह 'भारत भाग्य विधाता' कौन है?

सवाल बहुत बेहब वस्तु है लेकिन खरी वस्तु सिर्फ यह है, जो सवाल की कसौटी पर खरी उतर जाय। 'राष्ट्रगीत एक पूरे राष्ट्र की आत्मा का स्वर हुआ करता है। उसे ऐसा होना ही चाहिए। और 'राष्ट्रगीत' ऐसा ही है कि नहीं, यह जिज्ञासा जरूरी है। हमारे पास इस जिज्ञासा का समाधान क्या है कि आखिर यह भारत भाग्य विधाता है कौन, जो कि इस राष्ट्र के समस्त जन मन के मन का अधिनायक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह प्रतीकवाद के प्रतीकवाद का ही सूचक माना है और इनके अर्थों में इनके अर्थों जाने की हमारी प्रवृत्ति औपनिवेदिक मान्यताओं के अर्थों का अचूक प्रमाण?

नहीं हो ? मान सीजिए, हमसे कभी कोई विदेशी पूछ बैठे कि यह हमारा भारत भाग्य विधाता कौन है, तो क्या बतायेंगे उसे हम ? और वहीं कह दिया कि 'हमें कुछ नहीं मालूम ।' तो यह राष्ट्रीय शर्म का विषय होगा, या नहीं ?

बहरहाल अभी तो हम इस ज्वलंत सवाल की इतनी सी राष्ट्रीय बहम के लिए सामने उरस्थित करना चाहते हैं कि घुन तो, छर, घुन हुई ही, लेकिन शब्दों का भी कुछ महत्त्व होता है, या नहीं ? और कि 'जय है, जय है ।' गाने के लिए भी इतना ज्ञान होना जरूरी होगा या नहीं कि आखिर हम 'जय है जय है' या किसकी रहे हैं ? बिना प्रभुओं की मूरत ठीक से पहिचाने, तो जनम के गुनाम तब 'जय ह जय है ।' नहीं चिल्ला उठते—हम शताब्दियों के गुलामी की आतिर हा क्या गया है ?

हम सबमुच नहीं समझ पा रहे कि हमारे राष्ट्रगीत में का यह 'भारत भाग्य विधाता' अधिनायक कौन है । अनेकानेक विद्वानों ने समझना-बुझना चाहा, तो वो भी पण्डित जवाहरलाल नेहरू की तरह 'अर, शब्दों में क्या रखा है—आशय तो राष्ट्र की बदना से ही हो सकता है ।' कहकर टरका गये ।

हमारे उस समाल का जवाब भी अभी नहीं मिला कि क्या ऐसा होना सम्भव भी है कि शब्द अलग हों और उनका आशय अलग ? आखिर राष्ट्रगीत जैसे महत्त्व के काय में ऐसे शब्दों का प्रयोग असम्भव अथवा निषिद्ध क्यों हो जो आशय को अगम्य, अमूल या विरुद्ध नहीं करते हो ? 'वागर्थाविव सम्पृक्तौ' क्या पालिदास ने यो ही कहने को कह दिया था ? क्या शब्दों में सबमुच कुछ नहीं रखा ?

जानना चाहना अवज्ञा करना नहीं । राष्ट्रगीतको सही-सही जानना हमारा नतिक कर्तव्य है । बिना ज्ञान की थढ़ा अग्रथढ़ा है ।

तमस दूर करने की सनद

(१) हालात ऐसे बन गये हैं कि कला और साहित्य को गुणवत्ता पर बहस के बजाय हावापाई करने की कट्टरपथी तत्त्व अपना सांस्कृतिक अधिकार मानने लगे हैं। अमहिष्णुता की इस सृष्टि का यदि प्रतिवाद न किया गया, तो अन्ततः कलाकर्म ही असम्भव हो जायेगा।

(२) साम्प्रदायिक कट्टरपथियों की ताकत में इजाफा होने के कारण सामाजिक-राजनीतिक हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुछ भोले भाले लोग, बल्कि सजग बुद्धिजीवीयों तक 'तमस' के प्रति आशक्ति हैं। यह हमारे सांस्कृतिक वातावरण को विपाक कर पाने में कट्टरपथियों की मिली सफलता का सूत्र है कि नव दरादे वाले लोग भी 'तमस' पर एकपक्षीयता का आरोप लगाने पाये जाते हैं।

(३) जरा देखें 'तमस' में ऐसा है क्या, जो कुछ लोग इसमें शोखता रहे हैं, तो कुछ आशक्ति हो रहे हैं। अब तक प्रचारित तीन 'एपिसोड्स' से साफ जाहिर होता है कि न केवल डा. यात बल्कि टी० धी० सीरियस के रूप में भी 'तमस' उस अँधेरे को टटोलने की ईमानदार, ध्येयापूण कोशिश है, जिसने हमारे राष्ट्रीय जीवन को आज घस

रखा है। जो लोग इस ढरावने अंधेरे को आज और भी घनीभूत बनाना चाहते हैं जिनका रोगमार ही राक्षसी सृष्टि का निर्माण करना है जो हमारी आत्मा को तमस (अंधकार) के ओर भी गहर कृशों में घकेल दना चाहत हैं, वे ही साथ टी० बी० सीरियल 'तमस' के खिलाफ हाम पर फेंक रहे हैं।

(४) 'तमस' को चिंता किसी सम्प्रदाय विशेष के सर ठीकरा फोड़ने की न होकर उस बालावरण को बहुस्तरीय परख करने की है। कोई भी समाज अपने इतिहास की उपेक्षा नहीं कर सकता। विभाजन स्वाधीन भारत की विकटतम आसदी है।

ऊपर के चारों अश पुरुषोत्तम अग्रवाल के 'बीबी दुनिया' के २१ जनवरी १९८८ के अंक में प्रकाशित लेख से उद्धृत है। इतना कह लेने की इजाजत हो कि खुद उन्होंने भी जितना जागरूक इससे कम भोला भाला बुद्धिजीवी होने का सबूत तो नहीं ही दिया है। उनके लेख में 'तमस' के दूरदशन पर प्रसारण का नेपथ्य नदारद है।

कला, भाषा अथवा विचार माध्यमों के प्रति साम्प्रदायिक, संस्थागत अथवा सरकारी आतंकवादी रवैया अपनाये जाने को सामाजिक जाहिलपन के तमस को और बढ़ाने वाला करार न्य जाने से असहमति की गुंजाइश सिर्फ उन्हीं लोगों में होगी, जो यस्त स्वाधों या साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से ग्रस्त हों। जिनमें यह चेतना नदारद है कि कला साहित्य अथवा विचार माध्यमों से प्रस्तुत काय कलापी का जवाब दिसकें हगामों, साठी भासे या छुरे विलूलों से नहीं बल्कि बहम से दिया जाना चाहिये। कलात्मक अथवा वैचारिक प्रस्तुतियाँ का जवाब हगामों से सिर्फ ऐसे जाहिल लोग ही दिया करते हैं जिनमें सामाजिक चेतना जितनी घुघली साम्प्रदायिक अथवा संस्थागत बटबुद्धि का तमस उतना ही घना होता है। जिनका सोच विचार विवेक और सधन हैं थोड़ा भी वास्ता हो, उन्हें कलामाध्यमों के

द्वारा प्रस्तुत वृत्ता तो का जवाब, तक और विचार स देने की तमीज सीखनी हाती है, क्योंकि गलत बातों का सही जवाब भी तक और विचार ही दिया जा सकता है। इस दृष्टि से देखें, तो 'तमस' के दूरदर्शन पर प्रसारण को लेकर जो हिंसात्मक हंगामा मचाया गया, उसे सचमुच जाहिलपन के अलावा कुछ नहीं कहा जाना चाहिये। लेकिन 'तमस' के मसले को जिस तरह पुरुषोत्तम अग्रवाल ने उठाया है, वह भी इस बुनियादी मुद्दे को अंधेरे में रखने की चलाकी की दल है कि 'तमस' के द्वारा इतिहास के सच को प्रस्तुत किय गये हाने के दावे में सचाई कितनी है।

चूँकि पुरुषोत्तम का लेख 'तमस' की पहली दो तीन किश्तों तक सीमित है, इसलिए उम्मीदवारों में बहम ठीक होगी। क्योंकि साम्प्रदायिक कट्टरपंथियों से लेकर, ढेर सारे भोले भाले लोगो तथा सजग बुद्ध जीवियों के 'तमस' के प्रति आशंकित होने का जो सवाल उ होन हवा में उछाला है, उसका दायरा सिर्फ 'तमस' के टी० बी० प्रसारण तक सीमित है—'तमस' का उपनाम रूप को लेकर कोई विवाद नहीं रहा है। लेकिन 'तमस' के प्रसारण से आशंकित होने के खतरे से पहले, खुद पुरुषोत्तम के निष्कर्षों में छिपे इस खतरे की ओर सबत करना जरूरी होगा कि जिस दूरदर्शन पर उ होने 'रामायण' का प्रसारण करके हिन्दू साम्प्रदायिकता फैला रहे होने का आरोप लगाया था, उसे ही 'तमस' के प्रसारण से साम्प्रदायिक एक्ता, साम्यवादी दृष्टि तथा अंधेरे को टटोलने की ईमानदार, व्यापार और चेतनामयपन्न बाणिज्यो में जुटा मिट्ट करने के भीलेपन में भी कुछ कम समझा नहीं। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' के औपनिषदिक आह्वान में निम्न पुरुषोत्तम की यह बात साफ भूल ही गई कि अभी कुछ ही वक्त पहले इसी 'दूरदर्शन' में 'रामायण' के प्रसारण के सिवाफ भक्ति भक्ति के उद्गारों की भी मुट ही इतनी दूर तक फैल पाई थी तब ही फेंक रहे थे कि 'रामायण' में सीता के हनुमान को पर पुरुष के रूप में

देवने का प्रमथ ही उ हैं उद्धरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंश दिखाई पड़ रहा था। क्या पुरुषोत्तम कहना चाहते हैं कि 'रामायण' का प्रसारण करके जो 'दूरदर्शन' हिंदू साम्प्रदायिकता फैला रहा था, उसने ही अब अपने पाप बम के परिहार में 'तमस' का प्रसारण शुरू कर दिया है? सज्जन ही नहीं किसी भोले भाले बुद्धिजीवी को भी इतना तुमुकमिज्ज ज नही ही होना चाहिये कि खुद की तुष्टि का सवाल मुख्य हो जाय, स्थितियों को पूरापर, दोनों पक्षों में देखने का विवेक और धैर्य गौण।

पुरुषोत्तम ने 'तमस' की तीन किशता व प्रसारण से ही साम्प्रदायिकता का तमस छूट गये होने का दावा किया है। क्या दूरदर्शन के सूत्रधारों का भी यही खयाल है? क्या भारत सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से साम्प्रदायिक वद्वेषपयियों की ताकत में इजाफा करने वाले सम जिक राजनीतिक कारणों को ध्वस्त करने का पक्का इरादा कर लिया है? पुरुषोत्तम के लेख से स्पष्ट नहीं होता कि वो दूरदर्शन को किसी राजनीतिक ताकत के माध्यम मानते हैं या नहीं। और अगर मानते हैं तो उस राजनीतिक ताकत को क्या मानते हैं—सम्प्रदायवाद को बढ़ावा देने, या कि इसे पक्के इरादे के साथ ध्वस्त करने वाली?

जैसे कोई फनहा बच्चा मनपसंद झुनझुना या लिलीना पाते ही उत्फुल्ल हो उठता, और खुद की उत्फुल्लता को पूरी ताकत से हवा में उछालना शुरू कर देता है—ठीक वही हाल शायद, पुरुषोत्तम का 'रामायण' से हिंदू साम्प्रदायिकता फैलाने के षडयंत्र को ध्वस्त करने के इरादे से सरकारनियंत्रित माध्यम दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत 'तमस' व प्रसारण से हो गया। जस कोई मनमानी मुराद या जाने पर पिछले सारे गिले शिक्कों को सिरे से झूल जाय, पुरुषोत्तम भी झूल गये हैं। उन्होंने इस सवाल से गुजरने की कोशिश नहीं की कि आखिर इन चर्च दिनों में ही दूरदर्शन के चरित्र में ऐसा अंतिकारी परिवर्तन क्यों हो गया? भारत सरकार को 'रामायण' के प्रसारण से हिंदू

साम्प्रदायिक चेतना को बिस्तार और बिस्फोट का मौका मिल रहे होने के खतरों से आगाह आखिर किसने कर दिया अचानक ही ? देश को भोले-भासे लोगो ही नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम—जैसे साम्प्रदायिक बुद्धिजीवियों के भीतर का भी तनस छूटने का अभियान भारत सरकार ने क्या यो ही शुरू कर दिया ? और यह भी ठीक ऐसे वक्त में, जबकि मेरठ दिल्ली के दंगों और राम बाबरी मस्जिद के उपद्रवों की धूल ठीक से नीचे बैठ भी नहीं पा रही ? एक तरफ 'रामायण' और दूसरी तरफ 'तमस' के प्रसारण का करिश्मा क्या शुद्ध संयोग मान है ?

'तमस' के टी० वी० प्रसारण से जो परमसुष्टि पुरुषोत्तम के वाक्यों में फूटी पड़ रही है वह इस घात का सबूत है कि व्यवस्था के एक से हिंदुओं और दूसरे हाथ से मुसलमानों की सुष्टि की जादुई गैद उछालने से न सिर्फ लाखों लाख भोले भासे, बल्कि पुरुषोत्तम जैसे 'उत्तिष्ठ जाग्रत वरान्निबोध' की लसकार लगाने वाले परमसुष्टिजीवी भी दिग्भ्रमित हो सकते हैं। अथवा पुरुषोत्तम भारत सरकार की बेरा के सरकार-नियंत्रित दृश्य माध्यम पर पहली बार ऐसा प्रयत्न दिखाया जा रहा है जो साम्प्रदायिक हिंसा को अनाम अमृत असामाजिक तरीकों की जिम्मेदारी ठहरा कर पस्ला नहीं झाड़ सैता है।^१—जैसी मूल सनद यमाते हुए, हमें भी इतना बताते जरूर कि ऐसा देश की सरकार ने पहली ही बार क्यों किया है ? और कि आगे भी ऐसा (ही) करती रहेगी या यही आखिरी बार होगा ?

'रामायण' का प्रसारण भी तो आखिर दश की सरकार ने पहली बार किया है ? जबकि जहाँ तक दूरदशन से देश की विभाजन की त्रासनी को प्रस्तुत करने का सवाल है उसे 'युनियास' में 'तमस' से पहले प्रस्तुत किया जा चुका। हाँकि वहाँ इतिहास के सत्य का स्वरूप मिश्र था।

अकारण कुछ नहीं होता। पुण्योत्तम को बताना चाहिये कि देश की सरकार ने पहली बार ऐसा क्रांतिकारी कदम क्यों उठाया है? वो कुछ नहीं बताते कि साम्प्रदायिक हिंसा को अनाम अमृत असामाजिक तत्वों की जिम्मेदारी ठहराकर पस्ला भाव लेने से बचते हुए, देश की सरकार ने किन नामधारी या मृत तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि अगर देखें दावा यह भी किया है अपने लेख में कि अब तक अमृत ही चली आ रही साम्प्रदायिक ताज्जुबों को पहली बार 'तमस' के प्रसारण के माध्यम से नगा किया गया है, और इसी से साम्प्रदायिकता के तमस के रखवाले बीखला उठे हैं। किंतु जिन आयतमाज, स्वयंसेवक संघ या मुस्लिम लीग—जैसे संगठनों को उद्देश्य साम्प्रदायिकता के करार दिया है, ये संगठन तो 'तमस' के प्रसारण के पहले से ही मृत रहे हैं। साफ है कि यह मृत को अमूर्त बनाकर फिर उसे पहली बार मूर्त किये गए होने का अर्थ सूटने की थोड़ीक चालाकी के सिवा और कुछ नहीं।

इस बात की ओर फिर इंगित जरूरी होगा कि 'इस देश के सरकार नियंत्रित दृश्य माध्यम पर' की सनद साया करत हुए पुण्योत्तम ने, निहायत भोले भाले ढंग से, कायसी हुकूमत की विरासतदार मौजूदा सरकार को साम्प्रदायिक हिंसा की जिम्मेदारी से साफ धरी कर दिया। पुण्योत्तम के दावे से तो कुछ ऐसा आभास भी मिलता है कि देश के सरकार नियंत्रित दृश्य माध्यम पर दो अलग अलग सरकारों का बज्जा एक साथ है। जब तक मे एक सरकार हिंदू साम्प्रदायिकता को उत्प्रेरित करने और हिंदू पुनरुत्थानवाद की आग भड़काने के लिए 'रामायण चलाती है, तब तक मे दूसरी, साम्प्रदायिक हिंसा का गहरा तमम छांटकर, देश के लोगों के हृदयों को हिंदू मुस्लिम एकता की रोगनी से क्लिन्नमिला देने के लिए तमस का प्रसारण शुरू कर रही है।

और चूंकि दृश्य माध्यम सिर्फ एक ही है इसलिए रविवार शनिवार पर समझौता कर लिया जाता है। (जाहिर है कि पहली सरकार

दक्षिण, दूसरी वामपथी है ।) इस बौद्धिक भोलेपन पर कौन बलिहारी नहीं जायेगा ।

अब आएं पुरुषोत्तम के इस कथन पर कि—'कोई भी' समाज अपने इतिहास की उपेक्षा नहीं कर सकता । विभाजन स्वाधीन भारत की विकट आसदी है । पहली बात यह कि इतिहास और साहित्य क सच तथ्यों के स्तर पर काफी कुछ समान होते भी, अपन गुणात्मक प्रतिफलन में ज्यों-के-त्या कभी नहीं होय । फिर भी पुरुषोत्तम का आग्रह यदि तमस के द्वारा अपने समय समाज के इतिहास के प्रतिनिधित्व का हो, तो भी कुछ सवाल जरूरी होंगे । मसलत 'तमस' की जिन दो तीन किशतों के प्रमार्ण पर पुरुषोत्तम ने बहस उठाई, क्या य मधुमुख विभाजन की आसदी का कोई सम्यक् चित्र सामने रखती है ? 'तमस' ने क्या-क्या किया है, इसकी एक जो तम्बी तफसील उ होने अपने लेख में दी, वह 'तमस' उप यास का जितना हो, 'तमस' सीरियल का सच नहीं है । जबकि इतिहास का हो या साहित्य का, कोई भी सच किसी स्थान, काल के बीच और किसी कारण घटित होता है और इनकी आधी अधूरी या इतरफा प्रस्तुति स सच नहीं, बल्कि मिथ सत्याभास सामने आता है ।

'तमस' के दूरदर्शनी प्रसारण में इतिहास का यह सच पूरी तरह नदारद है कि विभाजन की साजिश को अजाम देने में कांग्रेस का बहु सततकालीन नेता वग सयसे ज्यादा साक्षायित था, जिसके अगुवा प० जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी नहीं । इसलिये 'तमस' में इतिहास का भी तथ्याकथित सच चंद कलत्रियों में है, इ हें लेकर विभाजन की आसदी उपस्थित किये, या अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों को एक सृजनात्मक मोड़ दे दिये गए होने का दावा ठीक नहीं । दूसरे, इन किशतों का इतिहास विभाजन की आसदी नहीं, विभाजन के दस्तावेजों पर दस्तखत होने से पूर्व के साम्प्रदायिक दंगों और इसके प्रति अनेक साहस बहादुरों के बहिष्कार रवय मात्र तक सीमित है ।

वकालत में पुरुषोत्तम ने ऐसा बहुत कुछ अपनी ओर स घोष किया है, जो 'तमस' सीरियल के बराबर में नहीं है।

अब देखना यह है कि हिंदू मुस्लिम दंगा की तैयारियाँ तथा उनके विस्फोट की जो भनकियाँ निहलानी ने प्रस्तुत की, वो इतिहास के सच की कितनी सामने रखती हैं। और कि इन किशतों में ऐम आगतिजनक वो मुद्दे क्या रहे हैं, जिनकी लेकर कि दंगामें लड़े किए गये।

इन किशतों का बयापटल पुरुषोत्तम सामने रख चुके, दोहराने की जरूरत नहीं। इनके द्वारा विभाजन की दासदी का सृजनात्मक मोड़ देने का सवाल ही नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगों की पृष्ठभूमि और क्रिया श्रितिके की निहायत भाँड़े अछूरे परिदृश्य ही सामने उभर पाते हैं। निहलानी इस सवाल को हाथ लगाते ही नहीं कि विभाजन के जिम्मे वार सत्त्व कौन थे। क्योंकि उन्हें पता है कि इस सवाल को छूते ही 'तमस' के दूरदर्शन पर प्रसारण की गुंजाइश खत्म हो जायेगी। वो जानते हैं कि विभाजन के दस्तावेजों पर भारत की ओर से आयसमाग या स्वयसेवक सघ के सचवासकों के नहीं, बल्कि अग्रेजों की बिरासतदार काग्रेसी हुक्मत के झण्डाबंदारों के दस्तखत मौजूद हैं। उन्हें सीमा कहा जा सकता था, लेकिन पुरुषोत्तम के दावे यह गुंजाइश नहीं छोड़ते। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि 'तमस' में इतिहास का सच प्रस्तुत किया गया है। जबकि 'तमस' का सारा दृश्यविधान सिर्फ साम्प्रदायिक बदरता और सामुदायिक सोमनस्य के फिल्मी प्रतिबिम्बन पर टिका हुआ है। और हकीकत तो यह है कि इतिहास के सच को आँख से ओझल करने की चालाकी निहलानी में चाहे जितनी हो लेकिन इतिहास की या तो समझ ही नहीं, या वैसा साहस या कलागिद्धि गायब है जो कांग्रेसी हुक्मत की आँखों में घूल भोंक सके। इसलिये अब दावा हो तो यह सवाल भी जरूर बनता है कि जो भनकियाँ सामने आती हैं, क्या वे एक ईमानदार और प्रासंगिक

कोशिश है ? क्या इनमें इतिहास के सच को इतिहास सच के रूप में ही प्रस्तुत करने की प्रतिश्रुति वास्तव में भूलकदी है ?

जो, नहीं, कतई नहीं ! यह सिर्फ पुरुषोत्तम की खामखयालियों और आग्रही वृत्ति में से फूटा उच्छ्वास मात्र है, जो विभाजन की त्रासदी से जुड़े नाना प्रसंगों से लेकर, ५० जवाहर लास नेहरू के पुण्य स्मरण तक का घटाटोप तानते हुए, ऊपरी तौर पर अत्यंत ही भोला-भासा और सुंदर, किंतु अव्यक्त में निहायत ही खोखल तकजास बुनता है ।

'तमस' की प्रारम्भिक किशो में निहलानी ने चौधरी महमूद अली के सुअरमेघ की रचना जितने प्रतीकात्मक ढंग से की है, हिंदू समुदाय की दंगों की तयारियों, शास्त्र से लेकर शास्त्रों तक की हिंसात्मक दीक्षाओं तथा इनके त्रियात्मक प्रतिफलन की दृश्यावली को उतने की स्थूल रूप में दिखाया है । इन तीन किशो का कुल निचोड़ यही है कि दंगा की व्यापक स्तर पर पूरा कियाजित तयारियों और कत्लों के सिलसिले की पहल हिंदू समुदाय ने की ।

पुरुषोत्तम का यह दावा शरीहून झूठ है कि 'तमस' की इन शुरुआती किशो की चिंता हिंदू या मुस्लिम, किसी भी समुदाय विशेष के मध्ये ठीकरा फोड़ने का नहीं, बल्कि वातावरण की बहुस्तरीय परत की रही है । क्या वो बतायेंगे कि जिनको दंगों की तयारी और शुद्धांत करते दिखाया गया, वो हिंदू नहीं, तो किस समुदाय के हैं ? अगर पुरुषोत्तम का तक हो कि उसमें सिर्फ पृथ्वी अंतरिक्ष से लेकर धनस्पति जगत तक की शांति का पाठ करते हुए युद्धस्तर पर मोर्चे की तयारियाँ करते आग्रहमाजियों तथा कुक्कुटवध की दीक्षा देकर, मुसलमानों को भी ठीक वैसे ही कत्ल करने का गुरुमंत्र देने वाले खाकी निष्कर्षियों की ओर मूस सकेत हैं, तो यह जवाब भी उह ही देना होगा कि क्या [ये हिंदू समुदाय नहीं ? या कि क्या मुसलमान अध्यापक की रक्षा को व्याकुल एक अकाली ओरत ही सार हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व

करती है ? क्या कि इन किशतों में सिर्फ वही अकेली औरत पड़ोसी मुसलमानों की रक्षा में क्रियात्मक हिस्सा लेती है, हिंदू समुदाय नहीं।

और अगर हिंदू समुदाय की साम्प्रदायिक सदाशयता का प्रतिनिधित्व के लिए इतना ही पर्याप्त है तब मुस्लिमों की राजिनाम में मुसलमानों होकर भी सुधार का कर्म करवाने वाले खीधरी मटमूद अली का मुस्लिम समुदाय की साम्प्रदायिक हिंसावृत्ति का प्रतिनिधि किस तक से नहीं बना जायगा ?

हालांकि पूरे सीरियल में निहलानी ने इस तथ्य को निहायत कलात्मक चतुराई के साथ व्यमूर्त्त ही रखा कि सुअर मरवाने वाला खीधरी मुसलमान है। क्योंकि अगर यह स्पष्ट हो जाता, तो खुद का मजहब का विरुद्ध सुअर मरवाकर दगा भटवान की तात्कालिक मुस्लिम साम्प्रदाय पर आ जाती। और पुष्पोत्तम का दावा है कि किसी समुदाय विशेष पर ठीकरा नहीं फोड़ा गया बल्कि विभाजन की आसदी का एक सागाताग इतिहास अवस्थित करते हुए—अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को एक सजनात्मक मोड़ देने की क्रांतिकारी पहल की गई है।

भीष्म जी साम्प्रदायवादी नहीं और न उनके साहित्य में कहीं साम्प्रदायिक संकीर्णता का जहर का कोई स्पष्ट भ्रमकता है। कम्युनिज्म के सिद्धांत और कम्युनिस्ट पार्टियों की इतिहास के साथ सबाहुर जाकर भी पैरवी करने की सशयता उनमें चाहे जितनी मौजूद हो। लेकिन परिस्थितियों के दबाव महापुरुषों तक को ढिगा देते हैं। तमस' का दूरक्षण पर प्रमाण से मिलने वाले लाभों के दबाव में, भीष्म जी ने इस ओर से आखिरी फेर ली है कि सीरियल का इस्तमाल काप्रेसी, हुक्मन को दश के विभाजन का कलक से बरी करन का इरादा में हो रहा है। इसलिये जो बात 'तमस' उपयास, ठीक यही बात 'तमस' की निहलानी द्वारा हुई दूरदर्शनी प्रस्तुति के बारे में नहीं कही जा सकती, क्योंकि इराद नेक हों, तो भी स्वतः सिद्ध नहीं हुआ करते। उन्हें काय में भी सिद्ध करना जरूरी होता है। दशकों के लिये निहलानी का मनो

गत इत्यादि नहीं, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत इन दूरदशनी किरती का यथायही 'तमस' सीरिष्य का यथाय है और यह यथाय झूठ से भरा तथा निहायत ही खतरनाक है, क्योंकि यह प्रतीक और स्थूल दृश्यों का एक ऐसा मायावी समीकरण तैयार करता है, जिसकी गद बहुत दूर तक जाती है। इन किरता में देश व विभाजन की विवदतम त्रासदी का ठोकरा ही नहीं, बल्कि पूरा झूठा, साफ तौर पर, सबसे ज्यादा हिंदू समूहों के माथे पर ही फूटता है, कांग्रेसी हुक्ममत नहीं।

क्योंकि इतिहास का सच अगर यही हो कि दगो और फत्तो की पहल हिंदुओं का ओर से हुई, तो मुसलमानों के पास पाकिस्तान माँगने के सिवा और कोई विकल्प ही कहाँ बचा? आत्मरक्षा हर हाल में जायज है।

इतना ही नहीं, यदि निहलानी द्वारा प्रस्तुत यथाय वास्तव में इतिहास का सच है, तो विभाजन का जिम्मेदारी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों अथवा कांग्रेस या मुस्लिमलीग के ऊपर नहीं डाली जा सकती। तब देश के विभाजन की पूरी जिम्मेदारी उन हिंदू समुदायों पर आवेग होती है, जो एक ओर सातिपाठ तथा दूसरी ओर विधिमियों की मुगिमी की तरह काट दिये जान के बबर दीक्षा-समारोह आयोजित करते हैं। हम फिर कहेंगे, अगर इतिहास का सच यही है कि दगो और फत्तो की पहल हिंदू समुदाय ने की, तो निहलानी सचमुच पूरे देश के आधार व पात्र हैं।

कला की सिद्धि इतिहास के सच को तोड़ने मरोड़ने से बचाने में ही है, क्योंकि इतिहास को झुठला करके देश, काल और समाज के सच को उजागर नहीं किया जा सकता। जब किसी साहित्य, विचार या कला माध्यम के द्वारा इतिहास की प्रस्तुति का उद्यम हो, उस समय की राज्य व्यवस्था के निहित स्वार्थों के बहुत गहरे दबाव इस पर पड़ा करते हैं। इसलिये अगर निहलानी ने कांग्रेसी हुक्ममत की

आप बचाकर उसके ही माध्यम में इतिहास का सच प्रस्तुत किया, तो यह हिंदू मुसलमान, दोनों के हित में ही कहा जा सकता है और इस सच से सबक लिया जाना चाहिए। जिन समाजों में सच की ताकत न हो, उनका क्षय निश्चित है। निह्तानी ने जोखिम भरेर इतिहास के कलात्मक प्रतिबिम्बन में हमारे सोच-सुवेदन को एक सजनात्मक मोड़ देने और तमस छीटने का क्रांतिकारी कार्य किया है, तो हमें बृत्तन होना ही चाहिए। लेकिन सवाल फिर यही—इतिहास का सच क्या सचमुच यही है ?

यहाँ एक बात का ध्यान जरूरी होगा कि इतिहास हो कि पाहित्य, किसी भी सच का सवाल समाज के हित के ऊपर का सवाल नहीं। जिसमें समाज की क्षति हो, वह हरहाल में झूठ है। इसलिए वैसे भी सच को अभिव्यक्ति देते में समाज-हित का सवाल केन्द्र में रखना जरूरी है। इस दृष्टि में देखने पर परिणाम शून्य ही मिलेगा। महतानी की इन प्रस्तुतियों से सिर्फ विवाद खड़ा हुआ, इतिहास के सच या विभाजन की त्रासदी के बुनियादी सवाल में जाने की प्रेरणा नहीं मिली। 'तमस' में लोगो के सोच-विचार को सजनात्मक मोड़ देने की कुशल खोजना, शाखाशृंगों की भाँति में बस्तूरी खोजना है। तमस सोरियल की उपस्थिति लोगो की चेतना को सिनेमाई इज्जाल में जकड़ने तक सीमित रही है।

हम पुष्पोत्तम की विभाजन की प्रामाणी पर टी०बी० माध्यम की पहली प्रस्तुति 'बुनियाद' की याद फिर दिलाना चाहेंगे जिसमें कि इतिहास के इस सच की एक दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया था। तब रतियाराम गुट्टु की तबाही का सच क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय और पाकिस्तान का मंच था ? और कि क्या तब इस देश के स्वयं-माध्यम पर सिर्फ पाकिस्तान का मंच प्रस्तुत किया गया था—'गोर' का ऐतिहासिक मंच ?

स्वयं के खतरे बड़ी कम नहीं हुआ करता। पुष्पोत्तम की

कोन समझाये कि निहलानी ने यह खतरा अनजाने भोज नहीं लिया, जान बूझकर उत्पन्न किया। बाद की किशतो में क्या हाना है, इससे शुरू की तीन किशतो की हकीकत में कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जो पहले मारे, सो मीर ! ' मुहावरा साम्प्रदायिक हिंसा में पहने को शाबासी नहीं, राष्ट्रीय शम की वस्तु बनाता है। और इन किशतो में इस राष्ट्रीय जम के कोसतार की काँग्रोसी हुकूमत के चेहरे पर स पोंछकर हिंदुओं पर बड़े फिल्मी अंदाज में पोता गया है।

इतिहास के सच पर फिल्म बनाना एक बात है इतिहास की फिल्मी बनाना बिल्कुल दूसरी बात। निहलानी दूसरी श्रेणी का फिल्मकार है।

'आक्रोश' — जस आदिवासियों के जीवनसंघर्ष पर आधारित फिल्म में भी उनकी लिपि ओमपुरी और स्मिता पाटिल के मिथुन कम की हॉलीवुड की तज पर 'हाइलाइट' करने पर ज्यादा थी, आदिवासियों के शोषकों की बेनकाब करने पर कम। यहाँ भी नत्थू चमार जिस ढंग से अपनी बीबी से साठ लड़ाता है, वह फिल्मों के हीरो हीरोइन की बेलिक्ला का करिश्मा ज्यादा प्रस्तुत करता है, 'तमस' उपन्यास के नत्थू चमार के जीवन की नासदी को उतना नहीं।

'तमस' मीरिंगल के प्रारम्भिक किशतो में निहायत सूक्ष्म रूप से हिंदुओं का साम्प्रदायिक दंगे और कत्लों की योजनाबद्ध पहल करने वाला बताया गया और हंगामा इसी बात पर ज्यादा हुआ। इतना ही नहीं, निहलानी ने, गुजरमेध की ही तज में, हिंदूराष्ट्र की शोषा से म प्रविष्ट हिंदू किशोरों का द्वारा मुर्गों से लेकर मुस्लिम फरींग के चकर बरत तक के दृश्या को जिस सनसनीधर फिल्मों के तज में प्रस्तुत किया, वह सिर्फ खाकी निबकर पहनने वाले बट्टरपयियों ही नहीं, बल्कि हिंदू मात के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाला है।

जिन आर्थिक-सामाजिक अथवा राजनैतिक कारणों से साम्प्रदा-

यिकता का जहर पनपता और फूटता है, उनको पर्दे के पीछे रखकर इस तरह के बबर दृश्य दिखाना, सिवा नफरत उत्पन्न करने के और कुछ नहीं करता। इस तरह के कुत्सित नज़ारों को बिना इनक पाछे निहित ऐतिहासिक तथ्यों के ही प्रस्तुत करना, तमस छाटना नहीं इरादतन हिंदू समाज के मुँह पर कोसतार पोतने की कोशिश करना है। मुअर से लेकर मुस्लिम फकीर की बबर हत्या तक में हिंदुओं को मुसलमानों से पहले शामिल दिखाना, यह इतिहास का सच नहीं गोप्य ब निहलानी का अद्वयसत्य है और इस पर सबसे पहले भीष्मजी का गतराज होना चाहिए था। अफसास कि नहीं हुआ।

यही नहीं, 'तमस' में बिताबा का जलान का काम करते भी सिर्फ हिंदुओं को दिवाया गया है, जबकि इतिहास का सच सिर्फ अमृतसर घात घर ही नहीं, लाहौर रावलपिण्डी और कराची का सच भी रहा है। जसा कि पहले भी कहा, इतिहास या साहित्य, किसी के भी सच को दिखाने की पहली शत उसके समाज, काल और वारणों को समग्रता में दिखाना है। निहलानी में सच का उसके पूरा पर अंगों के आलोक में दिखाने की यह तमीज सिर से नदारद है। अ यथा क्या यह असम्भव है कि बिभाजन की त्रासदी के दौर में किसी हिंदू अध्यापक के घर की बिताबों की मुसलमान दगाइयों के द्वारा आग लगा दी गयी हो और वह भी निहलानी के फिल्मी अंश में 'देखिय, यह रहा अमीर खुसरो का अदब, यह दीवाने गालिब, यह मीर साहब और दाग ब्रफर-जिगर मुरादाबादी फज का बलाग खोजता रह जाय ?

पुरुषोत्तम ने अपन लेख में, रोमिला थापर के हवाले से भी कुछ ऐसा दृश्य रचा है, जैसे बिताबें जलाने का काम सिर्फ हिंदू ही करते आ रहे हों। जबकि बिताबें सिर्फ दिल्ली पंजाब ही नहीं, रुस चीन पास ईरान, तूरान पाकिस्तान और जमनी-जापान आदि मुल्कों में जलायी गई हैं। सिर्फ हिंदुओं के द्वारा जलायी गई बिताबों की

फेहरिश्त हवा में उछालना सजग नहीं बल्कि पूवग्रहग्रस्त बुद्धिजीवी होने का सबूत देना है।

साम्प्रदायिक हिंसा बबरो जाहिन्को की चीज है, लेकिन खेद कि पुष्पोत्तम हर बार सिर्फ हिंदू साम्प्रदायिकता को सताड़ते हैं और रामलीला की परम्परा तक में उन्हें हिंदू पुनरुत्थानवाद की भग को जगाये रखने की साजिश दिखाई पड़ती है। यदि रामायण के नित्यपाठ या रामलीला के वार्षिक अनुष्ठानों से हिंदू पुनरुत्थान पर साम्प्रदायिक खपीर चढ़ाये जाने की साजिश माबित होती हो, तब यही स्थिति गिरिजाधरा, गुरुद्वारो और मस्जिदों में बाइबिल, ग्रंथ माहिव और कुरान पाक के नित्यपाठ से क्यों नहीं बनेगी, इस मद्द्ग में पुष्पोत्तम को कोई दिलचस्पी नहीं। सिर्फ एक घड़े पर साम्प्रदायिक हिंसावृत्ति का इलजाम थोपना, दूसरे घड़ों की साम्प्रदायिकता की पीठ धपपवाना है और यह पद्धति पार्टी-सिद्धांतों के काम की जाहे जितनी हो। इससे हिंदू और मुसलमान के बीच की बंदारों का दर होना सम्भव नहीं। साम्प्रदायिकता मात्र रो लाछित और उजागर करके ही साम्प्रदायिक तमस छोटने की जमीन तैयार की जा सकती है। एकतरफा बकालत तो साम्प्रदायिक कटटरपणियों की मुहिम को ही और खुराक पहुँचायेगी।

एक सवाल पुष्पोत्तम से और पूछ लेने में कोई हज नहीं। तमस' के साथ लेखक के रूप में भीष्म जी का न होकर, अज्ञेय या जनेद्र जी का नाम हुआ होता, तो भी उनकी प्रतिक्रिया यही होती? या वो कहे कि अगर भीष्म जी पार्टी से जुड़े नहीं होते, तो भी?

हाँ जहाँ तक 'तमस' के प्रसारण को लेकर दूरदर्शन के द्रों पर हल्ला बोलने वाला का सवाल है, उसमें भावावेग में शामिल होने वाले तो कई भोले भाने लोग भी जरूर हो सकते हैं लेकिन हिंसक जत्थों का संगठन और नेतृत्व करने वालों को तो सिवा जाहिल के और कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी साहित्यिक वैचारिक या

वत्सात्मक प्रस्तुति के बारे में कुछ भी विवाद बहस के तौर पर हाँ उठाया जाना चाहिए। निष्णोयक स्तर पर कुछ भी तभी तो कहा जा सकता है—और तभी कहा भी जाना चाहिए—जब बात पूरे तौर पर सामने आ चुकी हो। जिनमें किसी वस्तु का ध्यान और धैर्य से देखन का विवेक नदारद हो, वो कभी भी कोई 'प्रासंगिक' कदम उठा ही नहीं सकते। दूरदर्शन, रेडियो या अखबारों में की सामग्री का दखते ही गुस्से से बीखला कर हंगामा खड़ा कर देने वाले लोग समाज या देश के हित में सकारात्मक ढंग से कुछ सोचने विचारने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ऐसे लोग किसी भी समाज के लिए सिर्फ सनरनाक ही सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये भेद या भेदियनों की ही स्तरों पर दूसरों के इशारों पर हंगामा खड़ा करते हैं। पुण्योत्तम की भी, शायद, इतना ज़हर याद होगा कि 'खून का बदला, खून से लेंगे।' का प्रसारण भी देश के इसी सरकारी दृश्य माध्यम पर हुआ था। (और जहाँ तक याद आता है, शायद, पहली ही बार।) नतीजे हम देख चुके हैं।

इसमें क्या शक कि यह हिंदू समाज की संवेदना में तेज़ी से क्षय का दौर है। सहिष्णुता और समरसता के जिस अनन्य गुण ने भारत को वैदिक से लेकर गंगा जमुनी सभ्यता तथा संस्कृति तक का विरासतदार बनाया उसमें गहरी दरारें आ चुकी हैं। लोगों की धर्माग्रता की अर्धी गलियों की तरफ हँकने वाले संगठनों की ताकत में बढ़ोत्तरी हिंदू समाज की भयावह घाति है, क्योंकि यह एक उदात्त समज की आत्मिक शक्ति के ढूँढ़ रहे ज्ञान का लक्षण है। लेकिन अफसोस कि पुण्योत्तम—जैसे सजग बुद्धिजीवी भी इस खतरे का और बढ़ान में ही हाथ बँटा रहे हैं। देश के विभाजन की ज़ामनी अथवा साम्प्रदायिकता के खतरों की उनकी समझ निहायत सतही है क्योंकि वो इसकी जड़ें सिर्फ हिंदू अथवा मुस्लिम कट्टरतावादी संगठनों में ही ढूँढ़ रहे हैं। रहने की बौद्धिक सजगता की श्रेणी में गिनना चाहें

हैं। उस तयारकथित धमनिरपेक्ष व्यवस्था की तरफ उनकी आस कतरि नहीं उठनी, जो साम्प्रदायिकता का सबसे बड़ा शक्तिकेंद्र है। वा इस सचाई को पूरी तरह ओझल कर जाते हैं कि अगर 'तमस' क विभाजन की तासदी के वास्तविक बुनकरो पर रोशनी ढाली गई होती, तो इसे सामा य तौर पर फीचर फिल्म के रूप में सायजानिक सिनेमाघरो तक में प्रश्रन की अनुमति नहीं मिली होती, सेंसर बोर्ड से—परकार नियंत्रित दृश्य माध्यम दूरदशन की ब त ही बेकार है।

क्या पुरुषोत्तम नहीं जानते कि आयममाज या स्वयसेवक सघ जैसे हिंदू कट्टरवादी सगठनों की निर्णायक शक्तियों की हैसियत न विभाजन का मुद्दा तय करते वक्त थी और न ही आज केन्द्र में हिंदू कट्टरपंथी सरकार सत्ता पर है। ऐसे में देश के विभाजन की त्रासदी की बात हो, या आज के हिंदू मुस्लिम दंगों की, जिम्मेदारी कांग्रेसी हुकूमत के मत्थे पर ढाली जानी चाहिये थी, क्योंकि हकीकत यही है। 'तमस सीरियल में इतिहास के इस सच से साफ इकार है।

जो लोग 'तमस' सीरियल में हिंदू मुस्लिम दंगों और सामुदायिक सौमनस्य के दृश्यों की उष्चकोटि की कलात्मक प्रस्तुतियों का भुनभुना बजाते नहीं सकते, उन्हें इतना बताना जरूरी होगा कि जब दावा इतिहास के सच को प्रस्तुत किये गये होन का हो तो उन कलात्मक प्रस्तुतियों की कोई प्रासंगिकता नहीं, जो सच पर पर्दा तानती हो। जब दावा इतिहास के सच का हो, तब बहम भी इसी पर होगी। होनी चाहिये। ऐसे में पुन इतना कहने की शमा किया जाय कि पुरुषोत्तम की 'तमस' की समझ निहायत बोदी है, क्योंकि 'तमस' के टी०वी० प्रसारण के मुद्दे को जिस ढंग से उ होन उठ या इससे विभाजन की तासदी और साम्प्रदायिक हिंसा के आरोपो में बरी होने की मनद उन लोगों के हाथ आई, जो कि नमस के सबसे बड़े रखवाले हैं।

इतिहास का सच इतना आसान नहीं, जितना पुष्पोत्तम ममल बंटे । देश के विभाजन के इतिहास की प्रस्तुति उसी कांग्रेसी हुकूमत के नियंत्रित तथा माध्यम में सम्भव हो नहीं, जिसके अग्रूठ की छाप सत्ता हस्तांतरण के दस्तावेजों में आज भी मौजूद मिलेगी । इतिहास की तरफ भागने पर इतना साफ दिखाई दे जायेगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विघटन स्वाधीनता के संग्राम के इतिहास में जो भूमिका भारत की जनता की है, ठीक वही उन कांग्रेसी नेताओं की नहीं, जिन्होंने अखिर महात्मा गांधी तक को हाथियार पर कर दिया और सत्ता की हथियार में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ लौटेबाजी करके, देश की दो टुकड़ों में बाँटकर रख दिया ।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि साम्प्रदायिक दंगों की आग देश के विभाजन पर सुली मुस्लिम लीग और खुद के निरन्तर हुकूमत की कुत्तियों पर टिकाने को व्याकुल कांग्रेसी नेताओं की साँठ गाँठ से फली थी । 'तमस सींगिल मे इतिहास का यह सच नकारद है । इसमें साम्प्रदायिकता का तमस दूर करने की सनद कांग्रेस के हाथों में यमान के विनिमय में ही भीष्म साहनी और गोविंद निहलानी दोनों कांग्रेसी हुकूमत के द्वारा पुरस्कृत भी किये गए हैं ।

राष्ट्रपति बनाम प्रधानमन्त्री

जगत में हर वस्तु के दो छोर हैं। अखबारनबीसी के भी। कागज इकट्ठरी चीज नहीं। काले कारनामों से लेकर महाकाव्यो तक जाती है इसकी परिधि। अक्षरानान से लेकर अखबारनबीसी तक, कागज उस हर व्याप्त सफेद काम को जहरी है जिसमें लिखत पढ़त जहरी हो। अखबारनबीसी को लें, तो इसके भी एक छोर पर नागरिक में चेतना जगाने की मुहिम हो सकती है, दूसरे पर मानसिक दाहून की। वहाँ, किम छोर पर गया है, यह जीवित चलने की जिम्मेदारी उसकी है जिसे वस्तु को बरतना है। वस्तु अखबार हो कि आलू। आदमी को तो अखबार ही नहीं, आलू को भी ध्यान से पढ़ना चाहिये। बिना पढ़े न अखबार की असमिपत समझ में आती है न आलू की।

अब अगर आप कहें कि अखबार पढ़ने का तरीका तो आपको बिल मुल आता है, आलू भी कोई पढ़ने की चीज है? हम कहेंगे आलू ही नहीं, अखबार भी खाने की चीज है। आदमी के सिफ पेट ही नहीं एक अन्द चेतनाजगत और मस्तिष्क भी है और मुराक की जरूरत प्रत्येक को है। जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, अपढ़ भी पढ़ना जरूर है। भाषा ही नहीं, भावना भी पढ़ी जाती है। आत्मी की बनावट समझना जरूरी

है। वह मौखिक ही नहीं, बानों से भी पड़ता है। जब कान भी साथ न दें, तो अनुमान से पड़ना है। आदमी चूँकि खुद एक निहायत ही घलती फिरती, सोचती समझती, लिखती बोलती चीज है, इसलिये वह आलू को भी बाकायदे लिख-पढ़ सकता है। लिखत पढ़त जुड़ है। जिस लिखा, उधे बाकायदे पढ़ा भी जा सकता है। जो आलू को नहीं पढ़ सके, या अक्षरार क्या पढ़गा? प्रेमचंद की कफन कहानी का आलू पढ़िये। आलू वही है जिस हथ वरतन हैं, मगर मतबल बहा नहीं।

कुछ भी ऐसा नहीं जा आदमी की लिखत पढ़न से बाहर हो। लिखत पढ़त के भी दो छोर हैं। सही ओर गलत। सच और झूठ। आदमी न भी दो छोर है। उसके रहन की जगह यानी देश व भा। इन दोनों में एक तरफ बहुत बड़ा फासला है दूसरी तरफ बिलकुल नजदीकी रिश्ता। हमारे रहन की जगह मडया से महादेशो तक जाती है। सवाल है यह कि हमारी चेतना की परिधिवाँ कहीं तक जाती है? क्योंकि आदमी की असली ओकात मडया और महल नहीं, बल्कि चेतना से तय होती है। चेतना कुछ है, तो कचनमहल में काठ का चरल है। चेतना जागृत है, तो मडया की मिटटी जगमग-जगमग। हमारी चेतना का हाल क्या है?

एक मुहावरा है—घर भरना। अब घर भरने की फिज में अगर इससे हमें कोई वास्ता ही नहीं रहे कि हमारे देश और समाज के वातावरण में क्या भर रहा है, तो यह किस बात का सबूत होगा? घर में कितना भी माल मत्ता या सुंदरता भरने से कुछ नहीं होगा अगर कि बाहर दरिद्रता और प्रदूषण का राज रहे। घर के अंगिन में आसमान तक की स्वच्छता चाहिये आदमी को। सिर्फ ~~जगमग~~ पर सगमरमरी बनान से कुछ नहीं ~~जगमग~~ जमान रहे। जो पूरे देश को ~~जगमग~~ से उदासीन हों वो एक ~~जगमग~~ जगमग तब काटरबद्ध सोग ही

जगमग भरना

जगमग के

कभी -

डासते

चारदीवारी से बाहर की चिंता न करने वाले ही पूर देश में चरित्र का सकट उत्पन्न करते हैं। क्या हमने कभी 'म' चिंता में जाने की कोशिश की कि हमारे कायकलापो का असर कहाँ तक जायगा? यानी कि अगर हम सिर्फ खुद व निहित स्वार्थों तक ही सीमित हैं, तो दूसरों को क्यों गरज हो कि वा हमारा ध्यान रखें?

आज यह एक दूसरे का ध्यान न रखने का सिलसिला अगल-बगल, अडोस पडास, गली मोहल्ले, गांव कस्बे और नगर महानगरो तक होता पूर राष्ट्र में क्यों कायम हो गया है, ये कुछ हमारे व्यावहारिक जीवन के नितांत जरूरी सवाल हैं और इतना देखते चलना बहुत जरूरी है कि कौन हमें इन बातों का ध्यान निलाते चल रहा है—कौन इनसे बेखबर रखता हुआ। इस छोटी सी बात में व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक के सारे जरूरी सवाल छिपे हैं। जरूरत सिर्फ इतना ध्यान से पढ़ने और समझने की है। कागज पर की लिखत पढ़त अगर हमारी समझ के झरोखे खुले रखने में मदद न दे रही हो, तो साफ है कि कागज से चेतना के कपाट बंद करने का काम लिया जा रहा है। हमारे अलबत्ता नबीस कागज से क्या काम ले रहे हैं।

असवारनबीसों का मुख्य काम है—टां छोरों की मिलाना। लिखने और पढ़ने वालों के बीच सेतु रचना। हमें बताते चलना कि वस्तुओं या स्थितियों का स्वरूप पहले कैसा था, आज क्या है और जो प्रक्रिया चलन में है इसके बाद क्या इन्होंने क्या मोड़ लेना है। लेकिन यह एकतरफा काम नहीं। बताते चलने का कोई मतलब नहीं हुआ करता, अगर बिना इसमें पूछते चलना शामिल नहीं हो। पाठकों की प्रतिक्रिया के 'आप और हम', डॉक्यूमेंट्री या 'आपके पत्रों से जैसे कॉलम इसी पूछते भी चल रहे हाने का अहसास दिलाने के निमित्त ही रहे जाते हैं। लेकिन सब पूछिये, तो क्या सबकुछ पूछते चले आ रहे हैं असवारनबीस हमसे? या कि पूछने की औपचारिकता

निबटाने की खासाही व सिया और कुछ दम नहीं इनमें बि पाठना व पत्रो की कुछ पतिर्वा छापरर छुटो पा मना है ? हम जा कुछ वतास चल रहे हैं, यह सही है कि मसत इन मवास त छुटो पाने का मबत नारवर तरीका है यह बि सा जो तुमन बहा, यह भी छापर रहे है । मसत सही और झूठ मस का बहुत स बचन का आतान तरीका और क्या हो सक्ता है बि हम भी ठीक, तुम भी ठीक ।

“तबिअ अमली मवास तो है यह बि क्या हम मसमुष पूछन हैं ? मिक छाने नहीं, बहिक जवाब मागने के इगडे म पूछन हैं ? और अगर पूछते हैं तो ठीक ठीक जवाब नहीं पाने पर क्या यह भी पूछते हैं कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है ? और क्या इन बात को तब धार नहीं तो बार पूछने हैं कि—जो हमने पूछा था जप्ता क्या हुआ ?

चलिए इस पूछने के नमून के तौर पर, इस बार आप और हम मिलकर एक सवाल यही पूछ लें कि साहब, यह राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री की सञ्धानिष हैसियत का मामला क्या है ? पिछले तीस सालों में लगातार अकसर मगरमच्छ की तरह तट पर की धूप सेंकने की सी मस्ती में साहब आ निबसने जाने इन परम राष्ट्रीय महत्व के मामले को अभी और कितने दजको तक अण्डा पहने कि भुर्गों की तज में चलते ही रहना है ? अब पूछन पर आ ही गय, तो लगे हाथों यह भी पूछते चलें कि देश भर के नागरिकों को बे-कूफ बनाते चलने के इस राष्ट्रीय मुद्दे की हकीकत क्या है ? और बि आखिर क्या ऐसी अपग्रिहायता है हम अखण्ड भारतीय स्तर पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला भोवाना की हास्यास्पद नियमि म घनेलते रहने की ?

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री की मिली जुली कुश्ती का यह सिलसिला नया नहीं, लेकिन जो नजारा जानी जससिंह जी ने उपस्थित कर दिया, इसका सन्नमुच जवाब नहीं ।

जानी जी ने यह तेवर तो जरूर दिखाया कि जो नियुक्त कर सकता है, उसे बर्खास्त करने का भी हक है। लेकिन इस बात का पता ही गय कि जो राष्ट्रपति संविधान को ठेके पर रखकर, नितांत अमवधानिक तरीके से किसी को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करता है वह जरूरत पड़ने पर इसी संविधान से ऊपर वाली निजी विवेकप्रणाली से पस भी प्रचष्ट सस्रीय बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी तो कर सकता है? जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए सस्रीय बहुमत तो क्या सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया तक की जाई जरूरत न हो तब उसकी बर्खास्तगी में सुझाव के परा की अपरिहार्यता क्यों हो? जाहिर है कि रानीवगांधी प्रधानमंत्री पद पर अभी भी विराजमान हैं, तो इसलिये नहीं कि संविधान ने जानी जी के हाथ बांध रखे हैं।

हकीकत है यह कि चूनि मुस्क के सत्ता शतरंज के राष्ट्रीय चैम्पियन अभी इस मोहरे को हटाने की अपरिहार्यता अनुभव नहीं कर रहे। अमरा जिन लोगों के दृष्टि पर संविधान को ताक पर रखकर नियुक्त कराया जा सकता है, वो इसी पद्धति से बर्खास्त भी करवा सकते थे। करवा सकते हैं। साफ बात कि किसी भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति या बर्खास्तगी में गिणायक भूमिका संविधान नहीं, बल्कि उस संविधानतर प्रभुसत्तावाद की है, जिसने 'संविधान' को अपने हिमाक से और अपने हक में लिखवाया है। जैसे सृष्टि का कर्ता स्वयं की सृष्टि से अतर्धान है, तैसी ही, भारत के असली भाग्य विधाता भी हुकूमत की शतरंज का खेल अभेद्य पदों के पीछे से चलाते आ रहे हैं। संविधान तो वक्त पड़े पर की नगई ढाँका का ससाधन है। आपातस्थिति की नगई के वक्त संविधान की हकीकत सामने आ चुकी है और संविधान के सर्वोच्च अभिरक्षक राष्ट्रपति महोदय की भी। वक्त पड़ने पर कसा भी काला वारनामा संवैधानिक साबित किया जा सकता है, लेकिन इसके पहले संविधान सबसे ऊपर

है। पाखण्ड में तिलक चढ़ान और चुटिया सबसे ऊपर रहते हैं, चरित्र इनकी ओट में। राष्ट्रपति बनाम प्रधानमन्त्री की सदधानिक हैसियत का मकटसग्राम भी निवा पाखण्ड के और कुछ नहीं।

अखबारनवीसी की भाषा में कहें तो सुना जाता है कि १३ मई की रैली में जब प्रधानमन्त्री ने जयचक्र और मोरजाफर के रूपरी का हस्तेमान करत हुए खुश के किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, बल्कि देश की मामद और जनता के प्रति जिम्मेदार होने का दावा किया, तो जानी जी न शाम को प्रधानमन्त्री का राष्ट्रपति भवन में चय पिलाई। एकांत में ले जाकर, बड़े लाड से पूछा—'वयो, भई, ३१ अक्टूबर १९८४ के दिन रैली करके यह बताने की याद क्या मचमुच नहीं रही कि तुम किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त किये जाने से इकार करते हो—और सभी प्रधानमन्त्री का पत्र स्वीकार करोगे जब देश की सासद और जनता प्रधानमन्त्री बनायेगी?' बताया जाता है कि जवाब में जो कुछ प्रधानमन्त्री ने कहा उस ध्यान से सुन लेने के बाद ही जानी जी को सविधान और राष्ट्र की गरिमा की आंच न आने देने का संकल्प करना पड़ा।

बतात में पूछत चलने में तब में ही पूछत में कुछ बतात भी चलता जल्दरी हुआ। बहरहाल, फिर इसी बात पर आ जायें कि और क्या क्या पूछना चाहते थे हम। लेकिन इससे पहले देख ले थाड़ा यह भी कि इस प्रसंग में अब तक हम क्या कुछ बताया जा चुका। क्या सविधान विशेषज्ञों और क्या हमारे महामहिम राष्ट्रपतियों के द्वारा। इसमें क्या शक कि हमारे अखबारनवीसों ने हूबहू वही सब हमें पढ़ाया है जो कि बताने वालों के द्वारा बताया गया। लेकिन आत्मी और तात को पढ़न में कुछ पक होगी कि नहीं? दशोरदास ने वयो कहा होगा—'तू कहता कागद की लेखी—मैं कहता आखिन की देखी।' सिवा यह रतान के और क्या मकसद रहा होगा उनका कागद की लेखी का भरोसा मत करो, जब तब कि आखिन की

दखी में मिलान न हो जाय ! आइये, देख लिया जाय जरा कि वागद की नेली क्या कह रही है और आखिन की दखी क्या !

सविधान व वागदों पर का सारतत्व, थोड़ा म, कुछ यो है— राष्ट्र-पति कोर कानूनों से ऊपर एक नैतिक सत्ता हैं। यानी प्रधानमन्त्री के अधिनायकत्व में जो मन्त्रिमण्डल 'कानून का राज' चलाने की वायम होता है, उसके ऊपर नैतिक अकुश रखने को राष्ट्रपति की नैतिक सत्ता की अवधारणा की गई है।

ऊपर की इयारत को ध्यान से पढ़िये तो क्या मतलब निकलता है मित्रा इसक कि हाथी अपने महावत की 'अवधारणा' कर रहा है ? जिस नैतिक सत्ता का डेरा राजसत्ता के दरबार में हो वह कितना और क्या अकुश राजसत्ता के असोकतात्रिक कारनामों पर लगा सकती है, हमके उगहरण हमारी आँखों से दूर नहीं। पिछले संतोस वर्षों में क्या राजसत्ता न कोई अनैतिक बदम नहीं उठाया ? क्या आपातकाल का काना कानून भी नैतिक ही था ? था, तो हटाया क्यों गया ?

भारतीय सविधान की परिधिया इतनी व्यापक हैं कि कैंमी भी तानाशाही को बाकायदे सवधानिकता का जामा ओढ़ाया जा सकता है। आपातकाल सबून है कि हमारे सविधान की हर्दे कहीं तक जा सकती हैं। ऐमें में इतना तय मान लेना होगा कि जो कारनामा असोकतात्रिक हो, जरूरी नहीं कि सरकार उसे असवैधानिक माने। राष्ट्रपति पद का आविष्कार भारत भाग्य विधाताओं ने राज्यसत्ता के ऊपर नैतिक सत्ता की अवधारणा नहीं, बल्कि राजसत्ता के अनैतिक कृत्यों पर नैतिकता (यानी सर्वधानिकता) की मुहर लगवाने की कूटनीति में किया। नैतिक सत्ता राजसत्ता की अशफियों से नहीं खेलती। जो सत्ता क मोहरो पर मुनछरें उड़ाता हो, वह हर हाल में उसके अनुग्रह का मोहताज होगा। अगर राजसत्ता अनैतिक हो, तो उसके किसी अग विशेष के नैतिक होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सविधान में राष्ट्रपति की हैसियत राज्य व्यवस्था से बाहर नहीं। राष्ट्रपति हरहाल में

एक मुद्दे राजनतिक सत्ता है नतिक नहीं। नतिक सत्ता शाही बगियान में नहीं बोला करती। उसका काम निष्काम राजनीति भोग नहीं। उसकी जगह समाज है शाही दरबार नहीं।

सविधान के अनुच्छेद ७४ में नीतिक सत्ता का सबसे ऊपर हान की अवधारणा और इसी तब में मन्त्रिमण्डल का हर सर्वेधानिक कायदागम में राष्ट्रपति की सहमति और स्वीकृति का सटोतिवी होनी गई है। जो व्यवहार में नहीं, उसका सिद्धांत में हान की हानि के सिद्धांत और क्या कहा जाय? हम प्रथम में सर्वोच्च न्यायालय का १९५५ का फैसला की ये दो मुख्य नतीजें द्रष्टव्य हानी, जिनमें राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल (प्रकारांतर में प्रधानमंत्री) की सर्वेधानिक हैमियत तब का गई है।

१—हालांकि हम यह मानें कि राष्ट्रपति का कमला सर्वोपरि है और लोकसभा के निराकरण तथा निधन का जो अधिकार मन्त्रिमण्डल को उपलब्ध है, यह राष्ट्रपति के अधिकारों के नीचे है, तो यह साधना पड़ेगा कि सविधान में उसके लिए कोई लिखित या स्पष्ट प्रावधान है या नहीं।

२—हालांकि राष्ट्रपति मात्र शोभा प्रतीक नहीं हैं, लेकिन उनकी ओर उनकी महान् शक्ति की गरिमा ब्रितानी राजा की तरह इस बात से, बन्नी ओर धरत पर रहती है कि वह अपने मंत्रियों को उपलब्ध सलाह दें। यह मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति की दृष्टि में अनूचित रास्ते पर जा रही, तो वे ठीक सलाह देकर मन्त्रिपरिषद् के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। यह मन्त्रिपरिषद् की किर से विचार करने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन मन्त्रिपरिषद् अगर उनकी सलाह नहीं मानती, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने की बाध्य हैं। (सं २१० १९५५ अक १, पृष्ठ ८७)

इन दो नज्दों का सदन में ये कुछ सवाल जरूरी होंगे।

१—मायले को विचार के लिए स्वीकार करते समय तो ठीक, लेकिन फसला पारित करते में इस दलील का औचित्य क्या होगा कि

सविधान में कोई लिखित या स्पष्ट प्रावधान है, या नहीं ? सात 'याया' धीशो की खण्डपीठ नहीं देख और बता सकती कि इस मामले में सविधान में क्या प्रावधान है, तो क्या खुदाई विदमतगारों की कोई टोली आकर देखेगी कि सविधान में क्या प्रावधान है, क्या नहीं ?

जिस देश के सर्वोच्च 'याया' धीशो का हान यह हो कि पत्ला भाड़कर अलग खड़ा हो जाने में हो खुद की छुरियत देखें, वहाँ के सामान्य नागरिकों का हाल क्या होगा ? क्या नहीं देखा—या नहीं देखा—याया' धीशों ने कि सविधान के राष्ट्रपति सम्बन्धी अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है, क्या नहीं ? क्या बिना सविधान पढ़े ही निपुण हो जाते हैं 'याया' धीश, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के ? साफ है कि इन सारी टालमटोल के पीछे यह अमूल्य हिदायत काम कर रही है कि खबरदार, इस रहस्य को किसी पर कभी खोलना नहीं कि राष्ट्रपति की वास्तविक हैसियत सविधान नहीं, राजसत्ता के अधिनायकों के हाथों में है। परिणाम कि राष्ट्रपति की संवैधानिक हैसियत आज भी निराकार बह्य की है। उसे जब जैसी जरूरत हो, वैसी संवैधानिक हैसियत बनाने के चोरदरवाजों पर पर्दे आज भी उभो के लटके हैं।

२—उस महान् पद की महानता का क्या कहिये, जो अपने भूत-पूव आका ब्रितानी राजा की नकल में खड़ा किया गया हो। कोई पूछे सविधानमार्तण्डों से कि ब्रिटेन के राजा के प्रतिरूप की अपरिहायता भारत में क्यों ? यह बताने के लिये कि अंग्रेज जरूर गये, मगर अंग्रेज राज कायम है ? या इस आलाची में कि ब्रितानी राजा की नकल में जन मन गण अधिनायकों का वशानुगत शासन काममें रखने, और इसे संवैधानिकता तथा नैतिकता का जामा ओढ़ाने, के लिये ब्रिटिश आकाओं की नकल का एक अदद संवैधानिक शक्ति का सर्वोच्च मोहरा खड़ा करना जरूरी है ? ब्रिटिश माहल के सोकतत्र की छायावादी नकल के सिवा अत्र कहीं ऐसे महान् राष्ट्रपति पद की कोई जगह

होगी, जो एक अनुच्छेद में सर्वोच्च नतिर सत्ता है, तो दूसरे में कौन भी काले दस्तावेजों पर चुपचाप मुहर लगाने को लाचार करिदा ! पिछले अनुच्छेद में सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, तो अंगों में किसी फौजी कमाण्डर से भेंट करने के लिये प्रधानमन्त्री की अनुमति का मोहताज ! अनुच्छेद ७४ में मन्त्रिमण्डल को सलाह देने और ७८ में प्रहरी सूचनाएँ माँगने का अधिकारी है तो अनुच्छेद ८७ में मन्त्रिमण्डल की सलाह पर कैसे भी अनतिक दस्तावेजों पर चुपचाप दस्तखत करने को बाध्य ! —आश्चर्य कि 'राष्ट्रपति को ब्रितानी राजा की तरह ही आचरण करना चाहिये ।' की नज़ीर देते हुए हमारे माननीय 'यायाधीश गण भूल ही गये कि राजनैतिक—मानसिक रूप में भले ही हो, लेकिन संवैधानिक तौर पर अब भारत ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहा' । क्यों इतना महान् अनुभव होता है हमारे माननीय सर्वोच्च 'यायाधीशों तक को ब्रिटेन के राजा का पद ? बाकिर क्यों नहीं दूर हो पा रही हमारे औपनिवेशिक चरित्र में से अंग्रेजों की मानसिक—बौद्धिक गुलामी की बदबू ।

फैसले में यह भी स्पष्ट नहीं कि जिसकी सलाह मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी, जो भेजे गये दस्तावेजों पर हरहाल में बाँझ मूढ़ कर दस्तखत करने को बाध्य होगा, वह 'यक्ति चाहे विश्वसंभ्राट का मुकुट धारण किये क्यों न बैठा हो—वास्तव में वह सिवा एक हास्यास्पद शोभामूर्ति सिवा और क्या होगा । जो परनाला वहाँ गिरेगा, यह तय करने में असमर्थ हो, उसके पक्ष फैसले की ओकात क्या होगी ? जिसका पद पिलपिला, उसकी सलाह ठोस कैसे होगी ? सिर्फ सलाह देने का अधिकार अगर इतना संवैधानिक महत्त्व रखता हो, तो संविधान में हमारी जगह राष्ट्रपति से भी ऊपर होनी चाहिए क्योंकि हम भारत के प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल को ही क्यों, रीगन, थचर, मित्ररा, दैंग तैंग से लेकर गोर्बाचोव तक, दुनिया के सारे राष्ट्रपतियों—प्रधानमन्त्रियों और उनके मन्त्रिमण्डलों को यह सलाह देने के लिए पूरों

तरह स्वतंत्र हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं ! क्या उनके हक में होगा, क्या नहीं !

जाहिर है कि पूरे फैसले में सिवा याग्यास के और कुछ नहीं। इसमें इतना साफ सकेत है कि जो भी जानना चाहेगा कि राष्ट्रपति की संवैधानिक हैसियत की वास्तविकता क्या है, उसे सिवा बेवकूफ के और कुछ नहीं समझा जायेगा। मयया कौन नहीं जानता कि पद के साथ उसके कर्तव्य और अधिकारों की सूची बिलकुल स्पष्ट जुड़ी होती है। एक चपरासी तक अपने अधिकारों से अनजान नहीं होता। राष्ट्रपति का पद तो हर हाल में राष्ट्रपति का पद है।

यही एक जरूरी सवाल यह सामने आता है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपतियों की सभी अपने अधिकारों को जानने की जरूरत क्यों महसूस होती है जबकि प्रधानमंत्री से कुछ खटपट हो जाय, या कि 'सैवानिवृत्ति' का समय नजदीक आ चला हो ? जानी जो को अपने कायकाल के साढ़े चार वर्षों तक कभी जरूरत नहीं हुई कि जरा यह तो देख लें कि आखिर उनके अधिकार क्या हैं। जबकि जैसा पहले ही कहा, चपरासी हो कि राष्ट्रपति, पद के साथ अधिकारों का सवाल अपरिहाय रूप से जुड़ा है। जो अपने अधिकारों से उगासीन हो, साफ है कि वह अपने कर्तव्यों से भी पट्ला झाड़े बैठा है। यानी उसे पता है कि सारी राजसी सुविधाएँ उसे इसी 'अप्रत्यक्ष अनुबंध' में दी गई हैं कि वह धमाई गई शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ़ मुहर लगाने में करेगा। "यह कोई मसौल नहीं, पूरे राष्ट्र के हित का सवाल है कि जो राष्ट्रपति अपने अधिकारों को जानने की जरूरत तक महसूस न करता हो वह राष्ट्रीय संकट उपस्थित होने पर सिवा संविधान विशेषज्ञों से खुद के अधिकारों की हकीकत पूछते फिरने के नाटक के सिवा और करेगा क्या ?

अब थोड़ा राष्ट्रपतियों के इस दावे पर भी विचार कर लिया जाय कि उन्हें प्रधानमंत्री से सूचनाएँ माँगने का अधिकार है। जिसे

दूसरी के द्वारा तैयार कागजों पर दस्तखत करने के सिवा कोई अधिकार न हो, उसके सूचनायें माँगने से क्या होना जाना है ? फेयरफक्स और बोफोस बाण्डो पर सूचनाएँ प्राप्त करने का राष्ट्र को क्या मिला ? रह गया सवाल कि ससद में बहुमत प्राप्त करने या खोने पर प्रधानमंत्री को नियुक्त बर्खास्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया तो राष्ट्रपति ही पूरा करता है, तो इस औपचारिकता को तो चुनाव आयुक्त भी निबटा सकता है। मात्र इतनी खानापूरी के लिए एक गरीब मुल्क पर करोड़ों अरबों की लागत का सफेद हाथी लादने का संवैधानिक चाहे जिसना लेजिस्लेशनल ऑब्जेक्टिव कोई नहीं, क्योंकि ससदीय बहुमत के विरुद्ध राष्ट्रपति तभी फसरा से सकता है, जब सैनिक शासन कायम करना हो।

लोकतंत्र का यह बुनियादी तत्वाज्ञा है कि शक्ति का केन्द्रीकरण व्यक्ति में नहीं होने पाये। राष्ट्रपति को किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त या बर्खास्त करने के निजी अधिकार का मतलब ही ससद का अति क्रमण है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति या बर्खास्तगी के मामले को ससद के अधीन ही रखना चाहिये, क्योंकि लोकतंत्र की धुरी ससद है — राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति को ससद से ऊपर करने का मतलब है, उसे ससदेतर शक्तिपीठ बनाना। कोई पूछे कि तब सद्भातिक तौर पर ही सही, संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोच्च संवैधानिक शक्ति क्यों माना गया है तो जवाब मुश्किल नहीं। राष्ट्रपति में तानाशाही शक्ति का प्रत्यारोपण दरअसल ब्रिटिश मॉडल के ससदीय लोकतंत्र के अधिनायक प्रधानमंत्री की तानाशाही पर आवरण करने के इरादे से किया गया। आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी के हुक्म पर डमरू की काले कानून पर स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद और 'सूटकार आपरेशन' के दस्तावेजों पर सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च सेनापति माननीय जैस सिंह जी की आसमूद मुहर इसका मुहबोलता सबूत है। 'भारतीय संविधान' में इस तथ्य को छिपा लिया गया है कि राष्ट्रपति

के पद का सजन राजसत्ता के अधिनायकत्व पर मखमली पर्दा तानने के निमित्त किया गया है— लोकतंत्र की चिंता में नहीं। जनहित में राष्ट्रपति के ऐसे पद की न कस कोई प्रासंगिकता थी, न आज है, न आने वाले समय में होने की गुंजाइश, जो कि अपने आप में एक अव्यक्त तिलिस्म की शक्त लिये हो। जिसके अधिकारों की व्याख्या करन में सर्वोच्च न्यायालय तक असमर्थ हो, उस दश क कराडो—करोड़ सामान्य जन कैसे समझ पायेंगे? लोकतंत्र में जनता के ज्ञान से बाहर की हर वस्तु घोटाला है। जाहिर है कि अपने मौजूदा स्वरूप में राष्ट्रपति का पद हर हाल में राजसत्ता के अंत पुर का पद है। उसका सारा प्रभामण्डल राजसत्ता की निर्मिति है। जनता की उसकी शाही सवारी को सिवा बाढ से सगकर टुकुर-टुकुर देखन के, और कोई औकात कही नहीं। इस सारे मामले में उसकी कुल खमा हैसियत 'देख, तमाशा, देख।' की है।

जि हें ऊपर बहे गये में कुछ शका हो, जो मानते हो कि अभी अभी तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति माननीय अमर जी ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ॥ सूचनाएँ माँगने का पूरा अधिकार है—उहें माननीय चैकटरमण जी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हैसियत से दिये वक्तव्य के इस अंश की ध्यान में रखना चाहिये—'किसी भी मामले में सूचना माँगने का राष्ट्रपति का अधिकार निरकुशता की श्रेणी में आ जायेगा। प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई कायवाही नहीं की जा सकती। लोग सविधान में राष्ट्रपति का ऐसे अधिकार दना चाहते हैं जिसकी व्यवस्था सविधान के निमाण के समय नहीं की गई थी। कायवाही करने की जिम्मेदारी सदन की है। सविधान के तहत प्रधानमंत्री केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। सविधान में यह नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार या उहें जवाब देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति के अधिकार की रक्षा बाहर से नहीं खींची जा सकती।

राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री ही यह रेखा खींच सकते हैं।'

राष्ट्रपति जी ने उपरोक्त बयान के अंतिम वाक्य को जरा ध्यान से पढ़ा जाय। इससे साफ है कि राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के बीच सम्बन्धों की रेखा खींचने का काम न संसद का है, न संविधान का, बल्कि यह दो व्यक्तियों का निजी मामला है। अर्थात् 'कामद की लेखी' और 'आखिर की देखी' में है वही कोई मिलान? सारी खुदाई एक तरफ लेकिन आठवें राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टरमण जी का इस बात के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिये कि आज का सच तो उन्होंने कह दिया—बल की कौन जानता है। बल तो उधार का है, और जब परा लोकातन ही उधार का है, तब संविधान के तोतापाठ का क्या है। हालाँकि जब संविधान में ही मजबूती है, तब महामहिम डॉक्टरमण की खींची रेखा में संशोधन क्यों असंभव होगा? और सच है कि बड़ी रेखा हमेशा वहीं खींचेगा जिसके हाथों में राजसत्ता की नकल होगी।

राजसत्ता की वास्तविक नकल किन हाथों में है यह जानना जरूरी है क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के बीच अधिकारों को लेकर बार बार उपस्थित होने वाले संबंधानिब अटकलों के खेल को समझ पाना असंभव है।

मामले को समझ से बाहर कर दिये गए होने का कारण ही हमें सवाल उठाने पड़े हैं। हम बिल्कुल उम्मीद करना चाहेंगे कि जामी लोग हम हकीकत समझायेगें जबर। लोकतन्त्र का असली बिहारा वही है, जो पिनकने नहीं, समझाने में निष्ठा रखता हो।

क्या हम जानते हैं

असवारों में कई बार हमारे सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी के शब्दों के साथ, कुछ घटनाओं अथवा वस्तुओं की भावियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। बाद में उत्तर, लेकिन पहले उस सवाल के साथ शि—क्या हम जानते हैं? लेने शुरू और करने में कितना सामग्री या लगना है यह सवाल, लेकिन यहाँही इसकी गहराई में उतरिए, पहाड़ होता जाता है। दृष्टांत के तीर पर अगर पूछ लिया जाय कि क्या हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या, और शि इसका हमारे जीवन से वास्ता क्या अथवा कितना है तो कितने लोग होंगे इन देश में, जिनके सामने हाथ में सुरत जुम्बिश होने, और वह कंधे से ऊपर चढ़ने लगे ?

संपूर्ण अथवा संपूर्णता में किसी भी वस्तु को कोई नहीं जानता। जो जानता है सारभूत रूप में और कोई ज्यादा, कोई कम जानता है। कहें कि जिसका जितना वास्ता, और जिस स्तर की चेतना, चेतना जानता है। संविधान के ज्ञान के प्रसंग में भी सवाल यही मुख्य है कि संविधान से हमारा वास्ता कितना है ? तथा यह भी ठीक ठीक जाना जा सकेगा कि संविधान को हमसे कितना लेना देना

है। 'नागरिक' राज्य की इकाई है और संविधान, राज्य व्यवस्था की किताब। इस किताब से नागरिक के जन्म से मरण तक की स्वस्थि के सवाल बंधे हैं और तथ्य में कोई अंतर इससे नहीं पड़ता कि हम सचार्थ को जानते हैं या नहीं जानते।

बाबा तुलसीदास ने कहा— हित अनहित पशु पक्षिहु जाना। हिन अनहित को जानने बुझने का एक ही रास्ता है। जिससे वास्ता हो उसे जानना। अब अगर देश के निधानव प्रतिशत लोगों का जवाब हो कि हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते, तो माना कि यह सच ही होगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही होना भी चाहिए था ?

जो भी इतिहास भूगोल खगोल ज्ञान विज्ञान राजनीति साहित्य अथवा संस्कृति आदि के विज्ञान आज के हालाती का रोना रोते हो, उन्हें इस बात पर ध्यान देना जरूरी होगा कि राष्ट्रव्यापी जड़ता और दिशाहीनता की जड़ें कहीं, कितनी दूर और गहराई तक फैली हैं। राज्यव्यवस्था के प्रति उदासीन होने से क्यादा खतरनाक और कुछ नहीं, क्योंकि इसका साथ हमारे जन्म की बिलकारियों से लेकर मरण के कफन तक को घेरे होता है। हमारा भोजन भजन, बितन-भनन, रोना गाना नाचना, कोई काम कलाप ऐसा नहीं, जिस पर राज्य व्यवस्था के अंगूठी की दाब नहीं हो। फिर लाख टके की बात कि हमको हो, नहीं हो, राज्य व्यवस्था को हममें से प्रत्येक से वास्ता होता है। यह इसना हिसाब किताब बाकायदे रखती है कि कितने जड़ हैं कितने चेतन।

यह निर्विवाद तथ्य है कि हित छिगाने नहीं बताने की वस्तु है। जो सरकार संविधान को लोकहित के निमित्त ही बनायेगी यह प्रत्येक नागरिक को इतना बताना भी जरूरी समझेगी कि संविधान में उसके हितों की सुरक्षा की पहल तथा व्यवस्था किस किस रूप में की गयी है। क्या-क्या है उसके हित में जरूरी संविधान में इसे बताना सरकार

तथा जानना नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस जगत में प्रत्येक वस्तु के दो छोर हैं। जब तक दूसरा छोर अधरे में तब तक पहले छोर पर रोशनी होने का कोई मतलब नहीं।

एक छोर पर भारत सरकार है दूसरे पर हम। संविधान का उजासा क्या दोनों छोरों पर समान है? सत्यमेव जयते' तथा तमसो मा ज्योतिर्गमय' के सांझफलों की चमका-वाली भारत सरकार को (भी) इस सवाल का जवाब आज नहीं, तो कल, बल नहीं, तो परसों, परसों भी नहीं तो बरसों के बाद हा सही-देना तो जवाब जरूर ही पड़ेगा कि जिस देश की निमानने प्रतिशत जनता संविधान से अधरे में रखी जा रही हो, वहा लोकतन्त्रात्मक समाजवादी गणराज्य के भोषू दशो दिशाओ में लगाये होन क करिश्मो की हकीकत क्या होगी?

इसमें क्या शक कि एक स्वाधीन कहे जाने वाले मुल्क में भानमती खुद का पिटारा खुद के इस्तमाल के हिसाब से ही बनाने की स्वतन्त्र मानी जानी चाहिए, लेकिन अगर भानमती डके की चोट पर दावा करे कि उसने पिटारे से हमारे अस्तित्व के सवाल जुड़े हैं (और कि पिटारा तो हमारे ही निमित्त अंगीकृत-आत्मपित हुआ है) तब हमें भी इतना हक बिस्कुल होगा कि पिटारे की एक-एक वस्तु को जांचकर देखें। देखें कि हकीकत क्या है। अब अगर भानमती माये पर थोरिया चढाय कि पिटारे को हाथ नहीं लगाया जाय-या कि लगाया जाय, तो सिर्फ उतना और इस तरह से ही, जैसे कि भानमती चाह, तो इसमें कुछ हज़ नहीं होगा कि हम भानमती का भोटा कसकर पकड़ लें और कहे कि सभुरी, ठगविद्या चलाने की एक हम ही रह गय क्या? क्योंकि जो भी वस्तुओं के जांचे जाने में एतराज करे वह हितू कदापि नहीं हा सकता। हित का तो प्रयम तक ही जानना है और जान वही सकता है, जो जांच सकता है।

भारत सरकार ने संविधान, यानी अपनी सर्वोपरि किताब, को

हमें इतना तो मानना होगा कि जानने के लिए खुला रखा है। अस्त-व्युत्ता, राजश की इस सर्वोच्च किताब को हमारे लिए उजाले की शक्ति देन में उसकी रुचि बिम्बुल नहीं। अगर हाँ तो तब वह इस लिखे ईसा पठें मूसा, समझें बाबा आदम के 'बूझो तो जाने' की चुनौती के तौर पर हमारे सामने नहीं रखती। सामान्य नागरिकों की हैसियत से, किचहाल, हम इतना सवाल खुल ही पूछ लेना चाहते हैं कि क्या हम जानते हैं कि वस्तुओं की अगम्य सिर्फ वही लोग रखना चाहते हैं, जिन्हें सारी विज्ञान हमें हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में रखने की हो ?

क्या हम जानते हैं कि अगम्यता के लिए पाण्डित्य के इस्तेमाल की योजनाएँ सिर्फ वही लोग बनाने हैं, जिन्हें खुल के कारनामों के अतिविरोध छिपाने होते हैं ? क्या हम जानते हैं कि हित का सवाल हरहाल में भाषा सचचा हुआ है ? क्योंकि जो हमारा सचमुच हित चाहता हो वह कभी भी जानबूझ कर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा जो हमारी समझ और पहुँच के दायरे से बाहर हो। सारा स्वाधीनता संग्राम हिन्दी में चलाने के बादजून स्वाधीनता के तीस वर्षों के बाद अंग्रेज महाप्रभुओं की भाषा में संविधान को रखने से किसकी सम्प्रभुता के रास्ते चौड़े हुए ? भारत की निर्यात प्रतिगत अंग्रेजी के ज्ञान से भूय जनता, या कि अंग्रेजी बुद्धि में निष्ठाएँ एक प्रतिगत औपनिवेशिक प्रभुत्व का ?

क्या हम जानते हैं कि बाक और अथ एक दूसरे से मयूक्त हैं और ऐसी भाषा का कोई मतलब नहीं हुआ करता सिवा उगने की भाषा के जिसका अर्थ बूझना हमारे लिए असम्भव हो—फिर चाहे वह अंग्रेजी हो, या कि हिन्दी ? क्या हम जानते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी तक ही मामला सीमित नहीं, बल्कि भारत सरकार के द्वारा जो अंग्रेजी के उच्छिष्टानुवाद की भाषा चलाई जाती है उस हिन्दी भाषा को समझना हिन्दीतर प्रदेशों के लोगों की तो कौन बहे, स्वयं

हिंदी प्रदेशों के विद्वानों के लिए भी पत्थर के आवले चबाना है ? हम भारत सरकार के माग निर्देशन में रचे गये ऐसे कितने ही दस्तावेजों का हवाला दे सकते हैं, जिनकी भाषा नहीं समझ पाने का कोई अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि इतना दावा बिल्कुल किया जा सकता है कि इस अखण्डराष्ट्रीय हिंदी को समझने में स्वर्गीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य किशोरीदास बाजपेयी, पण्डित महाश्वीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्यामसुंदरदास तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे हिंदी के मुख्य विद्वानों को तक पसीना छूटते देर नहीं लगती ।

चूँकि प्रक्रिया अदालतों की भाषा के सवाल तक जाती है हम-सिए यहाँ भी ज़रूरी होया पूछना कि क्या हम जानते हैं कि घोषित आजादी के बाद भी देश को गुलाम रखने वालों की भाषा में ही शासन चलाने का सिफ, सिफ और सिर्फ एक ही मतलब होता है— देश की जनता को हरहाल में गुलामों की जिवनी जीने की नियति में रखना ? क्या हम जानते हैं कि वास्तविकता में कौन सा जीवन जी रहे हैं ? हमारी आँखों में स्वाधीनता की कौंध चमकमाती है, या कि गुलाम मानसिकता के काले धब्बे तरते दिखायी पड़ते हैं ?

हम फिर जोर देकर कहना चाहेंगे कि जानने की भाषा ज़रूरी है । क्या हम जानते हैं कि कानून की भाषा को महाकाव्यों की भाषा से भी जटिल बनाने का मतलब क्या होता है ? ऐसे में यह सवाल कैसे अप्रासंगिक कहा जा सकेगा कि क्या हम जानते हैं कि सविधान, बायदे कानून तथा मायालयों में अगर अपनी भाषा हुई होती, तो 'मायालयों में हमारी उपस्थिति थने हारे, निरुपाय, निरीह, बेजुबान जानवरों की तरह धक्के खाने की नहीं होती ?

यह एक राष्ट्रीय फज़ीहत के सिवा कुछ नहीं कि एक ओर हम दावा रखते हैं कि जब हमारे यहाँ भालदा विश्वविद्यालय ज्ञान का आसोक पता रहा था, उस दौर में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में

जंगली हाथियों का डेरा हुआ करता था। दूसरी ओर अंग्रेजों की जूठन हमारी सतानों को जीवन का सर्वोच्च सत्य बनी हुई है। भाषा के मामले में आज भी हमारी हेसियत ब्रिटिशों के टुकड़सोरों से ज्यादा कुछ नहीं।

क्या हम जानते हैं कि अंग्रेजी हमारे लिए ज्ञान विज्ञान के भरोखे खुले रखने के नहीं, बल्कि स्वाभिमान और चेतना को कुचलने के इरादों में कायम रखी गई है? क्या हम जानते हैं कि हिंदी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय भाषा की ओकात अंग्रेजी के सामने ठीक वही है, जो कभी गौरा साहबों के सामने उन सदियों के गुलाम हिन्दुस्तानियों की हुआ करती थी, जिनके लिए कि सिविलसाइंस और क्लर्कों की तरफ जाती सड़कों पर 'इंडियन एण्ड इंग्लिश आर नाट अलाउड।' लिखी सवितियाँ लगा दी जाती थी? क्या हम जानते हैं कि आज भी भारत की राजधानी के अंतपुरों, सुप्रीम कोर्ट तथा भारत के प्रधानमंत्री के इर्द गिद अंग्रेजी नहीं जानने वालों की हेसियत इससे शीघ्र कुछ नहीं?

क्या हम जानते हैं कि अपनी तथाकथित आजादी के चासीस साल बाद भी हम इस सच्चाई से बिल्कुल बेसरोकार हैं कि जो भाषा में गुलाम हो चरित्र में भी गुलामों के सिवा और कुछ नहीं होते?

हमारे संविधान में स्वाधीनता के सारे बुनियादी समाल नदारद हैं और यही संविधान को देश के सामान्य नागरिकों की पहुँच और समझ से दूर रखने का मुख्य कारण है। क्या हम जानते हैं कि पिछले चासीस वर्षों में गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ने भारत को एक ऐसी भयावह तथा शमनाक नियति में धकेल दिया है, जहाँ अंग्रेजी भाषा सूझने वालों की हेसियत ब्रिटिशों से कम नहीं—और अंग्रेजी नहीं जानने वाले करोड़ों करोड़ लोगों की ओकात 'याय-नानून और रोजी रोटी के भिखमणों की है। अंग्रेजी को अपने लगभग सौ वर्षों के एक धन शक्त के अंत में जितना अंग्रेज फँसा पाये, हमारी भारत सरकार

ने सिर्फ चालीस सालों में उसके दस गुने से ज्यादा फैला दिया है।

क्या हम जानते हैं कि संविधान में अंग्रेजी को अनन्त काल तक को हमारी चेतना पर कालिख की तरह इसलिए पोत दिया गया है कि हम जान ही नहीं पायें कि शासक वर्ग के लिए अलग तथा शासित वर्ग के लिए अलग भाषा का मतलब औपनिवेशिक प्रभुसत्ता-वाद के सिवा कुछ नहीं हुआ करता है। और कि औपनिवेशिक शक्तियाँ देश की सरहदों के बाहर ही नहीं, भीतर भी बाकायद डेरा बिये रहती हैं भाषा के माध्यम से।

क्या हम जानते हैं कि 'इंडियन कास्टीट्यूशन' में जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिये गये होने की बात की जाती है, वह शुद्ध सफेद भूट के सिवा कुछ नहीं? क्योंकि दरअसल संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया नहीं गया है, बल्कि दिये जाने का पाखण्ड मात्र रचा गया है। दरअसल हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिये जाने का सारा काइयापन अंग्रेजी की सम्प्रभुता कायम रखने के इरादे में है। हिंदी को हटाते ही अंग्रेजी को भी अंग्रेजों की तरह विदा होना होगा—यह रहस्य ही संविधान में हिंदी को राजभाषा के दर्जे का भुनभुना घमाने के पीछे की वास्तविक हकीकत है। क्या हम जानते हैं कि जब तक अंग्रेजी कायम है, तब तक जनतंत्र के अस्तित्व में आने का सवाल ही नहीं क्योंकि जनतंत्र सिर्फ जनता की भाषा में ही सम्भव हो सकता है?

क्या हम जानते हैं कि हमारा संविधान, अपने चरित्र में, एक शुद्ध औपनिवेशिक संविधान है? और कि इस संविधान के ज्यों के त्यों चलन में रहते भारत की करोड़ों-करोड़ों जनता की आर्थिक-सामाजिक मुक्ति का सपना सिवा एक त्रासद दिवास्वप्न के सिवा और कुछ नहीं। क्या हम जानते हैं कि संविधान से बेसरोकारी वैचारिक जड़ता का सूचक हुआ करती है, क्योंकि संविधान हमारे सामाजिक जीवन की सबसे जरूरी किताब है। घमंघ्रियों से भी जरूरी !

क्योंकि आत्मा का वह सारा आलोक व्यर्थ है, जो हमारे दैनंदिन जीवन का तमस नहीं छीट सके । क्या हम जानते हैं कि 'कास्टीचूशन ऑफ इण्डिया' हमारे सामाजिक जीवन का प्रकाशस्तम्भ बनने की जगह एक ऐसे अभेद्य तिनिरुद्ध की शक्ति बयो लेता गया है, जहाँ हम करोड़ो-करोड़ सामान्य हि दुस्तानियों के लिए आपातकाल का बधा कृप्य चाहे जितना अतभूत हो, किन्तु सामाजिक स्वाधीनता की रोजनी के चिह्न पूरी तरह अतर्धान हैं ?



आदमी और कानून

कानून व्यवस्था का आधारग्रन्थ है-संविधान। यहाँ हम आदमी और कानून के बीच के सम्बन्ध का सवाल इसलिए उठा रहे हैं, ताकि देखा जा सके कि संविधान में स्थिति क्या है।

किसी भी काय में हित का सवाल ही मुख्य हुआ करता है। कानून इसका अपवाद नहीं। संविधान राज्य व्यवस्था का आधार होता है। नागरिकों को संविधान में उल्कीण जनहित के स्वरूप को जाचते चलना जरूरी है, ताकि इस बुनियादी सवाल पर आलोक बना रहे कि संविधान में किसके हित को केन्द्र में रखा गया है-पूरे समाज या कि सिर्फ राजपूत व के।

कहना जरूरी न होगा कि हमारा मौजूदा संविधान (या वह सें कि इसका मौजूदा स्वरूप) समाज के हित को केन्द्र में रखे गये होने की कोई गवाही नहीं देता। परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों की तुमुल निनाद में प्रतिभूति (गारण्टी) देने वाले संविधान में ही मौलिक अधिकारों की बन्न खोदने के न जाने कितने प्रावधान मौजूद हैं। यहाँ विस्तार में जाने की गुंजाइश नहीं होने से, सिर्फ एक 'जानने का मौलिक अधिकार' का ही दुष्टांत काफी होगा। जानने की नाग

रिव का मूलभूत अधिकार धोपित करने वाले सविधान में विशेष अनुमति याचिका सब धी अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी मामले में, अतः, 'यायाधिकारियों का विवेक ही सर्वोपरि है। इस विवेकाधिकार की कोई सीमा नहीं। यह तक और सबानों से ऊपर है। इसमें यहीं तक स्वच्छता है कि किसी वि अ याचिका या समादेश याचिका को क्यों निरस्त किया जा रहा है, यह बताना, या न बताना भी सम्बद्ध 'यायाधीश के विवेक का प्रश्न है। सिर्फ इतना ही फसला भी पूरी तरह सर्वैधानिक माना गया है कि—याचिका निरस्त की जाती है।

शब्द अपना अर्थ स्वयं बोलता है। विवेकाधिकार से भी 'विवेक' की उपस्थिति प्रथम है 'अधिकार' की बाद में, किंतु जब किसी 'यायाधीश के द्वारा कारण बताये जाने से साफ इन्कार हा, तो साफ है कि सिर्फ पदाधिकार प्रयुक्त हुआ, विवेक नहीं।

क्या इसमें कोई विवाद हो सकता है कि आदमी का हित कारण जानने में ही निहित है। उसकी सारी सकारात्मक उपलब्धियाँ कारण जानने के उपक्रम से ही जुड़ी हैं। आग हवा पानी मिटटी पत्थर लोहा लकड़ से लेकर आकाश-पाताल तक की सारी वस्तुओं का कारण जानने के अथक अनवरत संघर्ष ने ही उसे ज्ञान विज्ञान की निधियों में सम्पन्न बनाया है। ऐसे में स्पष्ट है कि कारण बताने से इन्कार प्रकाशितर से मनुष्य के ज्ञान तकने का रास्ता रोकना है।

'याय मनुष्य के जीवन का सर्वोपरि तत्त्व है। न्याय करते में कारण बताने से इन्कार का अर्थ 'याय की सभावना को ही स्वस्त करना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 'भारतीय सविधान' में 'याय से साफ साफ इन्कार का प्रावधान बाकायदे मौजूद है। समझना मुश्किल है कि जब किसी याचिका या मामले को निरस्त क्यों किया जा रहा है, यह बताने की कोई जरूरत ही नहीं हो, तब 'याय या कानून की प्रासंगिकता ही क्या रह जाती है ?

हालांकि इस सदम में कई बातें हम सिलसिलेवार उठाना चाहेंगे, क्योंकि कानून और 'याय हमारे मायाजिक जीवन के अत्यन्त गहरे महत्त्व के सवाल हैं, लेकिन इतना कहना जरूरी लगता है कि मनुष्य एक गतिमान सृष्टि है। चूंकि वस्तुएं उसकी चेतना से जुड़ी हैं, इस लिए उसकी चेतना के वृत्त से बाहर, या ऊपर होते ही प्रत्येक वस्तु निरर्थक ही नहीं बल्कि घातक भी हो जाती है। संविधान इस नियम का अपवाद नहीं। संविधान के प्रति निष्ठा की बुनियादी मांग अधानु मोदन की नहीं चेतनासम्पन्न जागृत नागरिकों के रूप में हित के हर सवाल पर निरंतर बहस जारी रखने की ही हो सकती है, क्योंकि—वादे वादे जायते तत्वबोध।

कारण बताने में इकार खुद के स्वच्छाचार और भठ पर बहस को बचाने की चालाकी के सिवा कुछ नहीं। इतना हर कोई जानता है कि विधि में युक्तिसंगतता का प्रश्न सबसे प्रथम है और कारण नहीं बताना युक्तिसंगतता पर मिट्टी उलोचन के सिवा कुछ नहीं।

भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का कारण स्वयंसिद्ध है। ज्ञान विज्ञान के सार सोपान कारणों पर टिके हैं। ज्ञान का प्रथम आधार ही यह है कि अकारण कुछ नहीं। विवेक का भी कारण हुआ करता है। विवेक की पहली मांग कारण की होगी। ऐसे में विवेकाधिकार का उपयोग कारण बताने से इकार की छठ के रूप में करना सिवा के नूनी घृतता के और क्या है? अफमास कि विधि एवं 'याय की हत्या का यह प्रावधान हमारे संविधान में पूरी मिलजुजता में अंतर्भूत है। और अगर खिचड़ी के दो चार चावलो से ही उसकी परीक्षा सम्भव है, तब संविधान के ऐसे अंतर्द्विष्टों का उल्लेख किस तरह से निषिद्ध माना जा सकता, जो कि स्वयं उसके ही घोषित सिद्धांतों की मिट्टी पलीद करते हों?

उपरोक्त विवेचना में जाने का कारण, दरअसल, यह देख सकते

की बिनाता ही है कि हमारे संविधान के अन्तर्गत विपक्षी हित मुख्य है—दश लाख समाज, या कि सिर्फ राज्यपत्र का ? स्पष्ट है कि कारण बताते हैं इकार का प्रावधान सिर्फ राज्यपत्र के निहित स्वार्थों की सुरक्षा में ही परिकल्पित तथा विधिमण्डित किया गया है। मनुष्य का जितना कारण के अन्तर्गत जान पर निर्भर है। सोवतय का सर्वाधिक हितकारी व्यवस्था कहने के पीछे मुख्य तब ही यह है कि उत्तरदायी शासन में नागरिकों का हित का प्रत्येक सवाल उठाने का अधिकार रहेगा और सम्बद्ध अधिकारी का यह नैतिक ही नहीं मान्यते विधिक दायित्व होगा कि जवाब दे। यानी कारण बताये।

कारण चेतना का प्रथम प्रत्यय है। जो कारण बताने से इकार करे वह मनुष्य की चेतना का प्रथमशत्रु है, चाहे वह यादाघात के पक्ष पर ही क्या न बैठे हो। यदि याद का तो सारा विधान ही धूलि कारण के निर्धारण पर टिका है, इसलिए "यादवर्त्ता" तो दायित्व ही यह है कि कारण बताये। इस सिद्धांत एक अभिशाप के और क्या कहा जाय कि हमारा संविधान यादाधिकारियों को कारण नहीं बताने के लिए आवश्यक अधिकृत ही नहीं, बल्कि उत्प्रेरित भी करता है। शीन नहीं जानता कि छुट रतना ही छुट देना है।

जब सर्वोच्च न्यायालय में ही किसी भी महत्वपूर्ण याचिका को बिना कोई भी कारण बताये सिर्फ पदाधिकार के तहत निरस्त कर दिये जाने का प्रावधान मौजूद हो, तब जानने के मूलभूत अधिकार का दावा स्वतः ही एक सफेद झूठ सिद्ध हो जाता है। इस तथ्य की ओर इंगित करना इसलिए जरूरी लगा कि यह कारण नहीं बताने का मिलसिला राज्य व्यवस्था के छोटी से लेकर एही तब के राज्याधिकारियों के निद्रा में इस्तेमाल का साधन बना हुआ है। इस सर्वातीत, अपनी प्रकृति में ही गैरकानूनी कानून का इस्तेमाल सामान्य जनो की चेतना को कुचलने के काम आ रहा है। संविधान में ही मनुष्य की चेतना को कुचलने की छुट का होना देश के लिए अभिशाप है। एस

गम्भीर राष्ट्रीय महत्त्व के सवाल पर विधिवत बहस जरूरी है, क्योंकि एक बेतनासम्पन्न समाज की नींव ही इस बात पर टिकी होती है कि लोगो को जानने का अवसर सुलभ रहे।

दुचित्तापन सबसे बड़ी बाधा है। भारतीय संविधान में यह दुचित्तापन एक नहीं अनक जगह व्याप्त है और यह कारण है कि इसके सर्वोच्च शिल्पी प्रकाण्ड विधिब्रता डा० भीमराव अम्बेडकर को स्वयं आशंका प्रकट करनी पड़ी कि संविधान का दुरुपयोग भी हो सकता है। जबकि इतना तो वो स्वयं भी मली भांति जानते रहे होंगे कि किसी वस्तु का दुरुपयोग होना असंगत बात है और वस्तु के दुरुपयोग के अवसर खुले रखना बिल्कुल दूसरी।

हमारे संविधाननिर्माताओं के दुचित्तेपन का भी कारण है और वह समझना क सामान हाथ में में लावले की तरह स्पष्ट है। जानने के अधिकार को मूलभूत अधिकार मानते स इकार करते ही संविधान की शक्ति तागाही संविधान की निकल आनी है—और इस अबाधित मूलभूत अधिकार के रूप में संविधान में अतग्रथित परम की अनुमति राज्यतंत्र के अधिष्ठाताओं की ओर से नहीं—इस दुचित्तेपन में ही जानने के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में रखा तो गया मगर तंत्र के निहित स्वार्थों के आड़े आन पर इस बाधित किय जा सकने का चोर दरवाजा भी अत्यंत चतुर्गई के साथ बाकायद रख छोड़ा गया। विशेषाधिकार' इसी चोर-दरवाजे का विधिमण्डित नामांकन है। साफ है कि राज्यतंत्र के हक में रख छोड़े गये इस चोर दरवाजे का इस्तेमाल कोई भी राज्याधिकारी जब चाहे, पूरी तरह नि शक तथा निरकुश भाव से कर सकता है। मागे जाने पर इस बात के एक नहीं, अनेक दस्तावेजी सबूत देने का हम वादा करते हैं।

इतना हम पुन दोहराना चाहेंगे कि सवाल करना ही वास्तव में सम्मान करना है। हम जिस व्यक्ति को जितना सम्भ्रात, विद्वान या

बुजुग मानते हैं उससे उत्तम ही गहरे सवाल बार बार करते हैं। सवाल से सिर्फ वही विदवते हैं, जा चेतना को कुचलने का इरादा रखते हो।

सविधान सवालो से ही गतिमान हो सकता है, अद्यानुमोदन से नहीं। विवेकाधिकार को सवाल से ऊपर से जाना कानून को आदमी से ऊपर से जाने की साजिश के सिवा कुछ नहीं। आदमी और कानून के बीच का सम्बन्ध नतिव रूप में वही समाप्त हो जाता है, जहाँ कानून आदमी से बड़ा हो जाय। इसके बाद कानून राज्यतन्त्र के स्वच्छाचार का हथियार मात्र रह जाता है और लोकतन्त्र में यह बहस जल्दी है कि कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है।

कानून का राज्य

स्वाधीनता के न चार दशकों में क्या कभी इस सवाल में भी गये हम कि आखिर सरकार को बार-बार यह दोहराने की जरूरत क्यों पड़ती रहती होगी कि 'जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होगा ?' अभी सत्तीप्रथा निरोधक अधिनियम की बहस के दौरान भी सरकार को अत्यंत पभीर रूप में यही चिंता प्रकट करनी पड़ी कि कानून तो हम बनाये दे रहे हैं, लेकिन जब तक खुद जनता में सामाजिक जागृति नहीं आएगी, सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। यानी जब तक जनता सरकार का हाथ बँटाने को बाध नहीं बढ़ेगी, कानून अपना प्रभावी परिणाम दिखा नहीं सकेगा।

सरकार का कहना सिर माथे लेकिन अगर इस सवाल में जाएँ कि 'जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी' कहकर हमारी सरकारें दरअसल कहना क्या चाहती हैं, तो कई दिलचस्प, लेकिन उतने ही नुक्सानदेह नतीजे सामने आयेंगे, क्योंकि सरकार की चिंता से एक ध्वनि यह भी निकलती है कि कानून को अमल में लाने की नैतिक (अथवा सामाजिक) जिम्मेदारी जनता पर भी उतनी ही आयद

होती है, जितनी सरकार पर ! सरकार अपनी यह सदाशयता भलकाती भी साफ दिखाई पड़ेगी कि वह कानून को अमल में लाने के काम में नागरिकों से भी बराबर की साझेदारी चाहती है। यह प्रकारांतर से प्रशासन में जनता की भागीदारी के अवसर उत्पन्न करना है। यानी कानून का राज्य चलाने की अवधारणा में जनता को साझे में राज्य चलाने की आकांक्षा मौजूद है, किंतु व्यावहारिक कठिनाई है यह कि अगर जनता ही साथ नहीं दे, तब सरकार लाख चाहने पर भी कानून का पालन कैसे करा सकेगी ?

जाहिर है कि जनता पर (भी) कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी आवंटित करने की इस सदाशयता के पीछे शुद्ध राजनीतिक कौशल्यापन के सिवा और कोई कारण मौजूद नहीं, क्योंकि कानून को अमली जामा पहनाने की पूरी पूरी जिम्मेदारी भी उसी पर है, जिसने कानून बनाने का काम हाथा में ले रखा हो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक ही तंत्र के अलग-अलग अंग हैं, और कानून बनाने से लेकर, उसके अनुसार शासन चलाने तक की सारी जिम्मेदारियाँ इन पर ही आवंटित होती हैं। कानून को चलाना जनता का काम नहीं है। अब यही हम यह जरूरी सवाल पूछना जरूर चाहेंगे कि सरकार आखिर और किस मज की दवा है, अगर कि कानून को अमल में लाने, यानी कानून का राज्य चलाने का काम सभालने, में ही उसकी नाती मरती हो ? बड़े बड़े का उनके बाप को भी नामी याद दिला देने वाले प्रधानमंत्री का यह तक कितना मासूम है कि सिर्फ कानून बना देने में ही ? या होगा ?

हकीकत कुछ और है। जितनी या जिस तरह के, कानून अपनी गद्दी कायम रखने को जरूरी हो, उनको अमल में लाने में सरकार ने आज तक कोई कोताही नहीं बरती है, लेकिन वहीं कानून को अमल में लाने में सामाजिक जागरूकता और सरलता तो समझ हो, किंतु वोट की राजनीति की ओर झुकाव, वहाँ कानून की राह के पल्लू में तुरत

जनता के मते भाड़ फेंकने में सरकार का कुछ दूर नहीं गहरी बायम रखने को चुटकियों में आपात्स्थिति लागू कर देने में समय सरकार का सती प्रथा, बेगारी, बधुआ मजदूरी, साम्प्रदायिकता से लेकर उठाईगीरी तक के हर सामाजिक महत्व के मामले में सिर्फ कानून बना देने से क्या होगा? की चिन्ता में व्याकुल दिखाई पड़ना, किम बात का सबूत माना जाय?

बाबा तुलसीदास 'समर्थ को नहीं दोष गुसाई' यो ही नहीं कह गये। कठपडितों के कोप से वचन को शम्बूक का वध करने का पातक मोल लेते प्रभु राम तक की दुदशा को देखा, तब कहा। राज्य की बुभुक्षा कसे करुणामय कहे गये प्रभु की संवेदना तक को मार देती है, इस चेतना में ही तुलसीदास ने आखिर आखिर राम को बरशा नहीं। कवि के हाथ इससे अधिक कुछ होता भी नहीं कि वह मनुष्य के भीतर के औदात्य और राज्य के चरित्र की सीमाओं को दायमान कर दे।

जब भारत का प्रांतों के मुख्यमंत्रियों तक की छिगुली पर नचाने वाला सबसे प्रभुसत्ताधीन प्रधानमंत्री तक यह विनय और विवशता प्रदर्शित करता दिखायी पड़े कि सिर्फ कानून बना देने से क्या होगा, तब उससे यह सवाल पूछना भी जरूरी होगा कि सिर्फ कानून बनाने के लिए संसद की तो जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार की जरूरत क्यों होगी? जो सरकार- कहे कि कानून तो अमल में सिर्फ तभी लाय जा सकते हैं जबकि जनता इन्हें लागू और चरिताय करने में हाथ बटाय उमे इस सवाल का जवाब भी देना जरूर चाहिए कि सिर्फ जनहित के कानूनों को अमल में लाने में ही सरकार खुद को इतना निकम्मा और नाकाबिल क्यों अनुभव करती है?

'सिर्फ कानून बना देने से क्या होगा' कहना दरअसल कानून को मर्जी के अनुसार बरतना ही है। जहां हमें जरूरी होगा, कानून को

होती है, जितनी सरकार पर। सरकार अपनी यह सदाशयता भनकाती भी साफ दिखाई पड़गी कि वह कानून को अमल में लाने के काम में नागरिकों से भी बराबर की साझेदारी चाहती है। यह प्रकारांतर से प्रशासन में जनता की भागीदारी के अवसर उत्पन्न करना है। यानी कानून का राज्य चलाने की अवधारणा में जनता का साझे में राज्य चलाने का आकांक्षा मौजूद है, किंतु "यावहारिक कठिनाई है यह कि अगर जनता ही साथ नहीं दे, तब सरकार लाख चाहने पर भी कानून का पालन कस कर सकेगी ?

जाहिर है कि जनता पर (भी) कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी आसपास करने की इस सदाशयता के पीछे शुद्ध राजनीतिक कौशल्यापन के सिवा और कोई कारण मौजूद नहीं, क्योंकि कानून को अमली जामा पहनाने की पूरी पूरी जिम्मेदारी भी उसी पर है, जिसने कानून बनाने का काम हाथा में ले रक्खा हो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक ही तंत्र के अलग अलग अंग हैं, और कानून बनाने से लेकर, उसके अनुसार शासन चलाने तक की सारी जिम्मेदारीयाँ इन पर ही आसपास होती हैं। कानून को चलाना जनता का काम नहीं है। अब यही हम यह जरूरी सवाल पूछना जरूर चाहेंगे कि सरकार आखिर और किस मज की दवा है, अगर कि कानून को अमल में लाने, यानी कानून का राज्य चलाने का काम सभालने, में ही उसकी तानी मरती हो ? बड़े बड़ों को उनके बाप की भी तानी याँ दिला देने वाले प्रधानमन्त्री का यह तक कितना मशूम है कि सिर्फ कानून बना देने में ही ? या होगा ?

हकीमत कुछ और है। जितना, या जिस तरह के, कानून अपनी गद्दी कायम रखने की जरूरी हो, उनको अमल में लाने में सरकार ने आज तक कोई कोताही नहीं बरती है लेकिन जहाँ कानून को अमल में लाने से सामाजिक जागृति और सरदा हो समय हो, कि तु थोड़ा की राजनीति को ओसिम वहाँ कानून की तुलना के पन्तू से तुरत

जनता के मते भाड फेंकने में सरकार का कुछ दूर नहीं। गद्दी कायम रखने की चुटकियों में आपात्स्थिति लागू कर देने में सप्रय सरकार का सती प्रथा, बेगारी, यधुआ मजदूरी, साम्प्रदायिकता से लेकर उठाईगीरी तक के हर सामाजिक महत्व के मामले में सिफ कानून बना देने से क्या होगा ? की चिंता में व्याकुल दिखाई पड़ना किस बात का सबूत माना जाय ?

बाबा सुलसीदास 'समर्थ को नहीं दाप गुसाई' यो ही नहीं कह गये। कठपडितों के कोप से बचने को शम्बूक का वध करने का पातन माल लेते प्रभु राम तक की दुदशा को देखा, तब कहा। राज्य की बुभुक्षा कैसे करुणामय कहे गये प्रभु की संवेदना तक को मार देती है, इस चेतना में ही सुलसीदास ने आखिर आखिर राम को बरणा नहीं। कवि के हाथ इससे अधिक कुछ होता भी नहीं कि वह मनुष्य के भीतर के औदार्य और राज्य के चरित्र की सीमाओं को दर्शयमान कर द।

जब भारत का प्रांतों के मुख्यमंत्रियों तक की शिगुली पर नचाने वाला सबसे प्रभुसत्ताधीन प्रधानमंत्री तक यह विनय और विवशता प्रदर्शित करता दिखायी पड़े कि सिफ कानून बना देने से क्या होगा, तब उससे यह सवाल पूछना भी जरूरी होगा कि सिफ कानून बनाने के लिए संसद की तो जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार की जरूरत क्यों होगी ? जो सरकार- कहे कि कानून तो अमल में सिफ तभी लाय जा सकते हैं जबकि जनता इन्हें लागू और चरिताय करने में हाथ बटाय उसे इस सवाल का जवाब भी देना जरूर चाहिए कि सिफ जनहित के कानूनों को अमल में लाने में ही सरकार खुद को इतना निकम्मा और नावांजिल क्या अनुभव करती है ?

'सिफ कानून बना देने से क्या होगा' कहना दरअसल कानून को मर्जी के अनुसार बरतना ही है। जहां हम जरूरी होगा, कानून को

वरतेंग और अमल में लायेंगे और जहाँ बोट की राजनीति खेलनी होगी, या जनता का बेवकूफ बनाये रखना होगा, वहाँ कानून को सिर्फ बनाकर ही हाथ पीछे समेट लिया जायेंगे—इससे ज्यादा राज्य का मनमानापन और क्या हो सकता है ?

सती प्रथा का कलक समाज के साथे से कभी नहीं मिटाया जा सकेगा क्योंकि जनता में सामाजिक जागृति नहीं। दसपुत्र मूलन की हनुमतपुच्छ जैसी अनन्त योजनाओं का भी कभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सकेगा, क्योंकि जनता कानून का साथ नहीं दे रही। पंजाब में आतंकवाद का मिटना असंभव होता जा रहा है, क्योंकि जनता आतंकवाद का मुकाबला करने की आग नहीं आ रही। बकारी बेहानी की कोई समस्या हल नहीं होगी क्योंकि जनता हाथ आगे बढ़ाने में कजूसी कर रही है। ऐसे में सवाल पैदा होता है यह कि जब सारे काम आखिर-आखिर जनता का ही करन जरूरी हैं, तब जनता के खून-पसीने की कमाई की पश्चितार हाटला की अत्याशिया और शाही आरामगाही में फूकन जाने हाकिमों हुक्मों मघा हुजरा गरीबपरवरों की ऐसी अक्षण्डराष्ट्रीय जरूरत क्या है इस उस की जाकि कानून को सिर्फ बनाने की चीज समझन हो, जनहित में उत्तन की नहीं।

आदमी की बदनाम को गाली या मखौन समझना ठीक नहीं। अगर कोई सरकार कानून को सिर्फ बनाने की दस्तु घोषित करे, ता उसका गरबान पकड़कर पूछने का हक जनता की भी है कि जो समुहो चलने का सिर्फ हाथ में पकड़ने की चीज समझनी हो, रोटी चलने की नहीं, वह चूल्हे चोके में महराजिन का रतबा कान्ती क्यों फिरे ? हम कोई नयी बात नहीं कर रहे हैं। कालांतर में भी राज्य की बेहवाई में उत्पीडित जनता में नाना प्रकार के निस्स दृष्टांत गढ़कर ही स्वयं को सात्वना देने की कुछ प्रोग्रस की है क्योंकि इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस दल में सामाजिक जागृति नदारद हो वहाँ की जनता की अपनी

ही जूती से मत्था पुजवाना, और इसे ही लोकतंत्र कहना पड़ता है।
 जब यथा राज्य की उत्पत्ति का तो आधारभूत सिद्धांत ही यह है कि
 जनहित में कानून बनाने और उह अमल में लाने वाला तंत्र।

राज्य की एकमात्र प्रासंगिकता विधि के सम्यक् निर्माण और
 परिपालन में है। जो राज्यव्यवस्था इसमें अक्षम हो, या इससे कभी
 काटे, वह कानून का राज्य कभी कायम नहीं कर सकती। हमारी
 मौजूदा राज्य व्यवस्था का चरित्र यही है। उसकी एकमात्र चिंता
 और सारी मशक्कत राज्य का कानून जनता के मते घोपे रखने
 की है। कानून के राज्य की अवधारणा सिर्फ संविधान के पृष्ठों पर
 उद्घोषणा की वस्तु है क्योंकि कानून को अमल में लाने की सारी
 प्रक्रिया बोट की राजनीति यानी गद्दी के पाया के हिमाय से तय होती
 है।

विपक्ष के जुझारू मोर्चे भी कानून के राज्य का हवाला सिर्फ
 तभी तक देते हैं जब तक की खुद गद्दी तक नहीं पहुंच जायें। इसी-
 लिए मोकास फयरफैक्स काण्डा की घस से समद का ठूँक दन में समथ
 नाना प्रकार के जुझारू विपक्षी मोर्चापारियों ने भी यह सवाल कभी
 आज तक झूलकर भी नहीं उठाया कि जिन कानूनों की शमल में नहीं
 लाया जाना है, उनका बनाया जाना संविधान और जनता, दोनों के
 साथ धोखाधड़ी है।

सविधान हमारे जीवन की किताब

देश के नागरिकों का जितना प्रतिशत होगा, जो 'सविधान' का सरकारी इस्तेमाल की जगह स्वयं के हक हकूक की किताब के रूप में देखे ? जिस जितना बाकायदे समझ हो कि 'सविधान' सरकारी तन्त्र की तरफों पोषी नहीं बल्कि हमारे सामाजिक जीवन की सबसे जरूरी किताब है ? यह इकीकत है कि एक बार का पूजाघर के धमधम से कोई वास्ता नहीं रखने में कोई हज नहीं, मगर सविधान से बेसरोकारी का मतलब अपने इह गिद जँघेरा इकटठा रखना ही होगा ।

राज्य व्यवस्था में उदासीन लोग ही चेतन समाज की जगह जड़ सम्प्रदायों की बुनियाद बनते हैं । लोगों में इस बात की चेतना होनी चाहिये कि हम राटो से पहले नहीं भी सही, तो कम से कम साथ साथ या आगे पीछे सविधान को भी जलट पलट कर देखेंगे जरूर, क्योंकि यही वह किताब है जिसकी आयनें हमारी रोटो की किस्म और धूलें की आंच तक को प्रभावित करती हैं । जिस समाज में स्वयं के विपरीत सविधान को कूड़ाघर के सिपुद करने की समता नहीं हो, उसे इक्कीसवीं सदी में से जाना भेड़ों के झुण्डों की इक्कीसवीं सदी में पट्ट घाने के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ तक समाजनिर्पेक्ष

काल का प्रश्न है, किमी भी अगली शताब्दी में सिफ आदमी नहीं पहुँचता—भेड़ें भी साथ साथ जाती हैं।

आदमी की पहचान हो इसमें है कि वह किसी भी देश काल में किस हैसियत से रहता है। भेड़ें अपराधी नहीं, वा अपना जीवन जीती हैं, किन्तु वह व्यक्ति एक गम्भीर सामाजिक विकृति है, जो भेड़ों की तरह जीता है। वह राज्य बबर और आत्तायी है, जो लोगों को भेड़ों की नियति में कैद रखना चाहे। चेतन समाज की पहली जिज्ञासा राज्य के चरित्र को जानने की होगी और इसके लिये 'सविधान' की पहचानना जरूरी होगा।

हर वस्तु के दो छोर हैं। सविधान के भी। सविधान को जानने का मतलब उसका तातापाठ नहीं। ज्ञान का एक छोर किताबी, दूसरा क्रियात्मक है हमारे अनेक बड़े बड़े सविधानवेत्ता 'भारतीय सविधान' के सिफ किताबी विशेषज्ञ हैं, क्योंकि ये सविधान को देश-काल के सदर्भ में रखकर देखने के विवेक से भ्रूय हैं। इनकी सविधान मातण्डता देश के सामान्य जनो के किसी काम की नहीं। सविधान इनके लिये खुद के घड़े की किताब है और ज्ञान जब घघा बनकर रह जाय, तब अघेरा और बढ़ाता है। ये नहीं जानते कि जो समाज के काम नहीं आ सके ऐसा ज्ञान बिल्ली का गू है। इन सविधानवेत्ताओं की कोई सकारात्मक सामाजिक भूमिका नहीं। यायतत्र के अभयारण्य में विचरते सफेद हाथी हैं ये। इनका बानूनी कठजान किताबी लोद है। ये इस देश के सामान्य जन के किसी काम के नहीं। ये सविधान में देश के सामान्य जनो के हितो की रक्षा के बुनियादी सवाल कभी नहीं उठायेगे। ऐसे में चाहे जब सदबुद्धि बाये, स्वयं के हित के सवाल, आखिर-आखिर, हमें खुद ही उठाने होंगे।

यह भौतिक जगत वस्तुओं का पुज है। आदमी और सविधान भी वस्तु है किन्तु जानने की चेतना सिर्फ आदमी में होने से 'जानता'

सिर्फ यही है। मवाल जाँच पड़ताल और ध्यान-पटव, ये जानने के अपरिहार्य अंग हैं। सारे ज्ञान विज्ञान आदमी के इसी जानने के अनवरत उद्यम की उपज है। आदमी वस्तु को खुद के ज्ञान की परिधि में लये बिना कभी नहीं धरतता। जो धरतता हो, वह मूढ़ है। चेतन लोग जिस वस्तु को रूप में नहीं जानते उसे भी परिणाम से जाँचते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमने सविधान का पाठ किया हो। सविधान कोई स्वकेन्द्रित वस्तु नहीं। उसका क्रियात्मक क्षेत्र अत्यन्त विशाल है और जैसा कि पहले भी कहा, उसके स्पर्श हमारे चूल्हों की भींच तक व्याप्त है।

वस्तु के रूप और उसके क्रिया वयन की प्रक्रिया को भी जानना ज्ञान का उच्चतर सोपान है, किन्तु हर विषय का विशद ज्ञान असम्भव है। सविधान के रूप और उसकी प्रक्रिया का विशद ज्ञान सिर्फ उन्हें ही सम्भव है जो इसमें अपना ध्यान लगाते हो, किन्तु वस्तु की अंतिम कसौटी है—परिणाम। 'भारतीय सविधान' अब तक में लगभग चार दशक पुराना हो चुका और नतीजे समाने हैं। ये नतीजे सकारात्मक हो नव हमें कुछ नहीं कहना, किन्तु अगर नकारात्मक हों—जो कि हैं ही—तब देखना जरूरी होगा कि खोट कहाँ है। सविधान में या कि सविधान को निर्मित आत्मापित और व्यवहृत करने वाला के चरित्र में? हम सविधान पर इसी प्रसंग में बात करना चाहें। किन्तु हम सिर्फ उस एक वाक्यांश को लेकर जो कि सविधान का केन्द्रीय तत्त्व है।

राज्य और कानून समाज की सुचारु व्यवस्था की संकल्पना की उपज हैं। सविधान कानून की केन्द्रीय पुस्तक है। चूँकि राज्य समाज की उत्पत्ति इसलिये सविधान भी एक सामाजिक वस्तु है। वस्तु का इस्तेमाल आदमी करता है। ऐसे में, देखना जरूरी होगा कि सविधान का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं। यानी कि सविधान के पीछे का इरादा क्या है और अगर इरादा सही है, तो परिणाम उलटें

क्यों निकल रहे हैं। 'भारतीय संविधान' की निर्मिति का घोषित इरादा इस प्रकार है—

हम भारत के लोग, भारत की एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक घम निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक श्रम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अटूटता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बंधने के लिए बूढ़ सकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करत हैं।

साफ है इरादे के घोषित रूप में वही कोई खाट नहीं सिवा एक इस अन्त छिद्र के कि भारत के लोगों की तरफ से हम उनके प्रति निधि' की जगह हम भारत के लोग कहा गया है। दखने में यह निहायत छोटी, लेकिन गूढ़ाय में अत्यंत ही महत्व की बात है। दरअसल भारत के लोगों की तरफ से हम उनके प्रतिनिधि' की जगह हम भारत के लोग कहकर, भारत के सार जन गणों का एकाधिपत्य कांग्रेसी हुकूमत के अलम्बरदारों में अन्तर्भूत कर लिया गया। भाषा कोई मसूल नहीं।

भाषा सबसे बड़ी और सबसे कठिन वस्तु है, क्योंकि जानने का सबसे सुलभ और जल्द साधन यही है। क्या हमारा ध्यान कभी इस बात पर गया और हमने जानने की कोशिश की कि 'हम भारत के लोग' से आशय किन लोगों से है? क्योंकि यह तो तय है कि संविधान भारत के तमाम लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि उनके निमित्त कुछ ऐसे लोगों के द्वारा निर्मित, अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया

गया, जो उस दौर में देश का राजनैतिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
ऐस में स्पष्ट है कि या तो हमारे सविधाननिर्माताओं को इस बात
की कोई चेतना ही नहीं थी कि भाषा को हमेशा उसके वस्तुगत अर्थ
में ही धरता जाना चाहिये—और या वे जानते थे कि खुद के छद्म
पर भाषा का आवरण कैसे ढाला जा सकता है।

लेकिन चलिए अगर मान लें कि इरादे में कोई खोट नहीं था तो
देखें जरा कि परिणाम क्या निकला। वही हम भारत के लोग कहते
थे। वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक याव के समान
भागीदार लोग की शक्ति सामन उभरती है? प्रतिष्ठा अवसर की
समानता की गरिमा में लीप्त चेहरे देश की दशा दिशाओं में नियाई
पड़ते हैं? यति की गरिमा और राष्ट्र की अखण्डता की प्रतिभूति
चारों तरफ नजर आती है?

यही हम यह बुनियादी सवाल फिर बहुत क निय उठाना
चाहते कि सविधान की प्रस्तावना में उद्धोषित हम भारत के
लोग वाक्यांश का तात्पर्य दरअसल भारत के कितने लोगो से है?
और अगर इरादा में भारत के समस्त नागरिकों से, तब आर्थिक
सम्पन्नता, राजनैतिक एकाधिपत्य तथा सामाजिक निद्रा दृष्टा की
सारी चमकार आखिर देश के तिरप को प्रतिगत लोगो के बिचने चुपड़े
चेहरो तक ही सीमित क्या है? बाकी के अठानवे प्रतिगत भारत के
लोगो के चेहरो पर आज भी आर्थिक विपन्नता सामाजिक त्रासदो और
अ याव तथा उत्पीडन की मन्त्रिणा ही क्यों भिनभिना रही हैं?

कितने लोगो की गरिमा और आत्माभिव्यक्ति का स्वास्त उठाना
चाहा गया था आखिर भारतीय सविधान में? और अगर सचमुच
भारत के समस्त लोगो की गरिमा आत्माभिव्यक्ति तथा आर्थिक
सामाजिक राजनैतिक भुक्ति का संकल्प अंगीकृत किया गया, तो
परिणाम इसके बिलकुल उल्टा निकलते चले जाने के बावजूद
सविधान को क्यों का लो चलन में रखने की जरूरत क्या है? अगर

कोई दावा करे कि सशोधन किये गए हैं तो हमारा जवाब होगा कि सिर्फ रूप में चरित्र में नहीं।

इस बात पर ध्यान देना जरूरी होगा कि 'वाक्य' आदमी के वाक् का प्रतिनिधित्व करता है। भाषा दश, काल और सन्दर्भ से जुड़ी है। किस स्थान पर, किस प्रसंग में और किसके द्वारा कहा गया है कोई वाक्य, इसी से तय होता है उसका वास्तविक और पूरा मतलब। सविधान दश की सबसे बड़ी कानूनी किताब है। सविधान में के प्रत्येक वाक्य हमारी सामाजिक नियति का निर्धारण बोलता है। सविधान की प्रस्तावना में यदि धोपित है हम भारत के लोग, तो आगे के पृष्ठ पढ़ने से पढ़ने जरूरी होगा हम भारत के लोग' वाक्यांश का सही सही मतलब समझना। हम सचमुच जानना चाहते हैं कि हम भारत के लोग' का असली मतलब क्या है और कि हमें भी हमें शामिल माना गया है या नहीं?

यह एक बुनियादी सवाल है और इस सवाल को हम भारत के उन तमाम नागरिकों की ओर से उठाना चाह रहे हैं जिनके लिये आर्थिक सामाजिक-राजनैतिक 'याव' की आशाएँ सपने की सामग्रियाँ बन चुकी हैं। जिनके चेहरे पर, आत्माभिभ्यक्ति की दीप्ति की जगह असुरक्षा और आत्महीनता की राख पुती हुई दूर से ही साफ साफ दिखाई पड़ जाती है। जिनको कानून और 'याव' धज्ज का पेंड हो गये हैं और जिन्हें कदम कदम पर खुद की गरिमा और अस्मिता का सौदा करना पड़ता है। हम इन्हीं में शामिल हैं। ऐसे लोगों की मर्यादा अस्थी प्रतिशस्त से कम पड़ती है, तो हमारा सवाल निरर्थक है किंतु कदाचित् ज़्यादा तो सवाल का जवाब जरूरी है।

सविधान की प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' यो ही कहने को नहीं एक पुस्ता इरादे में कहा गया और चूँकि यह हम भारत के लोग' ही सविधान का के द्रीय तथा वारक तत्व है, इसलिये सिर्फ इस एक

वाक्यांश के मर्म को जानते ही हम इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि हम जानना चाहते हैं। हमें जानना आता है।

जिसके पहले पहला ही पना नहीं पड़े उसका किताब का आखिर पन्ने तक पढ़ना किताब का सिर्फ चाटना है। आदमी जब किताब का समझने ब्रह्मण और हित में बदलने की जगह चाटने की सामग्री बना ले तो उसे किताबी कीड़ा कहा जाता है। जो हम भारत के लोग वाक्यांश का मतलब नहीं जानते, या कि जान ब्रह्मकर इस सवाल में जाना नहीं चाहते, ऐसे सविधानमातण्ड विद्वान किताबी कीड़े हैं।

सड़क से लेकर सड़क और मज्जी से लेकर सविधान, किसी भी वस्तु का महत्व आदमी के आगे तभी बनता है, जब वह जानना चाहे, जानने का उद्यम करे और जो वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसकी उत्तम ही अधिक ध्यान से देखे। 'हम भारत के लोग' का महत्व हम कितना आंकते हैं? जिस क्षण हमारे ध्यान में यह बात आये कि 'हम भारत के लोग' कहकर आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, सिर्फ उसी क्षण 'भारतीय सविधान' के इस 'आप्त वाक्य' पर भी ठीक ठीक नजर पड़ेगी और तब ही हम वास्तव में जानना चाहेंगे कि सविधान में घोषित हम भारत के लोग' का सही मही मतलब और उसने पीछे का वास्तविक इरादा क्या है। यही यह शक नहीं उठाना जाय कि अभी कुछ देर पहले जिसे वाक्यांश, 'अब उसे ही वाक्य' यमो कहा जा रहा है। हम कहेंगे 'वाक्' की चरितायता उसके अर्थ में है, विराम चिह्न। म नहीं। जहाँ अर्थ का अन्वय हो, वहाँ सारे विरामचिह्न और व्याकरणसम्मतता के बावजूद भाषा गलत होगी और भाषा तभी गलत होती है जब इरादा गलत हो।

भारतीय सविधान'की भाषा गलत है, तो इसलिये कि इसका पीछे का इरादा गलत है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर, सर्वोच्च न्यायालय के सविधानमातण्डों तक, आप किसी से भी जरा पूछ दें

कि सविधान की प्रस्तावना में के आप्त वाक्य 'हम भारत के लोग' का सही मतलब और इसके पीछे का वास्तविक इरादा क्या है ? इनमें से कोई भी इस सबसे बड़े राष्ट्रीय (कानूनी) महत्व के सवाल का जवाब न तो देना चाहेंगे और न यह इनके बूते की बात होगा, क्योंकि सवाल का जवाब भी सिर्फ वही दे सकते हैं, जो सवाल में जाते हों। हमारे तथाकथित भाग्यविधाता जन-मन-गण अधिनायक यदि इस सवाल में गये होते कि आखिर सविधान के आप्त वाक्य 'हम भारत के लोग' की परिधि कहाँ तक जानी चाहिये तो सविधान का सारा ढाँचा ही बदल गया होता। तब सारे विधि विधान भारत के शत प्रतिशत लोगों की सामाजिक आर्थिक राजनैतिक मुक्ति, आत्माभिव्यक्ति और गरिमा की चिन्ता का केन्द्र में रखकर तय हुए होते। तब राष्ट्र की अखण्डता को भारत के जन सामान्य की अस्मिता से जोड़कर देखा गया होता।

अब अगर कोई यह जवाब दे कि इरादा यही था, तो हम कहेंगे, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि जिनका इरादा गलत नहीं होता, वो हमेशा परिणाम पर नजर रखते हैं। परिणाम अगर इरादे के उल्टा निकले, तो वस्तु और प्रक्रिया, दोनों को जाँचते और बदलते हैं 'भारतीय सविधान' को जाँचने या बदलने की कोई पहल हमारे भारत भाग्यविधाताओं में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने का कारण है और वह यह कि चूँकि सविधान के चार दशकों के क्रियात्मक प्रतिफलन के नतीजे सिर्फ अठानवे प्रतिशत उन भारतवासियों के विपरीत निकले हैं जो सविधान की प्रस्तावना में के 'हम भारत के लोग' की परिधि में नहीं आते। जो 'भारत के लोग' ठीक उसी अर्थ में नहीं जिस अर्थ में कि सविधाननिमाता विद्वानों के वाञ्छित डेढ़ दश प्रतिशत 'भारत के लोग' हैं।

विधि की कसौटी सच है और सच की कसौटी हित। मौजूदा सविधान से हम अठानव्वे प्रतिशत भारत के लोगों का हित नहीं हुआ है। सविधान की प्रस्तावना में का आप्त वाक्य 'हम भारत के लोग' झूठ है, क्योंकि उसमें न भारत के सारे लोग शामिल थे, न हैं और न सबके हित के सवाल। अथवा सविधान की प्रस्तावना में ही यह भी जरूर कह दिया गया होता कि इस प्रस्तावना में के सदस्य के विपरीत आचरण करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रद्रोही बरार दिया जायगा। तब राष्ट्रीय सबलों की भार सिफ हम अठानव्वे प्रतिशत दीन-हीनों पर ही नहीं होती। तब देश के भयावह रूप से आर्थिक तथा अन्य सकटों से ग्रस्त होने के दौर में काबूट पाक, सरिस्का, मोतीमहल, अण्डमान और सदाद्रोषों के मत्तबिसास हमारा मसूल नहीं उड़ा रहे हाने। तब राष्ट्र के आर्थिक रूप से सकटग्रस्त होने के दौर में और अधिक घनाढ्य होते जाने वाले लोगों की जगह, पचतारकी बिसासगृहो नहीं, सोहे के फाटक वाले बारागारी में होगी।

राष्ट्र की सांसत सिफ वही नहीं, जो कि राष्ट्रद्रोह का काय करते हों, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की आघा है, जिसमें आत्मानिव्यक्ति की चेतना और गरिमा नबारवही। राष्ट्र अपने वासिया का भोगोलिक-सांस्कृतिक धिम्ब हुआ करता है। जो दशा निवासियो, वही राष्ट्र की होती है। जो दीनता और अडता में घिरे रहे, वही राष्ट्र को भी दीन और अड बनाते हैं। सविधान में के आप्त वाक्य हम भारत के लोग का सही मतलब और इसके पीछे का वास्तविक इरादा क्या है इस सवाल के प्रति अंधे गूँगे और बहरे रहकर हम सिफ अपनी नही, राष्ट्र की भी गम्भीर क्षति कर रहे हैं।

आश्चर्य कि हमारा ध्यान इस ओर कभी गया ही नहीं कि सविधान की प्रस्तावना में का 'हम भारत के लोग' वाक्य हम भारतवासियो को दो अलग-अलग हिस्सों में बाँट दिये गये होने का सूचक है। एक हिस्सा

यह है, जो अपनी भाषा-भूषा और चमक दमक, सभी में हमसे पूरी तरह असंग है। सविधान ने उनके प्रभुत्व की चमकार को सतत कायम रखा है। दूसरा हिस्सा हम हैं—हम भारत के लोग, जिनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। जिनके लिये सविधान प्रभुसत्ता यग के महाश्वेत ऐरायत के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं हुआ है।

सफेद होना ही सच्चा होना भी नहीं। रंग रूप अतवस्तु से जुड़े हैं और अतववस्तु पहरी जाँच पड़ताल की माँग करती है। बगुल और कोयल का अंतर दोनों व रंग रूप ही नहीं, भाषा में भी बोलता है। बगुल को आदमी ने देखा, कोयल को सुना और इन दोनों के बीच के अंतर को अनुभव किया, तब ही तय हुआ कि पहचान सही है। ऐसे में अगर हम सविधान को देखना, सुनना और अनुभव करना चाहें तो इसमें आपत्ति की गुंजाइश क्योंकर होगी? और अगर हम यहाँ फिर यह सवाल उठाना चाहें कि सविधान की प्रस्तावना ही झूठ से प्रारम्भ क्यों है, तो इस भी बहस की चीज ही माना जाना चाहिये, क्योंकि सच और झूठ बहस की वस्तु हैं और बहस का नियेष सिर्फ यो करते हैं, जो झूठ को सच के रूप में बेच छाने का घधा खताना चाहें।

हमारे लेखे सविधान में का 'हम भारत के लोग' वाक्यांश शुद्ध सफेद झूठ है, क्योंकि इसके द्वारा चन्द प्रभुसत्तावर्गीय लोगों ने समग्र भारतवासियों का सप्रभुत्व तथा अधिनायकत्व हथिया लिया। इस तथ्य की प्रस्तावना में स्पष्ट रखा जाना चाहिये था कि 'भारत के मौजूदा जनप्रतिनिधियों के बहुमत के द्वारा एतवय सविधान को अंगीकृत, अभिनियमित तथा आत्मार्पित किया जाता है।'

'हम भारत के लोग' वाक्यांश से यह दावा जाहिर होता है कि भारत के सारे लोग—या इन लोगों के हित के समान—इस सविधान में शामिल हैं।

जो शामिल नहीं, उन्हें भी शामिल बताना, धुंध रचना है, और धुंध रचना ही झूठ को सच साबित करने का घधा खताना है। हकीकत

है यह कि मौजूदा सविधान का सारा ढाँचा तो राज्य को बे-द मे रखकर तैयार किया गया, लेकिन इसके संवैधानिक ढाँचों की परिधि पूरे राष्ट्र के दृष्ट तक फैला दी गई। प्रस्तावना में ही यह संवैधानिक खोखल साफ उजागर है क्योंकि इसमें का सारा बंदबोलापन पूरी तरह अमूर्त है। भारत के लोगो की इस प्रस्तावना (बल्कि पूरे सविधान) में कहीं कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं की गई है। वही यह नहीं बताया गया है कि भारत के लोग कहने का मतलब क्या है। हमारे विद्वान सवधानमातृ, शायद, इस तथ्य को भूल ही गये कि रहने वालों का सवाल उनकी दशा और दिशा के सवालों से जुड़ा है। अगर 'भारतीय सविधान' को सचमुच भारत के सारे लोगो के हित में आत्मामित किया गया होता तो न ही यह अंग्रेजो की जूठन में निमित होता और न इसमें भारत की डेढ़ प्रतिशत प्रभुसत्तावर्गीय जमात के शेरकुड स्टीफन-हून पब्लिक स्कूलो की शाही व्यवस्था के चौर दरवाजे खुले रहते और न अठान-प्रतिशत की सड़क शिक्षा प्रणाली या अशिक्षा के हवाले किया जाता। भारत के लोगो की डेढ़ और साढ़े अठान के प्रतिशत के अनुपात में अलग अलग बाँटने के सारे चौर दरवाजे सविधान में अंतर्भूत करते इस हम भारत के लोग आपन वाक्य की हकीकत क्या मानी जाय ?

अब हम आना चाहेंगे आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक "पाप और आत्मामि यक्ति के सवाल पर। सविधान की आत्मामि यक्ति ही है।

कि तु भारत के बितन प्रतिशत लोगो की आत्मामि यक्ति का दावा करना चाहेंगे हम इस सविधान में ? अपने ब्रिटिश आकाओ की अंग्रेजो की भारत के किनन लोगो की आत्मामि यक्ति की भाषा बरार देना चाहते थे, हमारे सविधान-निर्माता प्रभु ? जब कि आत्मामि यक्ति का सवाल आदमी से दीपर सवाल नहीं और आदमी की आत्मा के जीभ ही नहीं, आत्मा तक नालबुद्ध है—भाषा से। सविधान की पहली शत

है कि उसे राष्ट्र की भाषा में होना चाहिये। विदशी भाषा में किसी साम्राज्यवादी उपनिवेश का सविधान हो तैयार हो सकता है। आत्माभिषक्ति का सवास आदमी की जिदगी के हाल से बंधा है।

जिस भाषा को देश व अठानठे प्रतिगत नाग नहीं जानते हो, उस देश के सर्वोच्च पाठशाला की भाषा बनाना लोगों की पाप पा सकन की बाधा का गना घाटना है। मनुष्य व जीवन का सर्वोच्च तत्त्व है— पाप। पाप की भाषा का विदशी होना देश व लोगों पर बहुत आतंक जमाना है कि जिसे 'पाप पाप' का बहुत शोक हो, उनका विदशी भाषा जानना जरूरी होगा। और जाहिर है कि विदशी भाषा में वक्तवा उन्ही की सर्वोपरि होगी, जो दून शेरबुड स्टीफन मार्क द्विदिश अमेरिकी शिक्षा प्रतिष्ठानों की अम्याशिया में समर्थ हो। जो सविधान का, राष्ट्र के बहान, स्वयं का आत्मपित्त करने की वला जानत हो। जिन्होंने इस सत्य का धाड़ में झोक दिया हो कि जिनकी भाषा औपनिवेशिक हो, उनका चरित्र भी औपनिवेशिक ही होगा।

अगर कहें कि सविधान में सच और झूठ की पहचान अर्थात् है, तो यह फिर बहस का ही सवाल है। आर्थिक-सामाजिक राजनीतिक पाप का दावा तब उसी व्यवस्था में किया जा सकता है, जहां पूजा पर एकाधिकार की कोई गुंजाइश नहीं हो। पूजा पर एकाधिकार का मतलब किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। घराने या वग के अधिकार भी पूजागत एकाधिकार की श्रेणी में ही आते हैं और पूजागत एकाधिपत्य ही अर्थात् राजनीतिक एकाधिपत्य का ढांचा खड़ा करता है। भारतीय सविधान में पूजागत एकाधिपत्य को तोड़ने की तो बात ही छोड़िये, उसे और अधिक सक्रामक बनाने के रास्ते खोजे किये गये हैं।

हमारी मौजूदा राज्य व्यवस्था पूजा और राजनीति के गठजोड़ की उपज है। सविधान इस राष्ट्रघाती गठजोड़ पर कोई सवाल नहीं

उठाता। हमारे सविधानमातृष्ट इस सवाल में कतई गये ही नहीं कि सदियों की विदेशी दासता के शिकवे से बाहर निजले देश में अगर राज्यव्यवस्था आर्थिक तौर पर पूँजीवादी बाजार तथा राजनीतिक तौर पर खानदानी शफाखाने की शक्त में कायम होगी, तो सामाजिक न्याय के आकाश कुसुम आखिर कहाँ से टपका करेंगे मुल्क में ?

जब देश पूँजी और राजनीति के सोदागरी के हवाले हो, तब सविधान की प्रस्तावना में आर्थिक सामाजिक-राजनीतिक धार की पुर्गी बजाने से क्या होगा ? जहाँ पूँजी आदमी की थोक खरीद का साधन और निजाम शोषण पर टिका हो, वहाँ के शोषित उत्पीड़ित जन मन गण की आत्माभिव्यक्ति कौन सो रणत बिखेरेगी ? जहाँ एक ओर भोजन, वस्त्र, दवा तथा शिक्षा के अभाव में विकलांगों की कतारें हो, दूसरी ओर ग्राही अध्यापियों और कौमलांगियों के मध्य पक्षधारा बहुलो, अभयारण्यो तथा नाना द्वीपपूँजी में केलि बिहार करते नैतिक सामाजिक चेतना से शून्य चिसमनगो के हुजूम, वहाँ अवसर की समानता का सहअफूजा किन बोटलों में मिला करेगा ?

आश्चर्य कि हमारे सविधाननिर्माताओं को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जूठन के सविधान रचने के जोश में इतना भी होश नहीं रहा कि अंग्रेजी को जैसे वह ब्रिटिश हुकूमत के दौर में राजभाषा थी, तैसे ही स्वाधीन भारत में भी राजभाषा बनाये रखने से हमारा सारा स्वाधीनता सपना ही मिट्टी में मिस जायेगा। उहे यह भी चेत कतई नहीं रहा कि देश की राजभाषा अंग्रेजी होने से सविधान का यह भूल नकल हो ध्वस्त हो गया कि हम एक सम्प्रभुतासम्पन्न राष्ट्र हैं।

सम्प्रभुतासम्पन्न का एक ही अर्थ हो सकता है—स्वयं के नीति निर्धारण व कार्यकलापों तथा अपने समस्त अंगों में स्वाधीन होना। क्या भाषा देश का अंग नहीं ? भाषा का देश या देश का भाषा से क्या सचमुच कोई सम्बन्ध ही नहीं होता ? अगर होता है, तो जब तक कोई देश भाषा में विदेशी का मोहताज हो, उसे स्वाधीन कहना

सिवा शमनाक सफेद झूठ बोलने के ओर क्या होगा ? जब भाषा में सम्प्रभुता नदारद हो, तब भूगोल या आत्मा में सम्प्रभुता सिवा एक शमनाक घोंसे के ओर क्या होगी ?

जबकि भाषा से ही अस्तित्व तय होता है। भूमि का चप्पा चप्पा भाषा से निबद्ध है। भूगोल-खगोल, सब भाषा से ही तय होते हैं। बोलियों से अवल, प्रादेशिक भाषाओं से प्रदेशों और राष्ट्र भाषा से राष्ट्र के भूगोल खगोल तय होते हैं। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का अस्तित्व असम्भव है। इस प्रकार हम इतना बिलकुल कहना चाहेंगे कि संविधान में का राष्ट्र की अखंडता और एकता का उद्घोष सिवा घोंसे और झूठ के कुछ नहीं, क्योंकि विदेशी भाषा में राष्ट्र की संकल्पना असम्भव है। और कि सिर्फ मूर्ख ही इस सचाई से बेखबर होते हैं कि—जो भाषा में गुलाम हो, वो अपने सबस्व में गुलाम होते हैं।

अंग्रेजी के राजभाषा होने से देश की वास्तविक शक्ल आज भी ब्रिटिश-अमेरिकी उपनिवेश से भिन्न कुछ नहीं। विदेशी भाषा में शासन सिर्फ उपनिवेशों में ही चलाया जा सकता है। लेकिन हम जो अठानव्वे प्रतिशत जड़ मूल हैं, स्वाधीनता की चेतना से पूरी तरह शून्य, हमें आज भी इसी छपावे में मस्त रखा जा रहा है कि बड़ी चीज भाषा नहीं देश है। जैसे कि भाषा नितांत भिन्न वस्तु हो और देश का उससे कोई सम्बन्ध ही नहीं हो, जबकि जैसा कि पहले भी कहा, भाषा और देश अभिन्न हैं।

आत्मी बहबोनापन तो बघारता जाय, लेकिन उसके वस्तुगत सवाल को तरफ मारके भी नहीं, तो इसे सिवा झूठ और पाखण्ड के क्या कहेंगे ? 'भारतीय संविधान' में 'आर्थिक सामाजिक राजनैतिक' माय, अवसर की समानता तथा आत्माभिव्यक्ति एवम् व्यक्ति की गरिमा का संकल्प तो बड़े जोर शोर से किया गया है, लेकिन इसे यथार्थ करने की चिंता गायब है। संविधान में कहीं किसी ऐसी राज्य

व्यवस्था की कोई अवधारणा नहीं की गई है, जो इन बागज के फूलों को जमीन पर खिला मर्के। अगर सविधान सिर्फ कागद की लेखी रे स्तर पर भी खरा होता तो हम इतना विस्कुल मान लेते कि यह जो युग की दुदशा हम देख रहे हैं, इसके पीछे सविधान का क्रिया ब्यन नहीं हो पाना है। तबिन जैसा कि पहले ही कहा, वस्तु का प्रक्रिया मक प्रतिफलन आदमी का हाथ है। जिस वस्तु की निमित्त के पीछे जस चरित्र का नाग हो वंसा हो उस वस्तु का स्वरूप भी बनात है 'भारतीय सविधान' की निमित्त के पीछे जिन लोगों का दिमाग लगा है उ हाने जो कुछ लिखा हाया मे दस्तान बँधजाकर गिया। उ होने प्रभुपता बग के प्राधिकार को ता प्रस्तातीत बनाया तबिन देश के फाटि-कोटि सामा यजना के हाया मे मूल नागरिक अधिकारो का जो झुनझुना पकड़ा दिया। वह उतना ही बजता है, जितना प्रभुकुपा के नामरे मे आता हो

हकी त है यह कि हम अस्तित्व के मामले मे तब उन भारत भाग्य विधाताओ की दया कृपा के मोमताज ही हैं जो जब जारुी समझें माना प्रवार के काल जानून लागू करन की मवप्रभुत्व सम्पन्नता मे लस हैं। उनके इशारे पर इस देश का सर्वोच्च मायमूर्ति तक सबका निलज्ज भाग्य से यह कह सकता है कि—चूकि जीवन राज्य के द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए उस यापस लेन का भी राज्य का पूरा अधिकार है।

मॉन्ट्रेबुस मोलॉड भूतपूर्व चीक जस्टिस थाप इडिया मिस्टर ए० एन० रे जी के द्वारा १९७५ मे आपातकाल के रूप मे सविधान के नाभिबुण्ड मे मे उत्पन्न जिस खूसार भूत का पक्षमयन किया गया। यह आज भी ज्यों का-त्या सविधान मे ही यतभूत है और जब भी हमारे मवप्रभुत्वसम्पन्न मे भविधाताओ की सत्ता मकट मे हागी, इसे १९७५ मे भी ज्यादा बर्बरता के साथ हम पर फिर से छोड़ा जायेगा जरूर।

जो सविधान ढके की चाट पर बताता हो कि जीवन प्रकृति, परमात्मा या समाज की निधि नहीं बल्कि सरकारी जागीर है, उसे विचार अभिव्यक्ति की स्वाधीनता तथा अस्तित्व की प्रतिभूति (गारण्टी) के अधीन, दिव्य अपूर्व मौलिक अधिकारों से अलंकृत दिखाना सिर्फ वही सम्भव हो सकता है जहाँ के लोग सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक वैचारिक स्तर पर भी देशभक्ति की हद तक दीन-हीन और मगबद्ध हों। हम ऐसे ही मगबद्ध हैं। हम मनुष्य जाति का मखौल हैं। हमें इतना भी चेतन नहीं कि किसी भी देश की स्वाधीनता अस्मिता और गरिमा का चेतना में घुँस लोगो से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। यह देश भी अभिशाप है क्योंकि हम चलते फिरते अभिशाप हैं। तत्पावित स्वाधीनता के चार दशकों के बाद भी जो हमारी स्वाधीनता अस्मिता और गरिमा पर जड़ता और दीनता की बखर्कियाँ ही भिनभिना रही है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम ऐसे ही किसी सविधान के योग्य हैं, जिसमें हमारा जीवन तक सबप्रभुत्व-सम्पत्तियों के ठोकर की वस्तु हा।

१९७५ में साफ़ बता दिया गया कि सविधान में 'हम भारत के लोग' में आशय उन सबप्रभुत्वसम्पन्न भाग्यविधाता प्रभुओं मात्र से है जो सविधान को शीतान की बाइबिल के तौर पर इस्तेमाल करने की स्वच्छ हैं। जिन्होंने सविधान में नाना प्रकार के विवेकाधिकारों की प्रशिक्षित के द्वारा कानून को अपनी मुट्ठियों की वस्तु बना रखा है। जो इस पूरे इतमीनान में हैं कि हम सदियों के गुलामों की कभी यह सवाल व्यापेगा ही नहीं कि कानून की सबसे बड़ी किताब सविधान में आखिर विवेकाधिकारों को कानूनों से बड़ा दजा क्यों दिया गया है।

जबकि इतना तो किसी आँखों के अघे की भी समझना जरूर चाहिए कि विवेकाधिकार (यानी विवेक पर कब्जे) का दावा सिर्फ गुणों के द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन हम अबल व अधो

को कहा चेत है कि सविधान मे कानूनी अधिकारो से ऊपर विवेकाधिकारो की व्यवस्था दरअमल गुण्डा कानूनों की द्रष्टि के सिवा कुछ नहीं। और कि इससे सविधान मे की कानून के राज्य की व्यवस्था भूठी पड़ गई है। जहाँ कानून से बड़ी सत्ता विवेक (वास्तव मे स्वच्छाचार) की हो वहाँ कानून नहीं, विवेक का राज्य ही कामम होगा। और विवेक के राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण भारतेन्दु का 'अधेर नगरी चौपट राजा' है, जहाँ कि अपराधी को दण्ड की जगह फाँसी के फंदे के घेरे का नाप की गदन खोजी जाती है।

भारतीय सविधान मे कानून दिसान के दात हैं। राज्य के असली साने के दात हैं — विवेकाधिकार। १९७५ मे देश भर के लोगों के अस्तित्व को इसी विवेकाधिकार से हवा मे टाग लिया गया था।

अगर हम झूठ कह रहे हो, तो सच क्या है, यह बताने की नैतिक सत्ता विधिक जिम्मेदारी उन पर है, जिन्हें सविधान का भाष्य सौंपा गया है। और कि जो पूरे राष्ट्र की गरिमा और स्वाधीनता को विदेशी भाषा के हवाने किये बैठे हैं। और कि जिन्हें इस बात से कोई सराबार नहीं कि भाषा का देश में नाता क्या है। जो देश को उसकी भाषा से वंचित किये रहने मे ही स्वयं की सिद्धि देखते रहे हैं। जो इस सत्य से पूरी तरह बेखबर हैं कि झूठ को सच बनाना असम्भव है।

जैसा कि पहले ही कहा, अभी यह पहले ही पने पर तो इबादत को भगमने की राजिग है। यह किताब बहुत बड़ी है और इतनी ही जरूरी भी। इसे यानी सविधान को, देश के अधिसूख लोगों की चेतना में हाकर ही हमकी आत्मा को जगाया जा सकता है। हमारे सामाजिक जीवन की इस सबसे बड़ी पीछी के प्रति हमारा 'बाला अदार भंग कराकर' के मुद्गारे के हवाने हो रहना ठीक नहीं। जितना ही इस हम जानेगे, उतना ही हमारे काम की किताब सिद्ध होगा।

हमें इतना ध्यान रहना जरूरी होगा कि इस किताब से हम नियति के स्तर पर बैठे हैं। यह सचमुच बहुत बड़ी किताब है। इसके पृष्ठों में हमारे सामाजिक काय कलापो को प्रभावित करने की अपार क्षमता अतनिहित है। इसका पाठ धर्मग्रन्थों के पाठ से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी प्रतिच्छाया हमारे प्रत्येक कम तक जाती और उसे प्रभावित करती है। सविधान की परिभा में ही नागरिक जीवन की परिभा निहित है, इसलिये सविघ्न न के हित में सतत संघर्ष जरूरी है, क्योंकि जो किताब बड़ी हो उसके तकाजे भी बड़े होंगे जरूर।



कठफोड़वा कहीं रहता है ?

नई दिल्ली, १६ अगस्त ८८ । राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरामन ने सकीण और स्वार्थी तत्त्वों को 'कठफोड़वा' की संज्ञा दी है । श्री वेंकटरामन ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्र के नाम अपने मद्रास में कहा—'आज भारतीय लोकतन्त्र के वृक्ष की जड़ें मजबूत हैं और उसका क्षेत्र विशाल है, लेकिन सभी वृक्षों की भांति इस वृक्ष पर भी कठफोड़वा की दृष्टि पड़ी है ।' उन्होंने यह बात उन सकीण और स्वार्थी तत्त्वों के बारे में कही, जो चुनाव प्रक्रिया पर कुठाराघात करना चाहते हैं । श्री वेंकटरामन ने कहा—देश के संसदीय लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने वाले इन तत्त्वों की जितनी भी कठोर शब्दों में निंदा की जाय कम है ।' —मिनक जागरण १७ अगस्त १९८८

जो बोले, वह जानना भी जरूर चाहेंगे कि उनके बिचारों पर मुनन वालों का कहना क्या है । प्रतिक्रिया, मुनने वाले का नमगिक अधिकार है । इसके बिना बात अधूरी है । वाक्' मिनक से घड़ी वस्तु है । हमारे एक पहलू से सोचना और दूसरे से मुनना जुड़ा है । जो मुन, वही बात भी सकता है कि बात कैसी रही !

हमने अपन महामहिम राष्ट्रपति महादय का अभिभाषण बहुत ध्यान से सुना। सुनकर हमारी राय बनी यह कि भाषा बहुत बठिन वस्तु है और कि 'विदेशी बोली' के कुछ स्वाभाविक खतर हैं। शब्द का विवेक नष्ट हो जाना इनमें से एक है। अगर अब हम कहें कि राष्ट्रपति जी के स्वाधीनता की पूर्व संध्या के अभिभाषण में शब्द (या भाषा) का विवेक नदारद है, तो इसे सुरत महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अवज्ञा की घण्टा करार न लिया जाय क्योंकि न सच्चाई आक्षेप हुआ करती है और न जिज्ञासा अवज्ञा। इतना हमें भी पता है कि झूठ या गलत लिखना खुद की फजीहत करना है। हम यहाँ जो कुछ लिख रहे हैं, इस अनुभव और विश्वास में ही कि जो जितना महान उसकी जवाबदारी भी उतनी ही बड़ी है। नागरिक क नात पूछना हमारा हक है और बताना राष्ट्रपतिजी का फज। ज्ञान को बाधा शैतान से होती है, महान से नहीं। जो जितना महान्, वह उतना ही सवालो में घिरा है, क्योंकि हमारे अज्ञान की छाँटने की जिम्मेदारी उस पर ही सबसे ज्यादा है।

जो स्वयं के कहे का अर्थ बतान से इकार करे या मानकर चले कि उसका कहा लोगों के सवाल से ऊपर होगा, उसका ज्ञान सरासर धोखा है। वह नाथो में बाइबिल लिय बैठा शैतान है, क्योंकि मनुष्य का तो गरिमा ही इसमें है कि वह जितने ऊँचे स्थान पर से बोले, उतनी ही उसे शब्द की चेतना भी हो। महान् वह है जिसमें गहरी संवेदना और श्रुति हो। जो सदैव, इतना ध्यान रखकर ही बोलता हो कि लोग मुझे, तो जानना भी जरूर चाहेंगे।

ऊपर की छोटी सी भूमिका के बाद, हम कहना चाहेंगे कि जिस-शब्द का मतलब न आता हो, उसे दूसरों से सोचना ठीक नहीं। न ऐसे किसी शब्द को धारण करना ही बुद्धिमानो है जिसका कि मतलब बताने में पसीना छूटने का खतरा मौजूद हो। दूसरों के द्वारा

दिये गये 'शब्द' का तब तक कोई महत्त्व नहीं, जब तक कि वह हमारे कम या चरित्र से मेल नहीं खाये। विद्वान को मूख कहिये, तो वह कभी नहीं चिह्नकेगा, क्योंकि शब्द का कम या चरित्र से मेल बना नहीं। मूख को मूख कहिये, तो धरती खूँदने लगगा, क्योंकि शब्द चरित्र से समरस है।

हर शब्द की एक हृद है। अनहृद भी शब्द की हृद से बाहर नहीं। हृद से बाहर या ऊपर होना ही शब्द का विवेक खोना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यवहार में रहने पर शब्द रुढ़ हो जाता है, लेकिन विचारवान व्यक्ति की शोभा इसी में है कि शब्द के अर्थ से उदासीन न रहे।

गांधीजी को जब लोगो ने 'राष्ट्रपिता' संबोधन दिया, तो उसकी भी एक हृद थी और उसका दूसरा स्वर था—बापू। शताब्दियों की दासता में जकड़े लोगों के कानों में स्वाधीनता की लाठी की ठक ठक-ठक् पड़ी, तो लोगो को हुआ कि यह पिता की सी आवाज है। लेकिन 'राष्ट्रपति' शब्द से कानों में क्या गजता है? 'पति' के साथ पुत्र का छोर बँधा है। व्यक्ति में 'माँ' से उत्पत्ति का ज्ञान नदारद, तो 'पति' होना खतरनाक हो सकता है। हमारे महामहिम राष्ट्रपतिजी को, शायद, ज्ञान ही नहीं कि 'राष्ट्र' (धरती) माँ है और 'माँ' का पति होना कुत्सित विकृति।

संतुलन और अनुपात, हर वस्तु के अनिवार्य अंग हैं। ये नदारद हों, तो वस्तु को विकृत होते देर नहीं। 'राष्ट्रपिता' शब्द का संतुलन और अनुपात सवारने की 'बापू' मौजूद है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित अवाहरलाल नेहरू का संतुलन बनाने और उन्हें, उनके औपनिवेशिक चरित्र के बावजूद करोड़ों लोगों से जोड़ने में 'बाबा नेहरू' की भूमिका देखना जरूरी होगा। 'राष्ट्रपति' शब्द का दूसरा छोर क्या है? और जिस शब्द का दूसरा छोर नदारद हो, वह एक पहलू के

खोट सिक्के से भी बदतर है क्योंकि एक न एक दिन वह अपने धारक को धारोधार से जरूर डूबता है।

हम इतना बिल्कुल जोर देकर कहना चाहिये कि 'राष्ट्रपति' शब्द गलत है। 'प्रेसीडेंट' का पद 'राज्याध्यक्ष' का है। यही उसकी हद है। यहाँ से आगे 'राष्ट्राध्यक्ष' तक तो हद के इनारे किनारे ही, लेकिन 'राष्ट्रपति' होत ही हद से बाहर हा जाना है क्योंकि राष्ट्र कोई जागीर नहीं। दूसरे, राष्ट्रपिता भावना का शब्द है, जबकि राष्ट्रपति कानून (राज्य) का। कानून के 'शब्द' को 'अर्थ' से समतोल होना चाहिये, क्योंकि कानून का निष्पक्ष तुला है।

जिस देश का क्षेत्र आसितु हिमाचल विस्तृत हो। जिसकी जडा मे गंगा यमुना-नर्मदा कावरी ब्रह्मपुत्र जैम पवनदी का पवित्र जल महासागरो का रूप लेता हो। जिसमे विष्य और हिमाचल अरामली जैसी पवतश्रेणियो का डरा लगा हा। जहा धर्म, उपनिषद, रामायण और महाभारत जस महाकाव्य रचे गये हा, उसका 'पति' होने की भ्राति से बचना ही श्रेयस्कर होगा।

शब्द व्यक्ति के जीवन भर साथ रह, तभी सारा और प्रासंगिक है। भोग ता ऐसे भी हुए है कि शरीर से नहीं रहने पर भी, शब्द में उपस्थित है। 'राष्ट्रपति' शब्द का तो अनेक बार सिर्फ पाँच सात माल भी साथ चलना कठिन हुआ है। क्या हम आशा करें कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामस्वामी बैकटरामनजी शब्द पर थोड़ा ध्यान देने जरूर ?

इतना तो वो कह ही सकते हैं कि यह 'प्रेसीडेंट' का गलत अनुवाद है और चूकि हिं दी से उनका कोई सरोकार ही नहीं, इसलिए शब्दानुवाद के गलत होने को जिम्मेदारी उनकी नहीं। और चूकि उन्होंने मोक्षत्र की दुहाई दी है, इसलिए ध्यान मे रखना जरूरी होगा कि मोक्षत्र भी एक शब्द है और अगर प्रधानमन्त्री को 'लोकाधिपति'

कहा जाने लगे, तो लोकतन्त्र खत्म हो जायेगा ! इसलिए लोकतन्त्र में अधिनायकत्व या स्वामित्वमूलक शब्दों से बचना चाहिए ।

हालाँकि जहाँ तक हमारी ओकात का सवाल है देन को यह तक भी बिल्कुल दिया जा सकता है कि जिन्हें दश को गुलामी व शिकजे में जकड़ने वाले सम्राट् राज पञ्चम को भारत भाग्य विधाता मानत शम नहीं आई । जिन्हें अपने ही नहीं, बल्कि पंजाब, मिथ, गुजरात, महाराष्ट्र द्रविड प्रदेश उत्कल और बंगाल बल्कि विषय हिमाचल यमुना-गंगा और दक्षिणी पश्चिमी महासागर तक के राज पञ्चम का 'शुभ नाम' लेत हुए ही जागन और उही महाप्रतापी सम्राट् का शुभाशीष मागते कोई लज्जा अनुभव नहीं हुई, वही आज 'राष्ट्रपति' शब्द पर बहस क्यों उठाये ? लेकिन आदमी अगाध है और जने महास गरी में ज्वार उठते हैं आदमी में भी लहरें उठती जरूर हैं । बल्कि मचाई तो है यह कि आदमी जितने सन्धे समय तक मेलता है, उसने ही घनघोर शब्द भी उठाता है ।

हम नहीं तो आने वाल ही सही, लेकिन शब्द की बहस तो लाग उठायेगे जरूर, क्योंकि लोकतन्त्र क्या है ? आदमी की चीपाल है । और चीपाल में आदमी हुक्का ही नहीं शब्दों की भी गुडगुठाता है । सब धृष्टिये तो अगर 'शब्द की गुडगुड' निर्बाध नहीं तो साफ है कि लोकतन्त्र सिफ मुखौटे में ही मौजूद है । क्योंकि सिफ मुखौटा ही आदमी को मुखौटे की बातों बोलने का साधार करता है ।

शब्द की मत्ता ही बहस से है । बहस से शब्द धूमिल नहीं होना, निखरता है । शब्द के अभिज्ञान की बहस जरूरी है । अथवा उसका मतलब जानना असम्भव है ।

हमें समझा किया जाय, हमारे वतमान महामहिम राष्ट्रपति श्री रामस्वामी वैजटरमण जी की न कठफोड़वा शब्द का मतलब ही पता है और न 'राष्ट्रपति' का ।

गर्भ प्रसंग से जुड़ा है। कठफोड़वा से अगर राष्ट्रपति जी का वाक्य सरकार की ग्राह पर हजारों हजार वृक्ष एक दिन में कटवा लेने वाले गलतचोर नकली (काठ) के ठेकेदारों से हो, तो हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जाहिर है कि उनका (भी) वाक्य कठफोड़वा पक्षी ने ही है।

हमें लगता है, महामहिम राष्ट्रपति जीने 'कठफोड़वा' (पक्षी) ने, अपने स्वाधीनता की पूर्वसंख्या के अभिभाषण से पहले तक न 'हैं' भाँखों से देखा, न कभी कानों से सुना और न कभी जानने की गरूरत ही अनुभव की कि कठफोड़वा आखिर करता क्या और रहता कहीं है?

शब्द से उसका अर्थ जुड़ा है। गाय क्या खाती पीती और क्या देती है, उसके जीवन के क्षात क्या हैं, इन सारी बातों का कोई ज्ञान न हो, तो तब है कि 'गाय' शब्द का प्रयोग, अनर्थ के सिवा और कुछ नहीं करेगा। कठफोड़वा के खाने पीने, खेलने बूढ़ने, उबने फुदकने और रहने के ठिकानों का ज्ञान जिस हा, वह भूलकर भी यह आरोप कठफोड़वा पर कभी नहीं लगायेगा कि उसकी कुदृष्टि से विशाल क्षेत्र और मजबूत जड़ों वाले वृक्षों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कठफोड़वा बेचारे का तो खुद का अस्तित्व ही वृक्ष के सहो समामत बने रहने पर टिका है।

राष्ट्रपति जी को पता नहीं कि यह न-हा निरीह पक्षी तो वृक्ष की छाँट को उतना ही विदीन करता है, जितने से कि उसे भीतर के कीड़े मकड़ों का आहार जुट जाय। इसीलिए कठफोड़वा सिर्फ मोटे बगवत (बत्तख) वाले वृक्षों पर ही चोंच चलाता है। उसे अगर ध्यान से चोंच चलाते देखिए, तो दूध के सालब में माँ की किम्बोदते निशु की सी चेष्टाएँ करता मासूम पड़ेगा। और अगर वहीं श्रृपियों-कवियों का मा ध्यान लगाकर देखिए, तो जीवन-समर्थ का समीत तानता नजर

आएगा। लम्बी सीसी चोच उठाकर, यह इंगित करता आभासित होगा कि उसे अपनी कुट कुट कोयल की 'कुहू कुहू' से कम प्यारी नहीं। और कि—जीवन का सबसे सुंदर संगीत स्वयं जीवन है।

हम, फिलहाल इतना ही मान लेना चाहेंगे कि हमारे महामहिम राष्ट्रपतिजी ने कठफोडवा देखा ही नहीं है। क्योंकि देखकर भी धनदेला करना और ज्यादा गलत बात है।

हमने जगल देखे ही नहीं, योडा जिये भी हैं। हमने कठफोडवा देखा ही नहीं, उसकी कहानी भी सुनी है। हमें कोई यह कहता नहीं मिला कि कठफोडवा की कुदृष्टि से वृक्षों की खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में इतना हम और कहना चाहेंगे कि राष्ट्रविरोधी तत्त्वों को कठफोडवा की सजा देना मगरमच्छों को 'नहीं' मुनी मछलियाँ बताना है। काश कि राष्ट्रविरोधी तत्त्वों का चरित्र कठफोडवा की भाँति ही नैसर्गिक और स्वयं के अस्तित्व की रक्षा के अर्थ से जुड़ा होता।

जो नैसर्गिक, वह पाप से परे है। उसे जघन्य अपराधकर्मियों में शुमार करना अनीति है। कठफोडवा को दूखहता बताना, उस पर झूठा आरोप लगाना है। यह नैसर्गिकता की हत्या है। राष्ट्र के सर्वोच्च राजनैतिक आसन पर विराजमान व्यक्ति से तो कठफोडवा भी पाप ही पाना चाहेगा। लेकिन 'पाप' भी तो स्वयं में एक शब्द ही है। और जिस शब्द की चेत्तना न हो, उससे न्याय असम्भव है।

राष्ट्ररूपी वृक्ष या सोकतत्र की प्रक्रिया में कठफोडवा लग गये होने की जो चेतावनी राष्ट्रपति जी ने दी है, उससे वहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि राष्ट्र की जड़ों को सम्भावित खतरों में डूबा हिस्सेदारी सयप्रमुखसम्पन्न भारत सरकार की भी है या, नहीं। उन्होंने यह भी नहीं स्पष्ट नहीं किया कि चुनाव प्रक्रिया पर ठूठाराघात करने

वाले तत्व हैं कौन कौन ? और कि आज जो चुनाव पैसे और गुण्डा शक्ति का खेल बनकर रह गये हैं, इसकी जड़ें कहा हैं। न कही अभिभाषण में सरकार को यह निर्देश ही दिया गया कि वह चुनाव-प्रक्रिया को राष्ट्रविरोधी तत्वों के चंगुल से बचाये कैसे।

कितने भी कठोर शब्दों में निंदा करने से उन्हें क्या फक पड़ना है जो कि शब्दों की चेतना से ही ऊपर उठ चुके हों ? जिनके लिए राष्ट्र दूसरों से हिस मिल कर सधर्य करने और मगूल मनाने की जगह नहीं, बल्कि पिछारिया की तरह लूटने खसोटने का अड़ड़ा मात्र हो ?

अफसोस कि पूरे अभिभाषण में राष्ट्र के स्पंदन कही नहीं सुनाई दिये। उसमें राष्ट्र की अस्मिता, स्वस्ति और सवेदना के नाद की जगह सत्ता के 'बैंकप्राउण्ड म्यूजिक' की अनुपूज ज्यादा रही। भाषा, शिक्षा, न्याय, कानून और प्रशासन में किसी सकारात्मक परिवर्तन का दिशा निर्देश अभिभाषण में कही नहीं दिखा। उसमें आर से पार तक स्वाधीनता की पूव सध्या पर भाषण देने की औपचारिकता और सर्वोच्च पद के बधनों की छाया मात्र डोलती दिखाई पड़ी।

सकीर्णता भी शब्द है। जब व्यक्ति का जीवन समाज के करोड़ों लोगों की पहुँच से दूर हो जाय, जब व्यक्ति को सप्तसितारा भव्यताओं के बीच यह ध्यान ही नहीं रहे कि देश में लाखों करोड़ों अन्न वस्त्र और दवा तक की मोहताज हैं—जब कानून और न्याय तक के खरीद फरोख्त की वस्तु हो चुकने की कोई चिंता और वेदना ध्यापनी ही वद हो जाय—तब खुद का बासा राजसी ऐश्वर्य की चमकार से झिझमिलाते विशाल प्रासादों में होने के सतोष में निमग्न पड़े रहना मनुष्य के हक में नहीं क्योंकि 'सकीर्णता' जितनी जगह की नहीं, इससे ज्यादा सवेदना, विवेक और चरित्र की खतरनाक होती है। और तब अगर कहीं कोई अधानक पूछ बैठे कि—मा'मवर, कह तो दिया आपने, लेकिन कुछ बतायेंगे भी कि राष्ट्र को खतरनाक

१६४ / बठफोडवा कहाँ रहता है !

‘बठफोडवा’ हकीकत में कहाँ रहता है ? तो जवाब देना मुश्किल भी हो सकता है ! क्योंकि तब यह जवाब किसी काम का नहीं होगा कि — हम तो भव्य इन्द्र भवनों में विराजते हैं !

• •

शंलेश मटियानी की अन्य रचनायें
कहानी सग्रह
पाप मुक्ति तथा अन्य कहानियाँ
सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ
अतीत तथा अन्य कहानिया
सफर पर जाने से पहले
हारा हुआ
छिद्दा पहलवान वाली गली
वर्ष की चट्टाने / कोहरा
भेडे और गडेरिये
प्रतिनिधि कहानियाँ
अहिंसा तथा अन्य कहानियाँ
विकल्प कथा साहित्य (संपादित)
माँ की वापसी / बिल्ली के बच्चे
उपन्यास
डेरवाले / पुनजन्म के बाद
मुठभेड / आकाश कितना अनंत है
चन्द औरतो का शहर
बावन नदियों का सगम
बोरीवली से बोरीबंदर तक
अर्ध कुम्भ की जात्रा
माया सरोवर / रामकली
आलोचना/लेख
कागज की नाव
राष्ट्रभाषा का सवाल
लेखक की हैसियत से
यदा कदा / त्रिज्या
मुख्यधारा का सवाल
जनता और साहित्य
लेखक और संवेदना